सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
2013 की सं. 19

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
2013 की सं. 19

विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		*v*
विहंगावलोकन		*vii*
अध्याय I : प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.2	2
लेखापरीक्षा नियोजन तथा संचालन	1.3	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.4	3
अध्याय II : कृषि मंत्रालय		
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग		
दि.दु.यो. में वित्तीय अनुशासनहीनता	2.1	5
लाइसेंस शुल्क की कम वसूली	2.2	10
निधियों का समयपूर्व जारी करना	2.3	11
अध्याय III : नागरिक उड्डयन मंत्रालय		
या.से.शु. (एस.सी.) निधि एसक्रो खाते में से अमान्य व्यय	3.1	14
अध्याय IV : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय		
पेट्रोलियम एवं विस्फोट सुरक्षा संगठन, नागपुर	4.1	16
अध्याय V : विदेश मंत्रालय		
सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ	5.1	18
अध्याय VI : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
परियोजना उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि	6.1	20
प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	6.2	26
के.स.स्वा.यो. के एलोपैथिक दवाईयों का प्रापण	6.3	33
क्षयरोधी दवाओं के कालातीत होने के कारण हानि	6.4	46
अध्याय VII : गृह मंत्रालय		
सशस्त्र सीमा बल		
आवासीय परिसरों के निर्माण में अत्यधिक खर्च	7.1	50
सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब)		
अनियमित प्रापण	7.2	52

अध्याय VIII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
आकाश टेबलेट परियोजना में कमियां	8.1	55
अनुदान का अनियमित निर्गम	8.2	60
अध्याय IX : खनन मंत्रालय		
रॉक ड्रिलिंग रिग के उपयोग न होने के कारण हुआ निष्फल व्यय	9.1	62
अध्याय X : भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय		
भारतीय समुदाय कल्याण योजना के लिए आत्मनिर्भर समग्र निधि का सृजन न किया जाना	10.1	64
अध्याय XI : पोतपरिवहन मंत्रालय		
सुनामी से अब तक अं.सा.स्थि.नि.प्र.की पुनः स्थापना न करना तथा ₹75.14 लाख का निष्फल व्यय	11.1	66
अध्याय XII : कपड़ा मंत्रालय		
निर्मित फ्लैटों के क्रय में अत्यधिक बिलंब के परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध हुई	12.1	69
अध्याय XIII : पर्यटन मंत्रालय		
विज्ञापन अभिकरण को अभिकरण सेवा शुल्क का अनियमित भुगतान	13.1	72
अध्याय XIV : संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन		
अण्डमान लोक निर्माण विभाग		
निष्फल व्यय	14.1	75
पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय		
निष्फल व्यय	14.2	76
क्षति सुधार कार्य एवं मरम्मत की लागत सहित ₹ 3.73 करोड़ के जुर्माने की गैर-वसूली	14.3	79
जुर्माने की गैर-वसूली	14.4	80
मैनिंग एजेन्ट को किया गया अधिक भुगतान	14.5	82
ठेकेदारों को ₹ 58.43 लाख के अनियमित भुगतान	14.6	83
लक्षद्वीप प्रशासन		
लैंडिंग नौकाओं के प्रापण में निष्फलता के परिणामस्वरूप ₹12.21 करोड़ का अपव्यय	14.7	85
रडार ट्रांसपोंडरों को संस्थापित न किया जाना	14.8	88

सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ प्रशासन		
राजस्व हानि	14.9	90
सरकारी धन का दुर्विनियोजन	14.10	92
चण्डीगढ़ प्रशासन-पुलिस विभाग		
पुलिस बल की तैनाती हेतु प्रभारों की वसूली न होना	14.11	93
चण्डीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़		
निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु एकत्रित ₹28.04 करोड़ के उपकर का उपयोग नहीं होने के कारण लक्ष्य की उपलब्धि न होना	14.12	94
अध्याय XV : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		
राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु कार्यालय भवन के निर्माण में असामान्य विलंब	15.1	98
अध्याय XVI : युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय		
अनुदानों की अप्रभावी मॉनीटरिंग	16.1	101
अध्याय XVII : सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	17.1	104
ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर	17.2	106

	अनुबंध	
1	लाइसेंस फीस की कम वसूली	107
2	एच.वी.ए.सी. एवं बी.एम.एस. कार्य हेतु अदा की गई राशि में वृद्धि के विवरण	108
3	सलाहकारों के पास रखी गयी निधियों की स्थिति	109
4	वर्ष 2011-12 के लिए बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं में फॉर्मूला एवं कम मूल्य विकल्पों के आधार पर कीमतों की तुलना	110
5	के.स.स्वा.यो. दिल्ली में दवा की उपलब्धता पर व्यय	114
6	ब्रांडेड एवं जेनरिक दवा फॉर्मूला में समान दवाओं की सूची	115
7	जेनरिक फॉर्मूला एवं ब्रांडेड फॉर्मूला दोनों/पायलट परियोजना में सूचीबद्ध दवाओं के कीमतों की तुलना	119
8	एच.एस.सी.सी. द्वारा दवाओं की उपलब्धता में देरी	121
9	फार्मूला में सूचीबद्ध दवाएं जो स्थानीय औषधि विक्रेताओं से उच्च दर पर खरीदी गई, के कारण 2010-11 और 2011-12 के दौरान हुई हानि	122

10	के.स्वा.से.यो. के जीवन रक्षक दवाईयों की सूची में समान दवाओं के विभिन्न ब्रांडो के दरों की तुलना	127
11	लागत वृद्धि का विवरण	130
12	भारतीय समुदाय कल्याण योजना के अंतर्गत निधि का उपयोग	131
13	वातानुकूलित बसों के गैर/स्थानीय परिचालन के कारण राजस्व की हानि	133
14	खजाने में वाहन के पंजीकरण शुल्क/ड्राइवर लाइसेंस शुल्क को जमा न करना	135
15	आंशिक रूप से जमा किया गया वाहन पंजीकरण शुल्क	137
16	बकाया परिनियोजन प्रभारों का विवरण	138
	परिशिष्ट	
I	मार्च 2013 को, मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तक विभिन्न मंत्रालय/विभागों से प्रतिक्षित कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	139
II	ड्राफ्ट पैराग्राफ के संदर्भ में मंत्रालयों/विभागों का उत्तर	142

प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में सिविल मंत्रालयों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उद्घटित हुए निष्कर्ष निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वह हैं जो 2011-12 की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे। तथापि, पूर्व वर्ष से संबंधित मामले जिन्हें पिछले प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया जा सका था तथा 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, भी सम्मिलित किये गये हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सिविल मंत्रालयों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निहित है। इसमें 17 अध्याय है। अध्याय I एक संक्षिप्त परिचय देता है जबकि अध्याय II से XVI में विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ प्रस्तुत की गयी है। अध्याय XVII मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्रवाई टिप्पणी की सारांशीकृत स्थिति प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये है।

कृषि मंत्रालय

पशु पालन, दुग्ध उत्पादन तथा मत्स्य पालन विभाग

दि.दु.यों में वित्तीय अनुशासनहीनता

दिल्ली दुग्ध योजना कृषि मंत्रालय के एक उपक्रम में, मार्च 2012 तक ₹ 838.67 करोड़ की राशि की संचित हानि हुई थी। लेखापरीक्षा ने इसके वित्तीय प्रबंधन में अनेक कमियां पायी। दि.दु.यो. में अपनायी गयी रोकड़ प्रबंधन प्रणाली लागत प्रभावी नहीं थी। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदत्त अग्रिमों के संवितरण तथा समायोजन में भारी उल्लंघन पाए गये थे। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि 2009-12 अवधि के दौरान दि.दु.यो. में व्यय लगभग 87 *प्रतिशत* से 90 *प्रतिशत* निजी जमा खाते में से किया गया था जिसका अर्थ है कि भु.ले.का. प्रणाली द्वारा निश्चित किए गए आवश्यक नियंत्रणों को नजरअंदाज किया गया था।

पैराग्राफ 2.1

निधियों का समय-पूर्व जारी करना

मंत्रालय ने रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. को "कटड़ों के संरक्षण तथा पालन" योजना के अंतर्गत एक अधूरे प्रस्ताव के आधार पर तथा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.92 करोड़ की राशि जारी की। फलस्वरूप रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने के कारण निधियों का नौ माह से अधिक तक अवरोधन हुआ।

पैराग्राफ 2.3

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

जी.एम.आर. हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड का या.से.शु. (एस.सी.) एसक्रो खाता

या.से.शु. (एस.सी.) निधि एसक्रो खाते से अमान्य व्यय

जी.है.अं.ह.अ.लि. ने या.से.शु. (एस.सी.) निधि एसक्रो खाते से ₹ 100.40 करोड़ का अस्वीकार्य व्यय किया था।

पैराग्राफ 3.1

विदेश मंत्रालय

सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ

मंत्रालय द्वारा सम्पत्ति कर में वृद्धि के आधार पर सेवा प्रभार प्रति वीजा आवेदन वर्तमान दर से 12 *प्रतिशत* बढ़ाने की अनुमति के परिणामस्वरूप सेवा प्रदाता को अक्तूबर 2011 से दिसम्बर 2012 तक ₹ 3.45 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

पैराग्राफ 5.1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको)

नाको द्वारा क.वे.म. योजना खराब नियोजन तथा कार्यान्वयन को प्रदर्शित करती थी। मंत्रालय ने इस पर कोई विस्तृत व्यवहारिक अध्ययन नहीं किया। किसी वैध प्रलेखन अनुबंध के अभाव में, क.वें.म. की सुरक्षा एवं अनुरक्षण से संबंधित मामलों का संज्ञान नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप परियोजना को नाको द्वारा बंद कर दिया गया था।

क.वें.म. द्वारा कंडोमों की बिक्री नाको के अनुमान की तुलना में बहुत कम थी। क.वें.म. के माध्यम से उच्च जोखिम क्षेत्रों में कंडोमों की सुलभता बढ़ाने के अभिप्रेत उद्देश्य, योजना के अंतर्गत ₹ 21.54 करोड़ के निवेश के बावजूद प्राप्त नहीं किया जा सका था। मंत्रालय द्वारा पहले से स्थापित कं.वे.म. की स्थिति की जानकारी लिए बिना चरण II के लिए जल्दबाजी में निधियों को जारी करना अनुचित था।

पैराग्राफ 6.1

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

सरकार द्वारा प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (प्र.म.स्वा.सु.यो.) की घोषणा (अगस्त 2003) सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों को सुधारने तथा देश में गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा हेतु सुविधाओं में संवर्धन के उद्देश्य से की गयी थी। आगामी तीन वर्षों में, पिछड़े राज्यों में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उपलब्ध सुविधाओं के जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त छः अस्पतालों की स्थापना प्रस्तावित की गयी थी।

छः एम्स जैसे संस्थानों के निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए सलाहकारों तथा ठेकेदारों के चयन एवं किये गये भुगतान की प्रक्रिया की लेखापरीक्षा की गयी थी। लेखापरीक्षा ने परियोजना सलाहकारों के चयन तथा सलाहकारों एवं ठेकेदारों की भुगतान प्रक्रियाओं में कमियां पायी थीं। लामबन्द अग्रिमों के अनियमित निर्गम के मामले भी देखे गये थे।

पैराग्राफ 6.2

के.स.स्वा.से. में एलोपैथी औषधियों की अधिप्राप्ति

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिप्राप्त औषधियों में से 71 *प्रतिशत* फार्मूलरी से बाहर की थी इस तथ्य के बावजूद कि फार्मूलरी में औषधियों का मूल्य तुलनात्मक रूप से कम है। के.स.स्वा.से. ने (कम मूल्य ब्राडों की उपलब्धता के बावजूद अधिक मूल्य ब्रांडों की अधिप्राप्ति का सहारा लिया था।

संसदीय समिति की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद सामान्य औषधियों पर ब्रांडेड दवाओं को प्राथमिकता दी जा रही थी। इसने खजाने पर उल्लेखनीय अतिरिक्त वित्तीय भार डाला। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित मुद्रा मूल्य केवल नमूना परीक्षित मामलों से संबंधित है जो वास्तविक अधिप्राप्ति का केवल एक छोटा *प्रतिशत* है। इसलिए, यदि संपूर्ण अधिप्राप्ति को सम्मिलित किया जाए तो ऐसे अनियमित गतिविधियों का मौद्रिक प्रभाव और अधिक होगा।

पैराग्राफ 6.3

क्षयरोधी दवाओं के कालातीत के कारण हानि

मंत्रालय के केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग द्वारा क्षयरोधी दवाईयों के प्रापण में अनुचित योजना के परिणामस्वरूप ₹ 5.06 करोड़ मूल्य की दवाईयों के कालातीत होने के कारण हानि हुई।

पैराग्राफ 6.4

गृह मंत्रालय

सशस्त्र सीमा बल

आवासीय क्वार्टरों के निर्माण पर अधिक व्यय

सशस्त्र सीमा बल ने आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्राधिकरण प्रतिमानों के अनुमोदन के पश्चात एक समयबद्ध प्रणाली से कदम नहीं उठाये। यह 108 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण पर ₹ 5.19 करोड़ के कीमत वृद्धि का कारण बना।

पैराग्राफ 7.1

सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.)

अनियमित अधिप्राप्ति

सी.सु.ब. की फील्ड दूरसंचार केबल के प्रापण के समय निर्धारित प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 1.45 करोड़ की हानि हुई।

पैराग्राफ 7.2

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्च शिक्षा विभाग

आकाश टेबलेट परियोजना में कमियां

मंत्रालय ने उनकी कार्य प्रचालन क्षमता को निश्चित किए बिना भा.प्रौ.सं. राजस्थान (भा.प्रौ.सं.रा.) द्वारा एल.सी.ए.डी.-आकाश को लॉंच किया। फलस्वरूप परियोजना भा.प्रौ.सं. बॉम्बे को सौंपी गई। इस प्रकार भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा परियोजना पर किया गया ₹1.05 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त परियोजना को पूरा करने पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

पैराग्राफ 8.1

विद्यालयी शिक्षा तथा साक्षरता विभाग

अनुदान का अनियमित रूप से जारी करना

मंत्रालय ने मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने 372 मदरसों के लिए, योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित योग्यता शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये बिना वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार जम्मू व कश्मीर को ₹8.86 करोड़ की अनुदान राशि अनियमित रूप से जारी की गई।

पैराग्राफ 8.2

भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय

भारतीय समुदाय कल्याण योजना के लिए आत्मनिर्णय समग्र निधि का सृजन न किया जाना

भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय समुदाय कल्याण योजना हेतु संचित किए गए ₹23.95 करोड़ की आत्मनिर्णय समग्रनिधि का सृजन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.00 करोड़ राशि के ब्याज की हानि हुई।

पैराग्राफ 10.1

पोत परिवहन मंत्रालय

प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत निदेशालय

सुनामी के बाद से अं.सा.स्थि.नि.प्र. की पुनः स्थापना न होना तथा ₹ 75.14 लाख का निष्फल व्यय

विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण सुनामी आने के आठ वर्ष के पश्चात भी आवश्यक मार्ग निर्देशन सहायताएं पुनः स्थापित नहीं की जा सकी थीं जो आगे दिसंबर 2006 में उपकरणों की खरीद पर ₹ 75.14 लाख, जिसे अभी भी स्थापित नहीं किया गया है के निष्फल व्यय का कारण बना।

पैराग्राफ 11.1

कपड़ा मंत्रालय

तैयार निर्मित फ्लेटों की खरीद में अत्यधिक विलंब के फलस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ

गुवाहाटी में आवासीय फ्लैटों के निर्माण में विलंब परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ की ब्याज हानि एवं लागत में वृद्धि के अलावा सात वर्षों से अधिक समय के लिए ₹ 2.38 करोड़ का अवरोधन हुआ।

पैराग्राफ 12.1

पर्यटन मंत्रालय

विज्ञापन एजेंसियों को संचालन शुल्क का अनियमित भुगतान

फ्रैंकफर्ट, पेरिस, एम्सटर्डम तथा मिलान में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों ने विज्ञापन एजेंसियों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के विपरीत प्रावधानों वाले एक कार्यकारी अनुबंध के आधार पर एजेंसी संचालन शुल्क का भुगतान किया था इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2009 से मई 2012 तक अवधि के दौरान ₹ 88.67 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 13.1

संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

अण्डमान लोक निर्माण विभाग

निष्फल व्यय

अण्डमान लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण कार्य के आरंभ से पूर्व तटीय विनियमन क्षेत्र प्राप्त करने की चूक तथा अपर्याप्त डिजाइन के परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा दो बांध के निर्माण पर ₹ 0.31 करोड़ का अतिरिक्त देयता हुई।

पैराग्राफ 14.1

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय

सुरक्षा मुद्दों एवं लागू होने वाले अधिनियमों के साथ-साथ पो.प.मं., भा.स. और म.नि.पो.प. के अनुदेशों की उपेक्षा करते हुए, प.पो.से.नि. ने दो जहाजों के इंजनों के दोषपूर्ण डिज़ाइन अनुमोदित कर दिए जिसके कारण तीन वर्षों से अधिक के लिए जनता को उनकी सेवाओं से वंचित रखने के अलावा ₹ 16.35 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

पैराग्राफ 14.2

₹3.73 करोड़ के जुर्माने के साथ क्षति हेतु मरम्मत एवं पुनः सुधार की कीमत की वसूली न होना

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय के जहाज की क्षति के प्रति मरम्मत की लागत के साथ ₹ 3.73 करोड़ को जुर्माना लगाने में निष्क्रियता के कारण श्रम नियोजन एजेंटों से वसूल नहीं हुआ था।

पैराग्राफ 14.3

जुर्माना की गैर-वसूली

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय की जुर्माना लगाने में निष्क्रियता के कारण द्वीपों के मध्य समुचित संयोजकता उपलब्ध नहीं कराये जा पाने के अलावा भारतीय पोत परिवहन निगम से आम जनता के लिए ₹ 2.18 करोड़ की राशि वसूल नहीं हुई।

पैराग्राफ 14.4

श्रम नियोजन एजेंट को किया गया अधिक भुगतान

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय अनुबंध के अनुसार पूर्व सक्षम अधिकारियों तथा कम योग्यता वाले अधिकारियों के मध्य अवकल-परिश्रमिकों की वसूली करने में असफल रहा, परिणाममतः ₹ 78.96 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 14.5

ठेकेदारों को ₹ 58.43 लाख का अनियमित भुगतान

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय ने खाद्य सामग्री के लिए ठेकेदारों को ₹ 58.43 लाख का अनियमित भुगतान किया, जिसकी वास्तव में आपूर्ति नहीं की गई थी।

पैराग्राफ 14.6

लक्षद्वीप प्रशासन

लैंडिंग नौकाओं के प्रापण में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 12.21 करोड़ के निष्फल व्यय हुआ

सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन की अनुबंध की धाराओं के अनुसार बैंक प्रतिभूतियों की समय पर नवीकरण में विफलता के परिणामस्वरूप, अपूर्तिदाताओं से ₹ 12.21 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हो सकी।

पैराग्राफ 14.7

रॉडार ट्रांसपोडरों को संस्थापित न किया जाना

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) से बेतार परिचालन लाइसेंस (बे.प.ला.) प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप रॉयल्टी/स्पेक्ट्रम प्रभारों के प्रति ₹ 1.17 करोड़ व्यय के बावजूद ₹ 1.52 करोड़ मूल्य के रॉडार ट्रांसपोडरों के संस्थापित नहीं किया जा सका।

पैराग्राफ 14.8

सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ प्रशासन

सरकारी धन का दुर्विनियोजन

सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ के पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रोकड़ काउंटर से प्राप्त धन को खजाने में प्रेषण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 25.68 लाख के सरकारी धन को दुर्विनियोजन हुआ।

पैराग्राफ 14.10

2013 का प्रतिवेदन सं. 19

चण्डीगढ़ प्रशासन-पुलिस विभाग

पुलिस बल की तैनाती हेतु प्रभारों की वसूली न होना

पंजाब क्रिकेट संघ (पं.क्र.सं.) तथा किंग्स XI, पंजाब को पुलिस बल प्रदान करने में नियमों की अनुपालन न करने के फलस्वरूप सं.शा.क्षे. प्रशासन, चण्डीगढ़ द्वारा ₹ 8.92 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

पैराग्राफ 14.11

चण्डीगढ़ भवन तथा अन्य निर्माण कार्य कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़

निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एकत्रित ₹ 28.04 करोड़ के उपकर का उपयोग न होने के कारण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभार्थ कल्याणकारी योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारण, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों एवं अन्य से एकत्रित ₹ 28.04 करोड़ के उपकर अप्रयुक्त रहे।

पैराग्राफ 14.12

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु कार्यालय भवन के निर्माण में असामान्य विलम्ब

राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु कार्यालय भवन 2001 में भूमि अधिग्रहित होने के बावजूद भी बनाया नहीं जा सका था। विलंब का कारण मुख्यतः दोषपूर्ण नियोजन था। परिणामस्वरूप, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्माण गतिविधियों के लिए जारी ₹ 1.47 करोड़ की राशि मार्च 2004 से अवरूद्ध पड़ी हुई थी। काफी समय एवं अधिक व्यय के बावजूद, परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में ही थी।

पैराग्राफ 15.1

युवा एवं खेल मंत्रालय

अनुदानों की अप्रभावी मॉनीटरिंग

मंत्रालय राष्ट्रमंडल खेल - 2010 से संबंधित अनुदानों के निर्गम को प्रभावी रूप से मॉनीटरिंग करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, ₹ 191.22 करोड़ की निधियां 17 से लेकर 26 महीनों की अवधि तक भा.खे.प्रा. के पास पड़ी रही। इसने अनुदानों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली संस्वीकृतियों के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय भा.खे.प्रा. को अनुवर्ती अनुदान देने के पूर्व ₹ 22.12 करोड़ राशि के अव्ययित अनुदानों पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखने में विफल रहा था।

पैराग्राफ 16.1

अध्याय I : प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने कि क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों, लागू नियमों, नियमावली, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, का उल्लेख करती है। अनुपालना लेखापरीक्षा ने नियमों, विनियमों, आदेशों तथा अनुदेशों की वेद्यता, पर्याप्त, पारदर्शिता, औचित्यता तथा विवेक की जांच करना भी शामिल होता है।

लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.) की ओर से उसके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानक[1] के अनुसार की जाती है। इन मानकों में वे मानदण्ड निर्धारित हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा संचालन करने में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और उन्हें अपालन तथा अपशब्द के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में विद्यमान कमियों की सूचना देना अपेक्षित होता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से, कार्यकारी अधिकारी को शोधक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने तथा नीतियों और निर्देश, जो संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन का मार्गदर्शन करेंगे, भी बनाने की अपेक्षा की जाती है, इस प्रकार, ये बेहतर शासन के लिए योगदान दे रहे है।

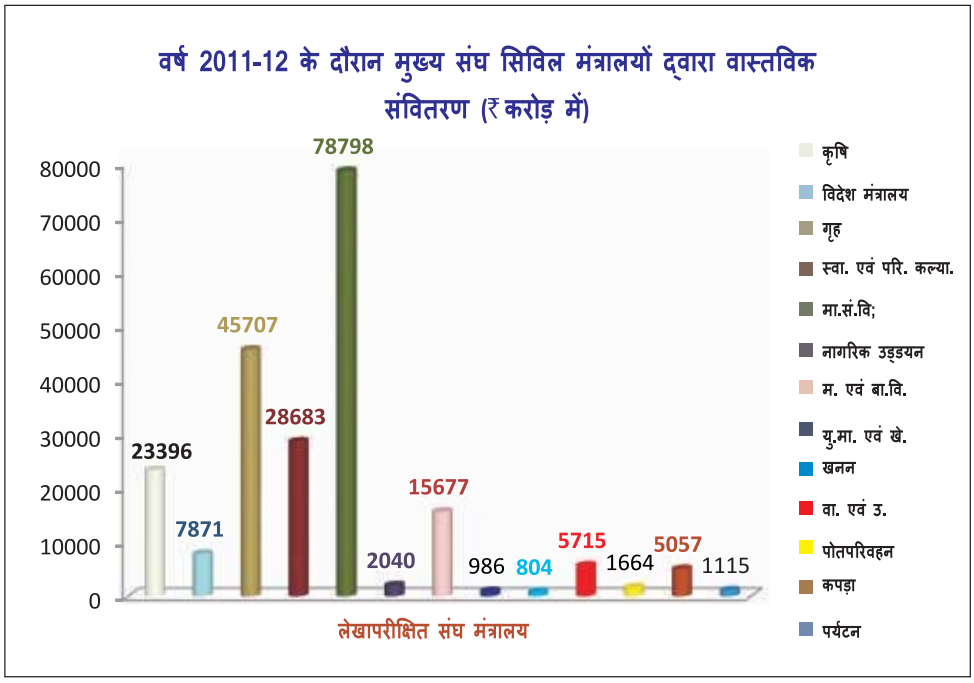
डाक एवं दूरसंचार, रेलवे तथा रक्षा मंत्रालयों को छोडकर संघ सरकार के लगभग 50 मंत्रालय/स्वतंत्र विभाग हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के इन 50 मंत्रालयों तथा विभागों का सकल व्यय नीचे दिया गया हैं।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय
2009-10	₹ 41,17,712
2010-11	₹ 40,23,332
2011-12	₹ 47,62,240

[1] www.cag.gov.in/html/auditing_standard.htm

निम्न चार्ट वर्ष 2011-12 के दौरान मुख्य संघ सिविल मंत्रालयों के वास्तविक संवितरणों को दर्शाता है:



इस प्रतिवेदन में, 15 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम विभिन्न अध्यायों में शामिल किए जाते हौ।

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

नि.म.ले. द्वारा लेखापरीक्षा करना तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 तथा 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। नि.म.ले, नि.व.म.ले. के (क.श.से.श.) अधिनियम[2] की धारा 13[3] तथा 17[4] के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय को लेखापरीक्षा करता है। अनुपालना लेखापरीक्षा हेतु सिद्धान्त तथा कार्यविधियां भारत के नियत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 में निर्धारित की गई हैं।

[2] नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971।

[3] (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, से संबंधित लेनदेनों,
(iii) सभी व्यापक, विर्निर्माण, लाभ एवं हानि

[4] संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार तथा स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा रिपोर्ट

1.3 लेखापरीक्षा नियोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, सम्पूर्ण मंत्रालय/विभाग और उनके विभिन्न यूनिटों में किए गए व्यय, उनकी गतिविधियों की आलोचनात्मकता तथा जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्वतः उनके सम्पूर्ण आंतरिक नियंत्रणों तथा पणधारियों की दिलचस्पी के आधार पर जोखिम के निर्धारण से आरंभ होती है। इस प्रक्रिया में पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा का निर्णय किया जाता है। ऐसे जोखिम निर्धारणों के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

इकाईयों की लेखापरीक्षा समाप्त होने के पश्चात लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित निरीक्षण प्रतिवेदन इकाईयों के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं। इकाईयों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर इन निष्कर्षों के उत्तर भिजवाने का अनुरोध किया जाता है। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं, तो या तो लेखापरीक्षा निष्कषों का निपटान किया जाता है या अनुपालन हेतु उपयोग की कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दिए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

1.4 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

संघ सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय की एक महत्वपूर्ण राशि खर्च करती है। 2011-12 के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (इसके विभिन्न विभागों सहित) द्वारा किये गये कुल व्यय की राशि ₹28683 करोड़ थी। इस प्रतिवेदन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित तीन थीम आधारित लेखापरीक्षा सम्मिलित हैः

- प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति न होना- नैको ने उच्च जोखिम क्षेत्रों में कडोमों की सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कं.वें.म. योजना लागू की थी। योजना में समुचित नियोजन का अभाव था और इसके कारण योजना पर किया गया। ₹21.54 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया। तदपरांत, नैको द्वारा योजना को बंद कर दिया गया।

- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य योजना ने देश में छः एम्स सदृश संस्थाओं की स्थापना का प्रस्ताव किया था। सलाहकारों के चयन की प्रक्रिया और किये गए भुगतान में कमियों उद्घटित हुई लेखापरीक्षा ने ठेकेदारों को संचालन अग्रिमों के अनियमित निर्गम के मामले भी देखे थे।

एलौपैथिक औषधियों की अधिप्राप्ति के.स.स्वा.यो. में ऐलोपैथिक की अधिप्राप्त की प्रक्रिया की लेखापरीक्षा जाँच में बड़ी कमियाँ उद्घटित हुई थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि औषधियों की अधिप्राप्ति से संबंधित क्रिया-विधि में मितव्यता को ध्यान में नहीं रखा गया था जिसने राजकोष पर उल्लेखनीय वित्तीय भार बढ़ाया।

अध्याय II : कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग

दिल्ली दुग्ध योजना

2.1 दि.दु.यो. में वित्तीय अनुशासनहीनता

दिल्ली दुग्ध योजना कृषि मंत्रालय के एक उपक्रम में, मार्च 2012 तक कुल ₹ 838.67 करोड़ की हानि हुई थी। लेखापरीक्षा ने इसके वित्तीय प्रबंधन में कई कमियां पायीं। दि.दु.यो. में अपनाई गई रोकड़ प्रबंधन प्रणाली लागत प्रभावी नहीं थी। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किए गए अग्रिमों के संवितरण तथा समायोजन में भारी उल्लंघन पाए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि 2009-12 के दौरान दि.दु.यो में लगभग 87 *प्रतिशत* से 90 *प्रतिशत* व्यय निजी जमा खाते में से किया गया था जिसका मतलब है कि भु.ले.का. प्रणाली द्वारा सुनिश्चित की गई आवश्यक जांचों को अनदेखा किया गया था।

दिल्ली दुग्ध योजना (दि.दु.यो.) पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसकी स्थापना 1959 में दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्य पर पौष्टिक दूध की आपूर्ति करने के साथ-साथ दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। अधिदेश के अंतर्गत इसे 'न लाभ न हानि' आधार पर कार्य करना था।

कृषि मंत्रालय दि.दु.यो. को इसके संचालन हेतु बजटीय सहायता प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.दु.यो. ने 31 मार्च 2012 तक लगभग ₹ 838.67 करोड़ की हानियां की थी।

लेखापरीक्षा ने संगठन में खराब वित्तीय प्रबंधन के उदाहरण पाए (अक्तूबर 2012) जिनकी अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

1. दि.दु.यो. में रोकड़ प्रबंधन

निष्फल व्यय

केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ विभागीयकृत लेखांकन प्रणाली में सिविल लेखा नियम पुस्तिका के अनुसार, प्राधिकृत बैंक को सरकारी लेन-देनों का संचालन करने हेतु पूर्णतः

प्रतिपूर्ति की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी सरकारी विभागों[1] के रोकड़ अनुरक्षण कार्यों को पूरा करने हेतु बदले में बैंकों को कमीशन प्रदान करता है।

भारतीय स्टेट बैंक दि.दु.यो के सभी बैंकिंग कार्यों हेतु प्राधिकृत बैंक है। भा.स्टे.बैं. पूरे रा.रा.क्षे. में फैली अपनी शाखाओं के माध्यम से दैनिक आधार पर रोकड़ संचालन के व्यवसाय में शामिल विभिन्न संगठनों को रोकड़ इकट्ठा करने की सुविधा प्रदान करता है। भा.स्टे.बैं. की रोकड़ इकट्ठा करने की सुविधा न केवल रोकड़ संग्रहण हेतु श्रमशक्ति परिनियोजन को कम करती है बल्कि रोकड़ संग्रहण तथा प्रेषण को वास्तविक समय आधार पर अनुमत भी करती है। दूसरी ओर, भा.स्टे.बैं. दि.दु.यो. के वितरकों[2] द्वारा रोकड़ को सीधे जमा करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.दु.यो. में दि.दु.यो. बूथों से रोकड़ दैनिक आधार पर ट्रांसपोर्टर्स ठेकेदारों के स्टाफ द्वारा एकत्रित किया जा रहा था जिसे आगे मार्ग-वार फील्ड रोकड़ियों द्वारा एकत्रित करके दि.दु.यो. के रोकड़ प्राप्ति अनुभाग में जमा किया गया था। रोकड़ काउंटर लिपिकों द्वारा अनुभाग में एकत्रित रोकड़ का चालानों से मिलान किया जाता था तथा दि.दु.यो. के बैंक खाते में जमा किया जाता था। यह कार्य चार सहायक दुग्ध संवितरण अधिकारियों, दो रोकड़ काउंटर लिपिकों, छः चालक सह विक्रेताओं, एक नि.श्रे.लि. तथा एक साथी द्वारा किया जाता था।

दि.दु.यो. में रोकड़ का संचालन कर रहे 14 अधिकारियों के वार्षिक वेतन एवं भत्तों पर किए गए व्यय को लगभग ₹60.41 लाख पर परिकलित किया गया।

दि.दु.यो. में मौजूदा प्रणाली प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली को सुनिश्चित नहीं करती क्योंकि पूर्ण रोकड़ संग्रहण को प्रतिदिन बैंक में प्रेषित नहीं किया जाता था।

इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 के महीने के रोकड़ संग्रहण तथा प्रेषण के विश्लेषण ने निम्नलिखित उजागर किया:

- दैनिक आधार पर एकत्रित तथा बैंक को प्रेषित औसतन रोकड़ को ₹ 80.34 लाख परिकलित किया गया। इस प्रकार दैनिक आधार पर संचालित रोकड़ काफी अधिक था। इस प्रमात्रा के रोकड़ का निजी संचालन चोरी तथा हानि के जोखिम से युक्त है। दि.दु.यों को भा.स्टे.बैं. द्वारा प्रदान सुविधा का लाभ उठाना चाहिए था।

---

[1] भा.रि.बैं. द्वारा जारी निर्देश-ज्ञापन का पैरा 26

[2] उन वितरकों पर लागू नकद संग्रह प्रणाली जहाँ दैनिक नकदी सीधे बैंक में जमा की जाती है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि दि.दु.यो. ने यह मामला भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष उठाया था जोकि दि.दु.यो. कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए सरकारी रसीद चालानों के आधार पर ट्रांसपोर्टरों से सीधे किए गए जमा को स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ था। यह प्रणाली जुलाई 2013 से कार्यान्वित की गई थी तथा इसके परिणामस्वरूप दि.दु.यो. कर्मचारियों द्वारा रोकड़ संचालन के परिमाण में लगभग 70 *प्रतिशत* तक की कटौती हुई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि दि.दु.यो. में रोकड़ प्रबंधन प्रणाली को आगे सुधारा गया था।

2. विभागीय अग्रिमों के आहरण में अनियमितताएं

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली प्रावधान करती है कि अस्थायी अग्रिम या तो सीधे संबंधित पार्टियों को किए जाएं या फिर विभागीय अधिकारियों द्वारा आहरित किए जाएं जो पार्टियों को संवितरित करने हेतु संक्षिप्त बिलों में एक मुश्त ऐसे अग्रिमों के विस्तृत लेखे अनुरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों को अग्रिम प्रदान करते समय निम्नलिखित सुरक्षा निर्धारित की गई है:

1) इन अग्रिमों को संवितरित कर रहे किसी भी अधिकारी द्वारा लिए गये पूर्व अग्रिम से पहले ही संवितरित राशियों हेतु लेखे को विस्तृत बिल उपलब्ध कराए, बिना दूसरा संक्षिप्त बिल आहरित करने को अनुमत नहीं किया जाना चाहिए, अगर उसी समय कोई शेष बचा तो उसे वापस किया जाए।

2) किसी भी मामले में विस्तृत बिल का प्रस्तुतीकरण अग्रिम आहरित किए गए महीने के अगले महीने की समाप्ति से अधिक विलम्बित नहीं होना चाहिए।

3) संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर उचित ध्यान सहित राशि की सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसे प्रत्येक अधिकारी द्वारा संक्षिप्त बिलों पर आहरित किया जा सके।

अप्रैल 2010 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान दि.दु.यो. के विभागीय अधिकारियों को प्रदान किए अग्रिमों की एक समीक्षा ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन को प्रकट किया जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है

- **अग्रिम की भारी राशि** - लेखापरीक्षा ने पाया कि दैनिक आधार पर अग्रिम भुगतान ₹ 0.23 लाख से ₹ 14.01 लाख के बीच थे। अग्रिम भुगतानों के समायोजन की प्रवृत्ति के विश्लेषण ने प्रकट किया कि प्रत्येक वर्ष, मार्च माह के दौरान, बकाया अग्रिमों में काफी गिरावट थी। यह दर्शाता है कि अग्रिम भुगतानों

का समायोजन नियंत्रण में था तथा दि.दु.यो. की वित्तीय विवरणियों की अच्छी स्थिति को प्रकट करने हेतु केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान इस संबंध में प्रयास किए गए थे।

- **आहरित अग्रिमों का खराब निर्धारण**- 2010-11 के दौरान, 83 मामलों में आवश्यकता से अधिक अग्रिम का आहरण किया गया था अर्थात् आहरित ₹5.88 लाख की राशि के प्रति ₹ 2.28 लाख को विलम्बों के पश्चात वापस किया गया था। इसी प्रकार, 2011-12 के दौरान, 79 मामलों में ₹ 8.08 लाख की अग्रिम राशि आहरित की गई, जिसके प्रति ₹ 2.96 लाख की राशि को काफी विलम्ब के पश्चात वापस किया था।

- **संहिता प्रावधानों के उल्लंघन में व्यक्तिगत को अग्रिम** - 108 मामले थे, जहाँ संहिता प्रावधानों तथा वित्तीय औचित्य के उल्लंघन में पिछले अग्रिमों का समायोजन करने से पहले दो अधिकारियों को अग्रिम प्रदान किया गया था।

दि.दु.यो. में विभागीय अग्रिम प्रदान करने में उल्लंघन के दो विशिष्ट मामले नीचे उजागर किए गए हैं:

क) दि.दु.यो. के एक कर्मचारी 'एक्स' द्वारा आहरित अग्रिमों का विश्लेषण (2010-11)

- 46 मामलों में कर्मचारी ने ₹3.20 लाख के अग्रिम आहरित किए तथा ₹1.47 लाख की राशि अर्थात् आहरित कुल अग्रिम के 46 *प्रतिशत* को वापस किया था।
- मासिक आधार पर आहरित औसतन अग्रिम तथा वापसी को क्रमशः ₹0.27 लाख तथा ₹0.12 लाख पर परिकलित किया गया।
- 21 मामलों में कुल ₹ 0.75 लाख की राशि आहरित की गई थी। यह पूर्ण अव्ययित राशि वापस की गई थी।

ख) दि.दु.यो. के अन्य कर्मचारी 'वाई' द्वारा आहरित अग्रिमों का विश्लेषण (2011-12)

- 62 मामलों में कर्मचारी ने ₹6.69 लाख के अग्रिम आहरित किए तथा ₹ 2.34 लाख की राशि अर्थात आहरित कुल अग्रिम के 35 *प्रतिशत* को वापस किया।
- मासिक आधार पर आहरित औसतन अग्रिम तथा वापसी को क्रमशः ₹ 0.56 लाख तथा ₹ 0.19 लाख पर परिकलित किया।
- 14 मामलों में कुल ₹ 1.06 लाख की राशि आहरित की गई थी। यह पूर्ण अव्ययित राशि वापस की गई थी।

प्रणालीगत कमजोरियां - म.प्र. दि.दु.यो. ने विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अग्रिम के आहरण हेतु कोई वित्तीय सीमा निर्धारित नहीं की थी। नमूना जांच आधार पर ऊपर उजागर अनियमितताएं एक वित्तीय सीमा को निर्धारित करने तथा अस्थायी अग्रिमों का संचालन करने हेतु विभागीय अनुदेश जारी करने की भी आवश्यकता को रेखांकित करती है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर, विभाग अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रोकड़ अग्रिम के आहरण हेतु मौद्रिक सीमा अब निर्धारित कर दी गई थी।

3. नि.ज.खा. का संचालन

सिविल लेखे नियम पुस्तिका तथा अन्य संहिता प्रावधानों[3] के अंतर्गत प्रशासनिक अध्यक्ष को, बैंक जिसमें खाता खोले जाना प्राधिकृत है द्वारा समग्र जांच किए जाने के तहत, सीधे खाते में प्राप्तियों को जमा कराने तथा उसमें से आहरण करने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक निजी जमा खाते (नि.ज.खा.) का अनुरक्षण करने का प्रावधान है।

2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए दि.दु.यो. द्वारा अनुरक्षित नि.ज.खा. से किए गए व्यय के विश्लेषण ने प्रकट किया कि व्यय दि.दु.यो. द्वारा 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय के 87 *प्रतिशत* से 90 *प्रतिशत* के बीच था। परिणामस्वरूप, पार्टियों/अभिकरणों को भुगतान जारी करने से पहले भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) द्वारा की गई जांचों को अनदेखा किया गया था। दि.दु.यो. में पूर्ण संस्वीकृति कार्यबल के साथ कार्य कर रहे भु.ले.का. को भी इसके कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया गया था तथा इसकी भूमिका स्थापना व्ययों के संसाधन तक ही सीमित थी।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यय की मदें अर्थात् संयंत्र एवं मशीनरी, मुख्य कार्य एवं लघु कार्य, मजदूरी, टैम्पो/वाहनों को किराए पर लेने के कारण परिवहन तथा कार्यालय व्ययों को नि.ज.खा. में शामिल करने हेतु मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार नि.ज.खा. के अंतर्गत इन शीर्षों से संबंधित व्ययों को दर्ज करना अप्राधिकृत था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि मदों पर हुए जिस व्यय को भु.ले.का. खाते में सम्मिलित करने के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था, उसे भविष्य में केवल

[3] सा.वि.नि. का नियम 88 एवं 89 तथा प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली का नियम 191

भु.ले.का., दि.दु.यो. के माध्यम से ही किए जाने को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करता है कि दि.दु.यो. ने रोकड़ प्रबंधन एवं अग्रिम संवितरण में अच्छी वित्तीय प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया था।

2.2 लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

दिल्ली दुग्ध योजना अपने परिसर में परिचालित भारतीय स्टेट बैंक से निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क की वसूली करने में विफल हुआ था। इसके कारणवश मार्च 1999 से नवम्बर 2012 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.88 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई थी।

सरकार अपने विभागों द्वारा दिए गए स्थान के बदले में बैंकों पर लगाए जाने वाले लाईसेंस शुल्क की दर आवधिक रूप से निर्धारित करती है। इस नीति के अनुरूप, संपदा निदेशालय (स.नि.), सामान्य पूल आवास के संबंध में वाणिज्यिक संस्थाओं से वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क की राशि को निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी करता है।

दिल्ली दुग्ध योजना (दि.दु.यो.) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 1972 में उनके परिसर में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा स्थापित की गई थी। दिल्ली दुग्ध योजना एवं बैंक के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार 1198.64 वर्ग फुट का क्षेत्र बैंक को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के रूप में रिकार्ड किया गया था। तत्पश्चात, बैंक ने अप्राधिकृत रूप से दिल्ली दुग्ध योजना के परिसर पर अतिक्रमण किया तथा अपने परिचालन स्थान को बढ़ा रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली दुग्ध योजना ने कई बार कृषि मंत्रालय को सूचित किया था (जून 2001) कि बैंक ने बिना अनुमति के ही 3150 वर्ग फुट के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिकृत कर लिया था। इस प्रकार, बैंक द्वारा अधिकृत क्षेत्र 4348.64 वर्ग फुट (1198.64 वर्ग फुट जमा 3150 वर्ग फुट) अर्थात, 404 वर्ग मीटर तक बढ गया था।

मंत्रालय ने पाया (नवम्बर 2001) कि अनाधिकृत प्रवेश को रोक पाने में दिल्ली दुग्ध योजना की विफलता, एक गंभीर कमी थी।

सामान्य पूल आवास से परिचालित बैंको से लाईसेंस शुल्क प्रभारित करने के लिए सं.नि. ने 16 मार्च 1999 से प्रभावी आदेश जारी किए थे। तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना सं.नि. द्वारा निर्धारित दरों तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिकृत क्षेत्र की गणना करे

बिना ही ₹ 4742 प्रति माह की निश्चित राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ था। यह पहले की दरों पर, 25 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी कर प्राप्त किया गया था, जैसा पट्टा विलेख में दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.दु.यो. द्वारा बैंक से प्रभारित लाइसेंस शुल्क, स.नि. द्वारा निर्धारित दरों से बहुत कम था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.87 करोड़ का लाइसेंस शुल्क कम उदग्रहण हुआ था।

इसी प्रकार, दि.दु.यो. द्वारा 11.90 वर्ग मीटर की जगह जनवरी 2007 के अनुबंध के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को ए.टी.एम. खोलने के लिए पट्टे पर दी गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली दुग्ध योजना ने ₹ 220 प्रति वर्ग मीटर की दर से अर्थात ₹ 2618 प्रति माह का लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया था। यद्यपि यह दर सं.नि. द्वारा अप्रैल 2011 से ₹ 5414 प्रति माह तक बढ़ाकर संशोधित कर दी गयी थी। इस प्रकार, सं.नि. की निर्धारित दर लागू न किए जाने के कारण ₹ 1.17 लाख की राशि के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई थी।

इस प्रकार, मार्च 1999 से नवम्बर 2012 तक की अवधि के दौरान दि.दु.यो. द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क प्रभारित करने में विफलता के कारण ₹ 1.88 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई**(अनुबंध-1)**। इसके अतिरिक्त, परिसर के अनाधिकृत कब्जे हेतु भारतीय स्टेट बैंक से कोई दंडात्मक क्षतिपूर्ति नहीं ली गई थी।

मामला मई 2013 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।

2.3 निधियों का समयपूर्व जारी करना

मंत्रालय ने रा.कृ.ग्रा.वि.बै. को "कटड़ों का संरक्षण एवं पालन" योजना के अंतर्गत एक अधूरे प्रस्ताव के आधार पर और योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 1.92 करोड़ की राशि जारी की। परिणामस्वरूप रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा राशि का उपयोग न किए जाने के कारण निधियों का नौ से अधिक माह तक अवरोधन हुआ।

कृषि मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र क्षेत्रीय योजना 'कटड़ों का संरक्षण और पालन' के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक अनुमति दी थी। ₹ 300 करोड़ के परिव्यय के साथ योजना को, योजना अवधि अर्थात् 2008-09 से 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) के माध्यम से कार्यान्वित होना था।

योजना के मुख्य उद्देश्य मांस उत्पादन, भैंस के मांस और सह-उत्पाद की निर्यात एवं घरेलू बाजार और चमड़ा उद्योग हेतु कच्चे माल आधार की वृद्धि के लिए उपलब्धता बढ़ाने के लिए कटड़ों का संरक्षण और पालन करना था।

योजना दिशानिर्देश के अनुसार, प्रत्येक राज्य में, संबंधित राज्य सरकार के पशु-पालन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं मॉनिटरिंग समिति (रा.स्त.अ.मॉ.स.) गठित होनी थी। समिति की बैठकें आवधिक रूप से होनी थी और उपयुक्त प्रस्तावों को मंजूर करना था। रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. के क्षेत्रीय अधिकारी को केन्द्रीय अधिकारी के रूप में कार्य करना था, जो रा.स्त.अ.मॉ.स. की संबंधित राज्यों में लागू होने वाली परियोजनाओं पर विचार करने के लिए बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार था। योजना हेतु उपलब्ध निधियां मंत्रालय द्वारा रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. को रा.स्त.अ.मॉ.स. के द्वारा संस्वीकृति विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के प्रति की जानी थी जिसका रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा एक माह के अंदर वितरण किया जाना था।

रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. ने मंत्रालय के समक्ष योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹ 4.37 करोड़ की धनराशि की मांग करते हुए एक प्रस्ताव रखा (अगस्त 2010) था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रस्ताव में केवल योजना के विविध घटकों के अंतर्गत अपेक्षित निधि के विवरण ही सम्मिलित थे। प्रस्ताव रा.स्त.अ.मॉ.स. द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित विशिष्ट परियोजना को सम्मिलित नहीं करता था। इस प्रकार, योजना में दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग (ए.वि.प्र.) ने यह जानते हुए कि रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अपूर्ण था, ₹ 1.92 करोड़ की राशि को जारी करने का अनुमोदन किया था। निधियां सितम्बर 2010 में जारी की गयी थीं। तदुपरांत, रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. धनराशि का उपयोग, पशु-वध अधिनियम के अंतर्गत भैसों की हत्या पर प्रतिबंध लगने के कारण राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण नहीं कर पाया था। इसके फलस्वरूप, इसने 'सुअर बाडा विकास' नामक अन्य योजना के अंतर्गत धनराशि के उपयोग की अनुमति मांगी (मई 2011), जिसके लिए मंत्रालय ने अनुमति प्रदान कर दी थी (जून 2011)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय के इस कार्रवाई के कारण वित्त वर्ष, जिसमें मूलतः निधियां संस्वीकृति की गई थीं, की समाप्ति के बाद निधियों का पुनर्विनियोजन हुआ। इस प्रक्रिया में, इसने सामान्य वित्त नियमावली के नियम 59 का उल्लंघन किया, जो व्यवस्था करता है कि निधियों को पुनर्विनियोजन की संस्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा

ऐसे अनुदान अथवा विनियोजन जिस वित्त वर्ष से संबंधित हैं, की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय दी जा सकती है। मंत्रालय की कार्रवाई इस प्रकार अनियमित थी।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सुअर-बाड़ा विकास योजना को निधियों का विपथन उपलब्ध निधि के एक ऐसी योजना, जहाँ अधिक धनराशि की मांग थी, में बेहतर उपयोग के एकमात्र अभिप्रेत से किया गया था। इसके अतिरिक्त, रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा "कटड़ों का संरक्षण एवं पालन" योजना के अन्तर्गत निधियों का उपयोग लाभार्थियों की रूचि पर निर्भर था तथा इस प्रकार की योजनाएं अक्सर चलने में कुछ अधिक समय लेती हैं।

मंत्रालय द्वारा निधियों के रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. द्वारा प्रस्तुत अधूरे प्रस्ताव, जो योजना के प्रावधानों की संगति में नहीं था, के आधार पर अनियमित निर्गम के मुद्दे को उत्तर पुष्टि नहीं करता था। यह मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव के अपर्याप्त जाँच को भी दर्शाता है। इसके बाद मंत्रालय का अन्य योजना हेतु निधियों का विपथन का कदम भी अनियमित था और इसने संसदीय प्राधिकृत की प्रक्रिया को कमजोर बनाया।

अध्याय III : नागरिक उड्डयन मंत्रालय

जी.एम.आर. हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड का या.से.शु. (एस.सी.) एसक्रो खाता

3.1 या.से.शु. (एस.सी.) निधि एसक्रो खाते में से अमान्य व्यय

जी.है.अं.ह.अ.लि. ने या.से.शु. (एस.सी.) निधि एसक्रो खाते से ₹ 100.40 करोड़ का अमान्य व्यय किया।

वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 88 के अनुसार, हवाई अड्डा संचालक वायुयान पर चढ़ने वाले यात्रियों से 'यात्री सेवा शुल्क' (या.से.शु.) लेने का अधिकारी है। इस प्रकार संग्रहित या.से.शु.[1] में एक सुरक्षा घटक (या.से.शु. का 65%) तथा एक सुविधा घटक (या.से.शु. का 35%) सम्मिलित है। किसी निजी हवाई अड्डा संचालक के मामले में, सुविधा घटक उसके द्वारा रख लिया जाता है, जबकि सुरक्षा घटक एस्क्रो खाते में रखा जाता है जिसका नागरिक उड्डयन मंत्रालय (ना.उ.मं.) द्वारा अनुमत सुरक्षा संबंधी व्यय करने में उपयोग किया जाता है। तदनुसार, जी.एम.आर. हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (जी.है.अ.ह.अं.लि.) (संचालक) जून 2008 से एक एसक्रो खाते का परिचालन कर रहा था।

ना.उ.मं. ने या.से.शु. (एस.सी.) एसक्रो खाते के विनियमन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (मा.प.प्र.) जारी की (जनवरी 2009)। मा.प.प्र. उन प्रयोजनों के विवरण देता है, जिनके लिए एसक्रो खाते की राशि का उपयोग किया जा सकता है।

तथापि, संचालक ने या.से.सु. (एस.सी.) निधि से निम्नलिखित अमान्य व्यय प्रभारित किया:

क्र. स.	व्यय के मद	वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
राजस्व व्यय				
1.	प्रशासनिक लागत	2008-09	1.46	मा.प.प्र. के पैरा 6.2 के अनुसार मान्य नहीं।
		2009-10	0.85	
2.	आतंकवाद बीमा प्रीमियम	2009-10	0.70	मा.प.प्र. के पैरा 6.7 के अनुसार, या.से.शु. (एस.सी.) से सृजित तय परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने
		2010-11	0.33	

[1]प्रति यात्री ₹ 200 पर निर्धारित; इसका 65 *प्रतिशत* अर्थात, ₹ 130 सुरक्षा घटक है।

		2011-12	0.57[2]	के लिए दी जाने वाली बीमा अनुमेय है। अतः हवाई अड्डा को सुरक्षा प्रदान करने वाली यह प्रीमियम अनुमेय नहीं है।
3.	क्वार्टरों के निर्माण हेतु उधार ली गयी धनराशि पर प्रदत्त ब्याज	2008-09	4.53	मा.प.प्र. तथा ना.उ.मं. के 9 मई 2006 के आदेशानुसार, केवल के.औ.सु.ब. को किये गये भुगतान ही अनुमेय हैं। के.औ.सु.ब. के क्वार्टरों पर किये गये व्यय, के.औ.सु.ब. को किया गया भुगतान नहीं है। अतः यह अनुमेय नहीं है।
		2009-10	6.86	
		2010-11	6.91	
		2011-12	8.27	
4.	भूमि पंजीकरण प्रभार	2010-11	0.03	व्यय को परियोजना निधियों से पूरा करना था या.से.शु. (एस.सी.) एस्क्रो खाते से नहीं।
कुल योग			**30.51**	
पूंजीगत व्यय				
1.	भूमि क्रय	2007-08	4.00	व्यय को परियोजना निधियों से पूरा करना था या.से.शु. (एस.सी.) एस्क्रो खाते से नहीं।
2.	के.औ.सु.ब. के क्वार्टरों का निर्माण	2008-09	65.89	
कुल योग			**69.89**	
या.से.शु. (एस.सी.) निधि में से अमान्य व्यय का सकल योग			**100.40**	

संचालक द्वारा या.से.शु. (एस.सी.) निधि से अमान्य व्यय के मामले को या.से.शु. (एस.सी.) एस्क्रो खाते के वर्ष 2007-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान ना.उ.म. ध्यान में लाया गया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए ना.उ.मं. ने जी.है.अं.ह.अ.लि. को उपरोक्त कथित 2010-11 तक किये गये सभी अनुचित व्ययों को तुरंत वापस करने और एक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश (जुलाई 2012) दिया। जी.है.अं.ह.अ.लि. ने ना.उ.मं. के निर्देशानुसार अनुचित व्ययों को वापस नहीं किया, बल्कि 2011-12 के दौरान ₹ 8.84 करोड़ का अतिरिक्त अमान्य व्यय किया था जैसा कि ऊपर दिखाया गया है।

इस प्रकार, संचालक द्वारा या.से.शु. (एस.सी.) निधि से ₹ 100.40 करोड़ का अमान्य व्यय प्रभारित करना अनियमित था और इसे शीघ्र वापस करना आवश्यक था।

[2] आंतकवाद बीजा प्रीमियम पर ब्याज के प्रति ₹ 0.14 करोड़ सहित

अध्याय IV : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

4.1 पेट्रोलियम एवं विस्फोट सुरक्षा संगठन, नागपुर

शिवकाशी में पटाखे अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (प.अ.वि.के.) हेतु निर्मित बुनियादी ढांचे का कम उपयोग।

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पे.वि.सु.सं.) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग (औ.नी.प्रो.वि.) के अंतर्गत एवं अधीनस्थ कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता विस्फोटक मुख्य नियंत्रक (वि.मु.नि.) करता है। इसे विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके अधीन बनाए गए विभिन्न नियमों के क्रियान्वयन का कार्यभार सौंपा गया है।

पे.वि.सु.सं. ने प्रदूषण स्तर कम करने हेतु पर्यावरण हितैषी पटाखों के निर्माण और पटाखों से होने वाले खतरों संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शिवकाशी में, जो पटाखा निर्माण गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है, पटाखे अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (प.अ.वि.के.) की स्थापना हेतु एक परियोजना की संकल्पना की (2003)। परियोजना की समाप्ति के लिए कोई निर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई।

भारतीय पटाखा उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाए गए प.अ.वि.के.के उद्देश्यों में पर्यावरण हितैषी पटाखों का निर्माण, जोखिमपूर्ण निर्माण प्रक्रियाओं का यंत्रीकरण, उत्पादों का विकास व मानकीकरण, कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा, रासायनिक संयोजना की प्रकृति का अध्ययन तथा निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन, तकनीकी संसाधन विकास, कच्चे माल का परीक्षण, इत्यादि सम्मिलित थे।

सिविल तथा विद्युत कार्यों को 10वीं पंचवर्षीय योजना (2007) की समाप्ति तक ₹3.48 करोड़ की लागत पर समाप्त कर लिया गया। परियोजना का विस्तार 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रयोगशाला उपस्कर, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा उपकरणों के क्रय हेतु किया गया। परियोजनाओं पर किया गया व्यय 2011-12 तक ₹6.49 करोड़ था।

जबकि प.अ.वि.के., शिवकाशी की परियोजना गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही थी, पेसो को रासायनिक संयोजन के आधार पर पटाखों का मूल्यांकन कर पटाखे के प्रत्येक प्रकार व श्रेणी का रासायनिक सूत्र ज्ञात करने हेतु अनुसंधान गतिविधियां प्रारंभ करनी थी (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 15 जुलाई 2005)। पेसो को पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक रसायन का अनुपात/संयोजन और अनुमत भार निर्दिष्ट करना और पटाखों को दो श्रेणियों-ध्वनि उत्पन्न करने वाले और रंग/प्रकाश उत्पन्न करने वाले पटाखों में विभक्त करना था।

पटाखों के संयुक्त मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षता में संबंधित मुद्दों की जांच करने हेतु गठित कोर समिति (2005) ने प.अ.वि.के. के उद्देश्यों को विस्तार से बताया और प.अ.वि.के. के लिए 53 तकनीकी तथा 40 लिपिक वर्गीय पदों की स्टाफ संख्या की सिफारिश की। तकनीकी/प्रशासकीय/सहायक स्टाफ के कुल 80 पद सृजित करने हेतु एक प्रस्ताव फरवरी 2006 में प.उ.नि. द्वारा औ.नी.प्रो.वि. को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसंधान और क्रियान्वयन गतिविधियां यथाशीघ्र प्रारंभ करने हेतु 12 पदों का न्यूनतम आवश्यक कार्य बल निर्मित करने हेतु प.उ.नि. द्वारा एक शीघ्र क्रियान्वयन माड्यूल भी जून 2006 में प्रस्तावित किया गया।

प.अ.वि.के. का उद्घाटन जुलाई 2011 में हुआ। तथापि इस इकाई के लिए कार्यबल के सृजन के प्रस्तावों को अब तक अनुमति नहीं मिली है (दिसम्बर 2012) जिसके कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे। संयुक्त सचिव, औ.नी.प्रो.वि. के निर्देश पर प.अ.वि.के. के बुनियादी कार्यों को प्रारंभ करने हेतु पेसो की वर्तमान श्रमशक्ति को गतिशील किया गया, अर्थात एक पटाखा नियंत्रक प.अ.वि.के. के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था, और स्टाफ स्तर पर एक वरिष्ठ व एक कनिष्ठ सहायक को डी.टी.एस., घोंडकायरी, नागपुर से और एक आशुलिपिक को कार्यालय पटाखा नियंत्रक, वैल्लोर से स्थानांतरित किया गया था। प.अ.वि.के. की सुरक्षा व रख-रखाव का कार्य के.लो.नि.वि. को प्रदान कर दिया गया है और दिन प्रतिदिन की न्यूनतम गतिविधियां अस्थायी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार कार्य करने के लिए समूचित रूप से सुसज्जित होने के बावजूद प.अ.वि.के. पेसो से लिए गए 3 तकनीकी स्टाफ के साथ कार्य कर रहा है जिनके पास सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित अनुसंधान कार्य करने की कुशलता नहीं है।

2009 से 2012 के दौरान शिवकाशी में दुर्घटनाएं होना और संचार माध्यमों द्वारा इनका उजागर होना लगातार जारी रहा।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2013) कि प.अ.वि.के. परिसर का प्रयोग संगोष्ठियों के आयोजन, प्रशिक्षण, परीक्षण, परीक्षाओं व पूछ-ताछ के लिए किया जा रहा था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय द्वारा प.अ.वि.के. परिसर का उपयोग करने हेतु किए गए उपाय उन प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते जिसके लिए ₹ 6.49 करोड़ का व्यय किया गया।

अध्याय V: विदेश मंत्रालय

5.1 सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ

मंत्रालय द्वारा सम्पति कर में वृद्धि के आधार पर सेवा प्रभार प्रति वीजा आवेदन वर्तमान दर से 12 *प्रतिशत* बढ़ाने की अनुमति के परिणामस्वरूप सेवा प्रदाता को अक्तूबर 2011 से दिसम्बर 2012 तक ₹ 3.45 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

भारतीय उच्चायोग, लंदन (मिशन) और उसके बर्मिघम व एडिनबर्ग स्थित वाणिज्यिक दूतावासों ने विभिन्न वीजा सुविधा सेवाएं प्रदान करने हेतु 24 जनवरी 2008 को मैसर्स वी.एफ. सर्विसेज (यूके) लि. (सेवा प्रदाता) के साथ समझौता किया। समझौते की अनुसूची I की शर्त 4.2 के अनुसार सेवा प्रदाता की सेवा प्रभार की धनराशि तभी बदली जा सकती है जब स्थानीय करों या वैट की दरों में बदलाव हो।

सेवा प्रदाता ने मुद्रास्फीति, भारतीय रूपये के मुकाबले ग्रेट ब्रिटेन पाउण्ड के अवमूल्यन, आवेदकों की संख्या में कमी और दरों और करों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मिशन से सेवा प्रभार प्रति व्यक्ति आवेदन £6.90 से बढ़ाकर £8.80 करने का अनुरोध किया (जुलाई 2010)। मंत्रालय ने स्थानीय करों के कारण सेवा प्रभार को 12 *प्रतिशत* वृद्धि करने की सहमति दी और बताया कि सेवा प्रभार में इतनी प्रतिशतता से बढ़ोतरी की जा सकती है। यद्यपि मंत्रालय ने सम्पत्ति कर में 12 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी सेवा प्रभारों में सम्पति कर के *प्रतिशत*/भार तक सीमित रखने की बजाय त्रुटिवश सम्पूर्ण सेवा प्रभार पर लागू कर दी। इस प्रकार 12 सितम्बर 2011 से प्रति आवेदन सेवा प्रभार बढ़कर £7.70 होने के फलस्वरूप ₹ 3.45 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में बताया गया है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (जनवरी और अगस्त 2012) कि सेवा प्रदाता ने वर्ष 2010 के दौरान 498333 वीजा आवेदनों पर कार्य किया। इस प्रकार, उनके द्वारा वर्ष के दौरान £6.90 प्रति आवेदन की दर से संग्रहित किया गया कुल सेवा प्रभार £3438498 था। वर्ष 2010 और 2011 के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा अदा किया गया सम्पति कर क्रमशः £127230.4 और £139969.20 था। अतः सम्पति कर के कारण व्यय में वृद्धि सम्पूर्ण रूप से £12739 थी। प्रतिशतता में, सम्पति कर 2010 में संग्रहीत सेवा प्रभार की कुल धनराशि का, 2010 में 3.70[1] *प्रतिशत* से बढ़कर 2011 में 4.07[2]

---

[1] 498333 (2010 के दौरान वीजा आवेदनों की संख्या) को £6.90 से गुणा (प्रति आवेदनकर्ता हेतु सेवा प्रभार) - £3438497.70, £127230.40 (वर्ष 2010 हेतु संपत्ति कर) को £3438497.70 से भाग (2010 हेतु लगाया गया कुल सेवा प्रभार) को 100 से गुणा = 3.70 *प्रतिशत*।

[2] 498333 (2010 के दौरान वीजा आवेदनों की संख्या को £6.90 से गुणा (प्रति आवेदनकर्ता हेतु सेवा प्रभार) - £3438497.70, £139969.20 (वर्ष 2010 हेतु संपत्ति कर) को £3438497.70 से भाग (2010 हेतु लगाया गया कुल सेवा प्रभार) को 100 से गुणा = 4.07 *प्रतिशत*।

प्रतिशत हो गया था। इस प्रकार सम्पति कर में वृद्धि सेवा प्रदाता द्वारा लगाए जा रहे वर्तमान प्रभार का मात्र 0.37[3] *प्रतिशत* थी।

सेवा प्रभार में वृद्धि को वर्तमान दर के 0.37 *प्रतिशत* की वृद्धि तक सीमित रखने के बजाय मंत्रालय ने त्रुटिवश इसे वर्ष 2010 के सम्पति कर की तुलना में सम्पति कर में *प्रतिशत* वृद्धि तक बढ़ा दिया जो 12[4] *प्रतिशत* निकल कर आया। संशोधित सेवा भार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित £ 7.70 के स्थान पर £ 6.93[5] होना चाहिए था क्योंकि प्रति आवेदन £0.03 की वृद्धि के परिणामस्वरूप £15658[6] का अतिरिक्त राजस्व सम्पति कर में वृद्धि के कारण होने वाले £12739[7] अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त थी। अतः इस प्रकार संपत्ति कर में वृद्धि के कारण सेवा प्रभार में वृद्धि हुई की गणना करने के लिए गलत विधि अपनाने के परिणामस्वरूप प्रति आवेदन £0.80 सेवा प्रभार की वृद्धि और अक्तूबर 2011 से दिसम्बर 2012 तक सेवा प्रदाता को £455688.31[8] (₹ 3.45 करोड़)[9] का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

मिशन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि इनपुटों प्रदत्तों को मंत्रालय को उत्तर हेतु अग्रेषित किया जा चुका है और जैसे ही तथ्य मिशन को प्रदान किए जाते हैं, उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2012 में भेजा गया और उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।

---

[3] 4.07 *प्रतिशत* में से 3.70 *प्रतिशत* घटाकर

[4] £5550.63 (2011के सम्पत्ति कर अर्थात £51140.63 में से 2010 का सम्पत्तिकर अर्थात् £45590 घटाकर) को 2010 के सम्पत्ति कर (£45590) से भाग करके 100 से गुणा करने पर

[5] 6.90 में 0.37 *प्रतिशत* को जमा करके (प्रति आवेदन पर वर्तमान सेवा प्रभार)

[6] 521945 (2011 में सेवा प्रदाता निपटाए गए आवेदनों की संख्या) को £0.03 से गुणा कर £127230 (2010 में सेवा प्रदाता द्वारा अदा किया गया गया संपत्तिकर) घटा पर

[7] £139969 (2011 के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा अदा किया गया सम्पत्तिकर) में से £127230 (2010 के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा अदा किया गया संपत्ति कर) घटाने पर

[8] प्रति आवेदन पर £0.77 को 591803 को गुणा करके (अक्तूबर 2011 से दिसम्बर 2012 के दौरान संसाधित आवेदन की संख्या)

[9] 1£=₹75.71 के विनिमय दर पर (अक्तूबर 2011 की विनिमय दर जोकि अक्तूबर 2011 से जुलाई 2012 तक की अवधि के दौरान सबसे न्यूनतम विनिमय दर थी)= ₹34500162

अध्याय VI : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको)

6.1 परियोजना उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है जो भारत में एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को विभिन्न एच.आई.वी./एड्स निवारण तथा नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से नेतृत्व प्रदान करता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने उच्च जोखिम क्षेत्रों में सामाजिक विपणन योजना के अंतर्गत कंडोम वेंडिग मशीनों (कं.वें.म.) के माध्यम से कंडोम तक गुणात्मक पहुंच बनाने का प्रस्ताव (मार्च 2005) रखा। योजना देश के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हर समय उच्च कोटि के कंडोमों की उपलब्धता एवं सुलभता बढ़ाकर सुरक्षित यौन अभ्यासों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करती थी। सार्वजनिक स्थानों जैसे, रेलवे स्टेशन, रेस्त्राओं, बस पड़ाव, सिनेमा घरों, रेड लाइट क्षेत्रों, बैंकों, डाक घरों आदि पर कं.वें.म. के प्रतिष्ठान के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त करने की रणनीति अपनायी गयी थी।

योजना को चरणबद्ध तरीके से परिचालित किया गया था जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

परियोजना चरण	शामिल किये गये जिलों की सं.	प्रतिष्ठापित किये जाने वाले कं.वे.म.[1] की संख्या	कार्यान्वयन अभिकरण	वित्तीय प्रबंधन	
चरण- I	67	11025 एल.टी.डी.ओ.- 8000 एम.टी.डी.ओ.- 3000 एच.टी.डी.ओ.- 25	हि.लै.लि. लाइफकेयर लि. (पूर्व में हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड) एक सा.क्षे.उ.	मार्च 2005 में ₹ 10 करोड़ जारी किए गए	मशीनों के प्रापण हेतु ₹ 8.33 करोड़ तथा शेष परिचालन एवं प्रोत्साहन व्यय को पूरा करने के लिए।
चरण-II	68	10025 एलटीडीओ-1000 एचटीडीओ-25	हिस्तुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोत्साहन न्यास (हि.लै.प.नि.प्रो.न्या.), हिं.लै.लि. के अंतर्गत एक न्यास	जनवरी 2007 में ₹ 10 करोड़ जारी किए गए। 2010-11 से 2012-13 के बीच ₹ 1.50 करोड़ के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में कं.वें.म. के अनुरक्षण लागत के लिए ₹ 50,000 प्रतिमाह का आवर्ती व्यय जारी किया गया।	₹ 8.85 करोड़ मशीनों के प्रापण तथा शेष परिचालन एवं प्रोत्साहन व्यय को पूरा करने के लिए। कार्यक्रम के कार्यान्वयन को दिसम्बर 2012 तक के लिए आगे बढ़ाया।

[1] निम्न, मध्य एवं उच्च व्यापार निर्गम प्रदान करने वाली मशीन

लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी थीं।

6.1.1 परियोजना का प्रत्यक्ष निष्पादन

6.1.1.1 कमजोर योजना

मंत्रालय ने योजना (चरण-I) की शुरूआत हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड द्वारा वेंडिंग मशीन के माध्यम से कंडोम का सामाजिक विपणन शुरू करने के प्रस्ताव के आधार पर की। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने योजना को आगे बढ़ाने से पहले कोई समग्र व्यवहार्यता अध्ययन नहीं कराया था।

अक्तूबर 2006 में, मंत्रालय में हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. द्वारा योजना (चरण-II) के अंतर्गत 11025 कंडोम वेंडिग मशीनों के प्रतिष्ठापन के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु एक बैठक आयोजित की गयी थी। प्रस्ताव के साथ हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. द्वारा एक प्रगति रिपोर्ट पेश की गयी थी, जिसमें उसने जनवरी से अगस्त 2006 के दौरान वेंडिग मशीनों के माध्यम से 13.33 मिलियन कंडोमों के विक्रय का दावा किया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यह प्रतिदिन प्रति मशीन लगभग 4.98 कंडोम था। यह प्रतिदिन 6 कंडोम के न्यूनतम लक्षित विक्रय से कम था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने देखा कि जनवरी 2007 में चरण-II हेतु अनुदान जारी करने से पूर्व, अक्तूबर तथा नवम्बर 2006 में इसकी बिक्री और भी कम होकर क्रमशः 1.57 एवं 1.55 प्रति मशीन प्रतिदिन हुई। तथापि, परियोजना के चरण-II हेतु स्थायी वित्त समिति (स्था.वि.स.) के प्रस्ताव को स्वयं फर्म द्वारा दिये गये मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ाया गया था।

इस प्रकार, न तो मंत्रालय ने योजना शुरू करने के पहले कोई समग्र व्यवहार्यता अध्ययन कराया, न ही इसने योजना के चरण-II हेतु आगे धनराशि जारी करने के पूर्व चरण-I के अंतर्गत योजना के वितरण के प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया था।

6.1.1.2 मशीनों को स्थापित करने में देरी

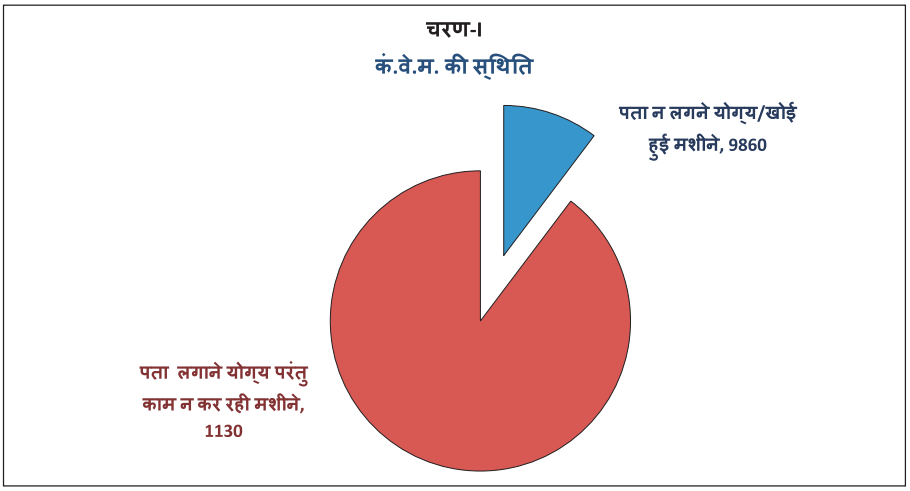
मार्च 2005 में हुए एस.एफ.सी. की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, मैसर्स हि.लै.लि. लिमिटेड को छः महीने के अन्दर कंडोम वेंडिग मशीनों को प्राप्त करना एवं लगाना था। इस संबंध में हि.लै.लि. द्वारा निर्गत अधिसूचना में पूर्तिकर्ता को कहा गया कि चरण-I में वह अनुबंधित मशीनों की पूर्ति, उसको लगाने और मशीनों को कार्यशील करने का काम 30 सितम्बर 2005 तक या उसके पहले पूरा करें। चरण-II में, मशीनों को अप्रैल से जुलाई 2008 के बीच स्थापित किया जाना था।

लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि चरण-I में मशीनों को अक्तूबर 2005 से जनवरी 2006 के बीच में लगाया गया था। चरण- II में मशीनों को लगाने का काम अगस्त 2008 में शुरू किया गया जो कि कं.वें.म. को क्रियाशील करने के अनुबंधित तिथि से बाद की तिथि थी। मशीनों को लगाने के काम में देरी के लिए जगह के चुनाव, मजदूरों के हड़ताल, मूसलाधार वर्षा इत्यादि को जिम्मेदार ठहराया गया। इस देरी ने इस योजना के परिणामों एवं लक्ष्य को काफी प्रभावित किया।

6.1.2 हि.लै.लि./ हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. के साथ अनुबंधों के अभाव में कंडोम वेंडिग मशीनों की घटिया देखभाल

मंत्रालय/नाको ने हि.लै.लि./हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. के साथ इस परियोजना के प्रबंधन एवं कं.वें.म. की सुरक्षा, बचाव तथा देखभाल की जिम्मेदारी के संबंध में कोई अनुबंध/ समझौता-पत्र नहीं बनाया। परिणामस्वरूप कं.वें.म. के देखभाल से संबंधित कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था।

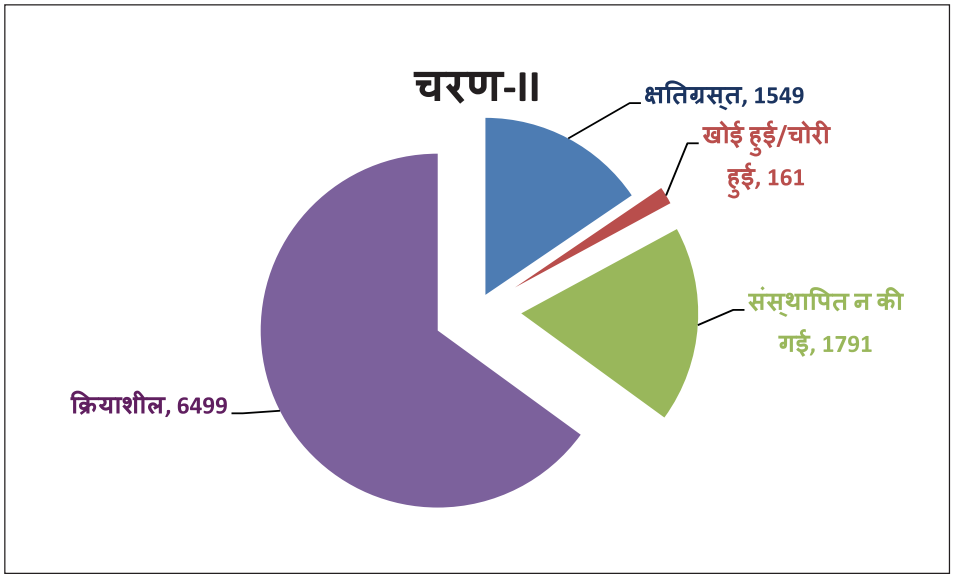
लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक कं.वें.म. की औसत उम्र 3 वर्ष है, जो कि उसकी सही देखभाल से सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पहले चरण के दौरान, इन मशीनों की देखभाल उनके प्रदायकों द्वारा जनवरी 2009 तक की गई। लेकिन बाद में प्रदायकों के साथ वार्षिक देखभाल अनुबंध के गैर मौजूदगी में मशीनों का रख-रखाव बंद हो गया। हि.लै.लि. लाइफ केयर लि. ने मशीनों के प्रचालन एवं रखरखाव हेतु एक प्रस्ताव रखा (अप्रैल 2009)। कं.वें.म. के कार्य करने की स्थिति जो कि हि.लै.लि. एवं हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. द्वारा नाको को उपलब्ध कराए गए थे, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:



जैसा कि देखा जा सकता है, चरण-I के अंतर्गत केवल 1130 मशीनें ही अपने स्थान पर उपलब्ध/पता लगाने योग्य थीं। चरण-I में लगाए गए कं.वें.म. का चोरी और क्षति के

लिए बीमा नहीं हुआ था, इसलिए चोरी हुए मशीनों का कोई क्षतिपूर्ति/दावा नहीं किया जा सका।

हि.लै.लि. ने नाको से आग्रह किया (अगस्त 2011) कि उपयुक्त कार्रवाई से छोटी-मोटी मरम्मत के बाद इनमें से कुछ मशीनों को क्रियाशील किया जा सकता था। लेकिन मार्च 2013 तक नाको के दस्तावेजों में इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रमाणिक रूप से दर्ज नहीं थी।



चरण-II में लगाए गए मशीनों का रखरखाव ₹ 10 करोड़ के लागत के अन्दर जून 2010 तक चला। इस परियोजना को ₹ 90 लाख के अतिरिक्त लागत पर कं.वें.म. के परिचालन एवं रखरखाव हेतु मार्च 2011 तक बढ़ाया गया। इस संबंध में मैसर्स हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. के साथ एक अनुबंध किया गया (जनवरी 2011)। इसका भुगतान दो किस्तों में फरवरी और नवम्बर 2011 के दौरान किया गया। इस परियोजना को और आगे ₹ 60 लाख के अतिरिक्त लागत पर सितम्बर 2011 तक बढ़ाया गया। चरण-II में मशीनों की स्थिति बेहतर थी। लेकिन यह तथ्य कि इन मशीनों ने अपने कार्य करने का सात साल का समय पूरा कर लिया था, मशीनों के लगातार रखरखाव पर किए जा रहे अत्यधिक व्यय की, इन मशीनों की उपयोगिता एवं प्रभाव के संदर्भ में नाको द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा होनी चाहिए।

नाको ने बताया कि कार्यान्वयन इकाइयों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए गए थे क्योंकि हि.लै.लि. एक केन्द्रीय है और हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. उसके द्वारा समर्थित एक न्यास था। उत्तर सा.वि.नि. के नियम 204 (IV-घ) वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जिसमें कहा गया है कि मुख्य कार्यों या उपकरणों के रखरखाव तथा

उनकी देखभाल के संबंध में अनुबंध का किया जाना अनिवार्य है। उत्तर उनके उस निर्णय के विपरीत था जिसमें उन्होंने जनवरी 2011 में एसएमपी के चरण-II के विस्तार और क्रियान्वयन हेतु मैसर्स हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. से अनुबन्ध किया था।

6.1.3 कं.वें.म. द्वारा कंडोमों की कम बिक्री

नाको ने प्रथम वर्ष में प्रत्येक निम्न व्यापार निर्गम प्रदान करने वाले मशीन (नि.व्या.नि.म.) मध्यम व्यापार निर्गम प्रदान करने वाली मशीन तथा उच्च व्यापार निर्गम प्रदान करने वाली मशीन से औसतन क्रमशः 6, 12 और 35 कंडोमों की बिक्री का अनुमान लगाया था। लेकिन यह पाया गया कि चरण-I में जनवरी 2009 तक के 36 महीनों में, 11025 कं.वें.म. द्वारा 16 लाख कंडोमों की बिक्री हुई जो प्रति मशीन द्वारा 1.34 पीस प्रतिदिन का औसत था। चरण-II के संदर्भ में टीएसजी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2008-11 के दौरान यह औसत 0.42 कंडोम प्रति मशीन प्रतिदिन था। चूंकि इस कार्यक्रम को सामाजिक विपणन संगठन (सा.वि.सं.) के साथ मिला दिया गया था, इसलिए 2011-12 से 2012-13 के दौरान औसतन कितने कंडोम का कं.वें.म. से विपणन हुआ, इस बात को नाको अलग से प्रमाणित नहीं कर सका।

यदि छः कंडोम प्रति मशीन प्रतिदिन के न्यूनतम अनुमानित बिक्री रखे तब भी यह स्पष्ट है कि कं.वें.म. द्वारा बेची गई कंडोमों की संख्या काफी कम थी। कम बिक्री की एक वजह मशीनों के खराब रखरखाव को भी माना जा सकता है। मंत्रालय उपचारी कार्रवाई हेतु कंडोम के कम बिक्री के कारणों का पता लगाने में विफल रहा।

6.1.4 कंडोमों की बिक्री द्वारा राजस्व बढ़ाने के संबंध में स्पष्टता का अभाव

मार्च 2005 में मंत्रालय द्वारा एसएफसी के लिए प्रस्तुत किए गये विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम को कंडोमों की बिक्री से अर्जित आय के द्वारा ही चलाया जाना था। द्वितीय वर्ष से इस कार्यक्रम में बिक्री से होने वाली आय को, तंत्र के रखरखाव ब्रांडिंग व्यय, इत्यादि पर खर्च किया जाना था। लेकिन लेखापरीक्षा मे यह पाया गया कि यह प्रस्ताव केवल कागजों पर था, क्योंकि इस कार्यक्रम से हुई आय की प्रमात्रा या उसके उपयोग का मंत्रालय/नाको के रिकार्ड में कोई जिक्र नहीं था। बार-बार आग्रह के बावजूद भी नाको ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। परिणामस्वरूप कंडोमों की बिक्री से प्राप्त धन एवं उनके उपयोगिता के संबंध में लेखापरीक्षा में सही पता नहीं लगाया जा सका।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि नाको के पास चरण-I एवं चरण- II में कंडोमों की बिक्री से प्राप्त धन में से क्रमशः ₹0.05 और ₹0.10 प्रति कंडोम के हिसाब से एक पुनः पूर्ति निधि बनाने हेतु प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन प्रस्तावित निधि नहीं बनाई गई। इस

कारण रिकार्ड में भी नहीं था और लेखापरीक्षा दल के बारम्बार आग्रह के बावजूद भी उन्हें कोई ठोस कारण नहीं बताए गए।

6.1.5 परियोजना को बीच में रोकना

अगस्त 2011 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण में हो रही कठिनाइयों की वजह से नाको ने इस कार्यक्रम को बीच में रोक दिया और इस परियोजना को कंडोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम (कं.सा.वि.का.) के साथ मिला दिए जाने का प्रस्ताव किया गया। कुल 6499 मशीनें, जो सितम्बर 2011 तक कार्य कर रही थी, सा.वि.सं. को सौंपा जाना था जो कं.सा.वि.का. को छः राज्यों में क्रियान्वित कर रहे थे साथ ही कुछ मशीनों को हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. द्वारा नये स्थानों पर स्थापित करना था। मशीनों को सौंपे जाने एवं विस्थापन की प्रक्रिया हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. द्वारा सभी संबंधित राज्यों में पूरी कर ली गई थी, सिवाय पश्चिम बंगाल में जहां कि वर्तमान सा.वि.सं. ने इन मशीनों को लेने से इंकार कर दिया था। इसलिए हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. को पश्चिम बंगाल में मौजूद 794 कं.वें.म. की देखभाल एवं उसके कार्यान्वयन को ₹ 50,000 प्रतिमाह के दर से दिसम्बर 2012 तक जारी रखने के लिए कहा गया। अक्तूबर 2011 से जून 2012 तक ₹ 50,000 प्रतिमाह के दर से हि.लै.प.नि.प्रो.न्या. को भुगतान किया गया।

6.1.6 निष्कर्ष

नाको द्वारा शुरू किए गए कं.वें.म. योजना उसके खराब योजना और क्रियान्वयन को प्रदर्शित करता है। मंत्रालय ने इस पर कोई विस्तृत व्यवहारिक अध्ययन नहीं करवाया। किसी वैध लिखित समझौते के अभाव में, कं.वें.म. के सुरक्षा एवं उसके देखभाल से संबंधित मामलों का संज्ञान नहीं लिया गया। परिणामतः यह परियोजना नाको द्वारा बीच में ही बंद कर दी गई।

कं.वें.म. द्वारा कंडोमों की बिक्री नाको द्वारा दर्शाई गई संख्या के हिसाब से काफी कम थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में कं.वें.म. द्वारा कंडोमों की उपलब्धतता में सुधार करना था, को पूर्ण नहीं किया जा सका, जबकि इस कार्यक्रम पर ₹ 21.54 करोड़ का व्यय किया गया। मंत्रालय द्वारा पहले से स्थापित कं.वें.म. की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल किए बिना चरण-II के लिए जल्दबाजी में निधियों को जारी करना अनुचित था।

इस मामले के बारे में मंत्रालय को मार्च 2013 में सूचित किया गया। जून 2013 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

6.2 प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

6.2.1 प्रस्तावना

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (प्र.मं.स्वा.सु.यो.) की घोषणा (अगस्त 2003), देश में सस्ती/विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों में सुधार तथा गुणात्मक चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं में संवर्धन के उद्देश्य से की गई थी। आगामी तीन वर्षों में पिछड़े राज्यों में, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस छः नये अस्पतालों की स्थापना प्रस्तावित थी।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (आ.मा.मं.स.) ने प्र.मं.स्वा.सु.यो. के प्रथम चरण को दो घटकों, अर्थात् (i) छः एम्स सदृश (ए.ल.) संस्थानों[2] की स्थापना तथा (ii) 13 चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन, की संस्वीकृति (मार्च 2006/जून 2006) दी थी। प्र.मं.स्वा.सु.यो. का चरण-II में दो अतिरिक्त राज्यों[3] में ए.एल. संस्थानों की स्थापना तथा छः अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन प्रस्तावित (फरवरी 2009) था। प्र.मं.स्वा.सु.यो. के चरण-I की अनुमानित लागत फरवरी 2010 में ₹ 9307 करोड़ थी। योजना के अंतर्गत बजट तथा व्यय नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		बचत	बचत % में	पूंजी		बचत	बचत % में
	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय			बजट आवंटन	वास्तविक व्यय		
2004-05	60	6.16	53.84	89.73	-	-	-	-
2005-06	250	2.52	247.48	98.99	-	-	-	-
2006-07	75	6.27	68.73	91.64	-	-	-	-
2007-08	150	87.49	62.51	41.67	-	-	-	-
2008-09	50	33.46	16.54	33.08	440	450.54	-	-
2009-10	148	12.67	135.33	91.44	1300	461.81	838.19	64.48
2010-11	50	21.54	28.46	56.92	700	632.30	67.70	9.67
2011-12	55.94	42.29	13.65	24.40	1560.63	834.81	725.82	46.51

6.2.2 स्थिति

30 जून 2012 तक प्र.मं.स्वा.सु.यो. चरण-I की स्थिति दर्शाती हुई छः ए.एल. संस्थानों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नीचे दी गयी है:

[2] बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल) ओडिशा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) तथा उत्तराखण्ड (ऋषिकेश)

[3] उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

(₹ करोड़ में)

एम्स की परियोजना	आवासीय परिसर एवं अन्य चार पैकेजों के निर्माण हेतु कुल निविदाकृत लागत	% में भौतिक प्रगति				
		आवासीय परिसर का निर्माण	चिकित्सा महाविद्यालय का पैकेज-I निर्माण	अस्पताल परिसर एवं एच.वी.ए.सी. का पैकेज-II निर्माण	पैकेज-III विद्युतीय सेवाएं	पैकेज-IV संपदा सेवा
भोपाल	521.26	92.30	74.30	46.10	7.88	5.35
भुवनेश्वर	531.00	21.00	72.52	55.19	2.15	शून्य
जोधपुर	389.50	100.00	76.00	68.00	20.00	शून्य
पटना	583.83	99.20	83.50	43.90	48.17	5.73
रायपुर	512.54	100.00	49.21	43.92	34.30	2.13
ऋषिकेश	490.41	93.10	63.17	69.03	30.00	शून्य
	3028.54	68.39	70.86	53.73	22.13	4.32

6.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

योजना के चरण-I के अंतर्गत शामिल छः ए.एल. संस्थानों के निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए सलाहकारों तथा ठेकेदारों के चयन प्रक्रिया तथा उन्हें किये गये भुगतानों की लेखापरीक्षा जून-अगस्त 2012 के दौरान की गयी थी। निष्कर्षों की आने वाले पैराओं में विवेचना की गई है।

6.2.3.1 परियोजना सलाहकार के चयन में अनियमितता

मंत्रालय ने अपने सलाहकार[4] के माध्यम से, प्र.मं.स्वा.सु.यो. के अंतर्गत अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालय परिसर के निर्माण हेतु परियोजना सलाहकारों की नियुक्ति हेतु 'अभिव्यक्ति की अभिरूचि (अ.अ.)' आमंत्रित की (अगस्त 2007) थी। अभिव्यक्ति की अभिरूचि में प्रत्याशित बोलीदाताओं के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (प्र.हे.अ.) को जारी करने के अर्हता मापदण्ड सम्मिलित थे। अ.अ. का पैरा 16 निर्धारित करता है कि तय समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

जवाब में, 14 फर्मों ने अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा ने पाया कि इनमें से, चार फर्मों के पास पर्याप्त परियोजना अनुभव नहीं था जबकि तीन फर्मों (मैसर्स एस.एम.ई.सी. सहित) ने तय समय-सीमा के बाद आवेदन किया था। इस प्रकार, केवल

[4] आंतरिक सलाहकार के रूप में, हि.लै.लि. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से विभिन्न कार्यकलाप सेवाओं अर्थात् कार्यान्वयन गतिविधियों के समन्वय, संपर्क, मॉनीटर करने, बोली प्रक्रिया प्रबंधन को शुरू करने, सलाहकारों को भुगतान करने, राज्य सरकारों आदि से समन्वय करने को प्रतिपादित करता है।

सात संस्थाएं ही प्रस्ताव हेतु अनुरोध को जारी करने के लिए योग्य थीं। तथापि, अ.अ. का मूल्यांकन करने के बाद, दिसम्बर 2007 में, हि.लै.लि. ने 13 चुनी गयी फर्मों (तकनीकी रूप से अयोग्य चार फर्म तथा दो फर्म, जिन्होंने अपने आवेदन देर से भेजे, को सम्मिलित करते हुए) को प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया (दिसम्बर 2007)। बाद में, प्र.हे.अ. बोलियों के मूल्यांकन के बाद, चार सफल फर्मों (अप्रैल 2008) को छः ए.एल. संस्थाओं (अप्रैल 2008) के परियोजना सलाहकार के रूप में चुना गया था। मैसर्स एस.एम.ई.सी. को एम्स, ऋषिकेश के लिए परियोजना सलाहकार के रूप में ₹ 5.18 करोड़ की लागत पर चुना गया था। अप्रैल 2012 तक के लिए परामर्श शुल्क के रूप में फर्म को ₹ 2.17 करोड़ की अदायगी की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स एल.एम.ई.सी., अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अनुसार प्र.हे.अ. जारी करने के योग्य नहीं था। इस प्रकार परियोजना सलाहकार के रूप में फर्म का चयन अ.अ. की अनुपालना में नहीं था, और परिणामतः फर्म को ₹ 2.17 करोड़ के अनियमित भुगतान का कारण बना।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि हि.लै.लि. ने वृहत भागीदारी तथा बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए अ.अ. की विलंबित प्रस्तुति को स्वीकृत किया होगा।

उत्तर अ.अ. प्रलेख के पैरा 16 के अनुसार असंगत था, जो प्रावधान करता था कि तय समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बोलियों की प्राप्ति के पश्चात, मंत्रालय ने भी अपने सितम्बर 2007 के पत्र द्वारा मैसर्स हि.लै.लि. का ध्यान अ.अ. के इस प्रावधान की ओर आकर्षित किया था।

6.2.3.2 अस्पताल परिसर के सिविल कार्यों के लिए बढ़े हुए शुल्कों पर अनियमित व्यय

मंत्रालय ने चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अस्पातल परिसर हेतु सिविल कार्यों को भी दो अलग पैकेजों में करने का निर्णय लिया था (अगस्त 2009)। विद्युत कार्यों को दो पैकेजों, यथा (i) उप-स्टेशन, अ.ऊ.आ., डी.जी. सेट आदि, तथा (ii) एच.वी.ए.सी. एवं बी.एम.एस.[5] आदि, में विभाजित करने का निर्णय लिया गया था।

सिविल पैकेज-II यथा अस्पताल परिसर के संदर्भ में तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, मंत्रालय ने निश्चित किया कि एच.वी.ए.सी. कार्य तथा बी.एम.एस. को पैकेज-II के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त कार्य-क्षेत्र के

[5] उत्तापक, वायु-संचार तथा वातानुकूलन (उ.वा.वा.), भवन प्रबंधन प्रणाली (भ.प्र.प्र)

साथ संशोधित वित्तीय बोलियां आमंत्रित की गयी थीं। तथापि, पैकेज-II हेतु वित्तीय मूल्यांकन के दौरान यह देखा गया कि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दर प्रत्येक परियोजना हेतु प्राक्कलित लागत की तुलना में अनुचित रूप से अधिक थी। तदनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (स्वा.प.क.मं.) की संस्वीकृति से पैकेज-II हेतु निविदाओं को रद्द करने तथा नई बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय (मई 2010) लिया गया था। तदुपरांत, स्वा.प.क.मं. ने मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया कि "एच.वी.ए.सी. तथा बी.एम.एस. कार्य को छोड़कर सामग्री तथा श्रम हेतु वृद्धि उपधारा को निविदा में के.लो.नि.वि. के प्रतिमान के अनुसार ठेकेदारों को वास्तविक मूल्य वृद्धि के अनुसार ठीक भुगतान करने के लिए सम्मिलित किया जा सकता है।"

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 मई 2010 को जारी आगामी प्र.हे.अ. स्पष्टतः उल्लेख करता है कि वृद्धि उपधारा एच.वी.ए.सी. एवं बी.एम.एस. कार्यों[6] के लिए लागू नहीं होगा। तथापि, जून 2010 में आयोजित बोली-पूर्व सम्मेलन के बाद मंत्रालय ने निश्चित किया कि "उ.वा.वा. कार्यों के लिए वृद्धि का भुगतान के.लो.नि.वि. जी.जी.सी. के उपधारा 10 सी सी के अनुसार किया जाएगा।" लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इस मुद्दे की प्रत्याशित बोलीदाताओं द्वारा बोली-पूर्व सम्मेलन में नहीं उठाया गया था। अतः बोली-पूर्व सम्मेलन के पश्चात स्वा.प.क.मं. की संस्वीकृति लिये बगैर निविदा प्रलेख में इस प्रभाव का संशोधन अनियमित था। अंततः पैकेज-II के लिए ठेके जुलाई 2010 में दिये गये और जैसाकि **(अनुबंध-2)** में वर्णित है, उ.वा.वा. तथा भ.प्र.प्र. कार्य हेतु वृद्धि उपधारा पर ₹ 1.56 करोड़ का व्यय, स्वा.प.क.मं. के विनिर्दिष्ट आदेशों के विरूद्ध किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि 21 जून 2010 को आयोजित बोली-पूर्व सम्मेलन के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा उ.वा.वा. कार्य के लिए संशोधन किये गये थे।

हांलाकि, उत्तर स्वा.प.क.मं. के निर्धारित आदेशों के गैर-अनुपालना के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा प्रत्याशित बोलीदाताओं द्वारा उठाये गये प्रश्नों का हिस्सा नहीं था।

---

[6] मूल्यों/परिश्रमिकों के बढ़ने/घटने के कारण भुगतान से संबंधित प्र.हे.अ./जी.सी.सी. की उपधारा 10 सी.सी.

6.2.3.3 अभिप्रेरण अग्रिम को अनुचित रूप से जारी करना

के.लो.नि.वि. निर्माण नियमावली की धारा 32.5 तथा अनुबंध की सामान्य शर्तों (अ.सा.श.) की उपधारा 10 ख (II) के अनुसार, मंत्रालय द्वारा विभिन्न ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंध में अभिप्रेरण अग्रिम (अ.अ.) निविदा मूल्य के 10% से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। हांलाकि, इस निवेदन को ठेकेदार द्वारा कार्य को शुरू करने के आदेश के एक माह के भीतर किया जाना था। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों के साथ किए गए नए अनुबंध की सामान्य शर्तों की उपधारा 10 ख V के अनुसार, 'यदि प्रभारी अभियंता द्वारा परिस्थितियों को उचित समझा जाता है, तब प्रभारी अभियन्ता के विवेक पर एक माह की अवधि को बढ़ाया जा सकता है'। इसके अतिरिक्त, के.लो.नि.वि. निर्माण नियमावली का पैरा 32.5(ii) के अनुसार अग्रिम को दो से कम किस्तों में जारी नहीं करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने निम्न तीन मामलों में ₹ 8.32 करोड़ के अभिप्रेरण अग्रिम का अनुचित निर्गम पाया जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	जारी की गई अ.अ. राशि (₹करोड़ में)	टिप्पणी
1.	एम्स, भुवनेश्वर में आवासीय परिसर	मैसर्स आर.डी.बी. रियल्टी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	4.89	के.लो.नि.वि. नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए मंत्रालय ने एक किस्त में ₹ 48.86 करोड़ के निविदा मूल्य की 10 *प्रतिशत* की दर पर अ.अ. जारी किया था।
2.	एम्स भोपाल में आवासीय परिसर	मैसर्स कुमार कोलोनाइजर्स एवं कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1.18	परियोजना सलाहकार (हि.लै.लि.) ने अनुबंध की सामान्य शर्तों का उल्लंघन करते हुए अ.अ. के अनुदान हेतु अवधि बढ़ा दी थी। इसके अतिरिक्त, हि.लै.लि. द्वारा प्रस्तुत तर्क कि कार्य की शुरूआत करने के लिए अ.अ. की आवश्कता थी, यह गलत था क्योंकि कार्य पहले से ही प्रगति पर था।
3.	एम्स, पटना में आवासीय परिसर	मैसर्स आर.डी.बी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2.25	निर्धारित अवधि के बीत जाने के पश्चात मैसर्स हि.लै.लि. द्वारा अ.अ. जारी किया गया था। हांलाकि, तथ्य को मंत्रालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि एम्स, भुवनेश्वर के आवासीय परिसर के मामले में, मैसर्स हॉस्पीटल सर्विस कन्सल्टेन्सी कोर्पोरेशन (हॉ.स.कं.को.) ने अभिकरण को अ.अ. जारी

नहीं किया था तथा एम्स, भोपाल एवं पटना के आवासीय परिसर के मामले में, अ.अ. की पूर्ण रूप से वसूली हो चुकी है।

हांलाकि, यह उत्तर निर्धारित प्रावधानों के प्रतिकूल मंत्रालय द्वारा अ.अ. के अनियमित अनुदान के मुद्दे को शामिल नहीं करता है।

6.2.3.4 आंतरिक सलाहकार को ₹ 25.20 लाख का अतिरिक्त भुगतान

मंत्रालय ने पूर्व प्रभाव से मार्च 2007 से, हि.लै.लि. के साथ अनुबंध किया (अगस्त 2008)। अनुबंध के पैरा 4.5 के अनुसार, विज्ञापन प्रभार, कानूनी व्यय एवं बीमा के अनुरक्षण हेतु भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम के वास्तविक व्यय, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रभार, सुरक्षा व्यवस्थाओं हेतु भुगतान, स्थलों पर परियोजना प्रकोष्ठ चलाने के लिए माल संबंधी व्यय की मंत्रालय द्वारा वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर होने से पूर्व उप-परामर्श कार्य हेतु, क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी हेतु तथा दस्तावेज एवं अन्य विविध व्यय के प्रति शुल्क के रूप में मंत्रालय ने मैसर्स हि.लै.लि. को ₹ 25.20 लाख के व्यय की प्रतिपूर्ति की थी। इसके अतिरिक्त, हि.लै.लि. को किया गया भुगतान अनुबंध में शामिल नहीं था। इस प्रकार, हि.लै.लि. को ₹ 25.20 का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि परामर्श कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर होने से पूर्व ही मैसर्स हि.लै.लि. को भुगतान कर दिया गया था जो कि परियोजना पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए किया गया था।

तथ्य यह है कि भुगतान, अनुबंध के प्रावधान जिन्हें पूर्व प्रभाव से प्रदान किया गया था, के अंतर्गत शामिल नहीं था।

6.2.4 अन्य अनियमितताएं

- सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अंतर्गत, आधिक्य व्यय, विशेष रूप से यदि वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में किया जाए, तब इसे वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि सा.वि.नि. के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मंत्रालय ने 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान अग्रिम के रूप में मार्च के महीनों के दौरान सलाहकारों/ठेकेदारों को कुल ₹ 81.62 करोड़ की पर्याप्त निधियां जारी की थीं।

❖ मंत्रालय ने (अक्तूबर 2007) ऋषिकेश एवं पटना स्थलों के ए.एल. संस्थानों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण हेतु परामर्श कार्य मैसर्स हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड (हि.लै.लि.) को तथा भुवनेश्वर एवं रायपुर स्थलों हेतु मैसर्स हॉस्पीटल सर्विसिज कंसल्टेंसी कोरपोरेशन लिमिटेड (हॉ.स.कं.को.लि.) को सौंपा था। मंत्रालय एवं हि.लै.लि./हॉ.स.कं.को.लि. के बीच हुए अनुबंध समझौते में परियोजना की वास्तविक प्रगति के आधार पर परियोजना सलाहकारों के माध्यम से ठेकेदारों को कार्य के निष्पादन के अनुसार भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय, कार्य की वास्तविक प्रगति की बजाय तिमाही आधार पर उनकी अनुमानित निधि आवश्यकताओं के आधार पर हि.लै.लि./हॉ.स.कं.को.लि. को निधि जारी कर रहा था। बदले में, सलाहकार कार्यों की वास्तविक प्रगति के आधार पर संबंधित ठेकेदारों को निधियां जारी कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप सलाहकारों के पास निधियाँ अवरूद्ध हुई।

इसके अतिरिक्त, इन अनुबंधों की उपधारा 10.6 के अनुसार 'सलाहकार द्वारा भारत सरकार से लिया गया अग्रिम/प्राप्त जमा पर अर्जित ब्याज को, भारत सरकार से लिए गए अग्रिम/प्राप्त जमा में जोड़ा जाना चाहिए।' हांलाकि, मंत्रालय ने सलाहकारों द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने पास रखी हुई निधियों पर कमाए गए ब्याज का कोई मूल्यांकन नहीं किया था। नवम्बर 2008 से मार्च 2010 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 1 से लेकर 166 दिनों तक की अवधि हेतु सलाहकारों (हि.लै.लि. एवं हॉ.स.कं.को.लि.) के पास ₹ 0.57 करोड़ से लेकर ₹ 16.66 करोड़ की निधियां अवरूद्ध पड़ी हुई थीं। इससे ₹ 2.72 करोड़[7] ब्याज का प्रभाव पड़ा **(अनुबंध-3)**।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि सलाहकारों को जारी की गई निधियों पर अर्जित ब्याज का हिसाब रखा जा रहा था तथा अंतिम भुगतान के समय समायोजित किया जाएगा।

यह उत्तर सलाहकारों के पास निष्पादन हेतु अतिरिक्त निधियों को रखे जाने की आवश्यकता को स्पष्ट नहीं करता।

❖ अनुबंध की उपधारा 3.6 के अनुसार, सलाहकार मैसर्स हि.लै.लि. अनुबंध पर हस्ताक्षर के एक माह के भीतर ₹ 12 करोड़ के परामर्श कार्य प्रभारों के 5 *प्रतिशत* के बराबर निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स

[7] 2011-12 के दौरान केन्द्र सरकार के उधार (7.9 *प्रतिशत*) का औसत लागत के आधार पर

हि.लै.लि. ने शुरू में 27 सितम्बर 2008 से 03 अक्तूबर 2011 की अवधि को आवृत्त करते हुए ₹ 60 लाख की निष्पादन गारंटी प्रस्तुत की थी, तथा फर्म से ₹ 87.05 लाख (मैसर्स हि.लै.लि. को भुगतान की गई कुल राशि ₹ 17.41 करोड़ का 5%) के लिए कोई नई गारंटी प्राप्त नहीं हुई थी।

परियोजना सलाहकारों के चयन में कमियां तथा सलाहकारों एवं ठेकेदारों की भुगतान प्रक्रियाएं जैसा कि ऊपर बताया गया है, दर्शाता है कि मंत्रालय ने परियोजना को कार्यान्वित करने में पर्याप्त यथोचित परिश्रम नहीं किया था। लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मंत्रालय द्वारा तुरंत ध्यान देने एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

6.3 के.स.स्वा.यो. के एलोपैथिक दवाईयों का प्रापण

6.3.1 प्रस्तावना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय) "केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना" (के.स.स्वा.यो.) के माध्यम से दिल्ली रा.रा.क्षे. से अलग के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत आवृत 23 शहरों में रह रहे केन्द्र सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनरों तथा उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करता है। पूरे देश में 250 के.स.स्वा.यो. स्वास्थ्य केन्द्र (पहले औषधालय कहे जाते थे) के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

चिकित्सा भण्डार संगठन (चि.भ.सं.) को के.स.स्वा.यो. अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु अपेक्षित दवाईयों एवं औषधियों के प्रापण का कार्य सौंपा गया है। चि.भ.सं. सात चिकित्सा भण्डार डिपो (चि.भ.डि.)[8] के माध्यम से काम करता है। राजकीय चिकित्सा भण्डार डिपो (रा.चि.भ.डि.), दिल्ली दिल्ली में सभी के.स.स्वा.यो. स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए दवाईयों के प्रापण, भण्डारण तथा संवितरण हेतु एक नोडल केन्द्र है।

6.3.1.1 संगठनात्मक ढांचा

के.स.स्वा.यो. के प्रमुख, निदेशक के.स.स्वा.यो. होते हैं। अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) चि.भ.डि. दिल्ली तथा के.स.स्वा.यो. के चार क्षेत्रिय कार्यालयों के प्रशासनिक अध्यक्ष है। क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के के.स.स्वा.यो. स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करते हैं तथा वह के.स.स्वा.यो. स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा की गई स्थानीय खरीद से संबंधित बिलों को संसाधित करने तथा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है। दिल्ली से बाहर के शहरों में, के.स.स्वा.यो. के प्रमुख संयुक्त/अतिरिक्त निदेशक होता है जो के.स.स्वा.यो. इकाईयों पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण रखता है तथा औषधि के आपूर्तिकर्ताओं को उनके बिलों के प्रति भुगतान को प्राधिकृत करता है।

[8] मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, हैदराबाद, गुवाहटी, करनाल तथा नई दिल्ली।

6.3.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

लेखापरीक्षा में 2009-10 से 2011-12 के दौरान दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, चण्डीगढ़, भोपाल, जबलपुर, कोलकाता, चैन्नई, तिरूवनन्तपुरम, हैदराबाद, बैंगलोर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर तथा मुम्बई में चिकित्सा भण्डार डिपो तथा के.स.स्वा.यो. स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा के.स.स्वा.यो. में एलोपैथी दवाईयों के प्रापण की संवीक्षा शामिल की गई है।

दिल्ली में, चिकित्सा भण्डार संगठन (चि.भ.सं.), चि.भ.डि. के कार्यालयों तथा मंत्रालय में संबंधित अभिलेखों की जांच की गई थी। दिल्ली से बाहर के शहरों में संबंधित अभिलेखों की जांच संबंधित संयुक्त/अतिरिक्त निदेशक के.स.स्वा.यो., केन्द्रीय चिकित्सा भण्डारों/चिकित्सा भण्डार डिपो के कार्यालयों तथा के.स.स्वा.यो. केन्द्रों पर की गई थी।

6.3.2 के.स.स्वा.यो. में दवाईयों के प्रापण पर व्यय

2009 से 2012 की अवधि के लिए के.स.स्वा.यो. हेतु दवाईयों के प्रापण पर मंत्रालय द्वारा किया कुल व्यय नीचे तालिका में दिया गया है:

दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर के.स.स्वा.यो. में दवाईयों के प्रापण पर कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	योग
के.स.स्वा.यो. दिल्ली	328.15	387.28	326.92	**1042.35**
दिल्ली के बाहर* के.स.स्वा.यो.	200.40	232.83	270.00	**703.23**

6.3.3 के.स.स्वा.यो. में दवाईयों की प्रापण प्रणाली

मंत्रालय सरकारी अस्पतालों, चिकित्सा भण्डार संगठनों तथा के.स.स्वा.यो. हेतु ब्रांडड तथा प्रजातिगत दवाईयों के लिए अलग-अलग से दवाई फार्मूलरी कही जाने वाली दवाईयों की एक सूची का अनुरक्षण करता है। 31 मार्च 2012 को प्रजातिगत फार्मूलरी 1128 दवाईयाँ तथा ब्रांडड फार्मूलरी में 622 दवाईयाँ थी।

प्रजातिगत तथा ब्रांडड दवाईयां

प्रजातिगत दवा को इस रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दवा विज्ञापन के बिना इसके रसायनिक नाम के तहत बेची जाती है, इसलिए प्रजातिगत दवाईयों को ब्रांडड से अलग संघटक दवा के नाम के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।

* दिल्ली से बाहर के के.स.स्वा.यो. में शामिल 23 शहरों में व्यय

ब्रांडड दवाईयां एक औषधीय कम्पनी द्वारा एक मार्का - संरक्षित नाम के तहत बेची गई एक दवा/औषधि-मिश्रण है।

दवा फार्मूलरी एक समिति[9] द्वारा तैयार की जाती है जिसमें, साथ-साथ, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर शामिल हैं। मंत्रालय फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवाईयों की दरों को अंतिम रूप देता है। ये दवाईयां के.स.स्वा.यो. को आपूर्ति से पहले प्रयोगशाला में अनिवार्य जांच के अधीन हैं। दिल्ली में, के.स.स्वा.यो. स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु फार्मूलरी दवाईयों/औषधियों के प्रापण के उत्तरदायित्व के लिए मैसर्स हॉस्पीटल सर्विसिस कंसलटेंसी कोपोरेशन लि. (हॉ.स.कं.को.लि.) को आउटसोर्स कर दी गई है। प्रत्येक वर्ष, चि.भ.डि. एक प्रबंधन समिति का गठन करता है, जिसमें चि.भ.डि. के चार क्षेत्रों के क्षेत्राध्यक्ष शामिल होते हैं, जो के.स.स्वा.यो. हेतु बैंडड तथा प्रजातिगत दवा के वार्षिक प्रमात्रा की आवश्यकता को निर्धारित करती है। चि.भ.डि. को औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित आवश्यकता को हॉ.स.कं.का. को भेजा जाता है।

दवाईयों जो फार्मूलरी में सूचीबद्ध नहीं है, की स्थानीय खरीद हेतु चि.भ.डि. दिल्ली स्थानीय औषध विक्रेताओं की नामसूची तैयार करता है तथा औषध विक्रेताओं के साथ मोल भाव के पश्चात दवाईयों के अधिकतम क्रम मूल्य (अ.क्र.मू.) पर छूट की दरें निर्धारित करता है। इसी प्रकार, दिल्ली से बाहर के शहरों में, के.स.स्वा.यो. इकाईयों के संबंधित अध्यक्ष स्थानीय कैमिस्टों की नामसूची तैयार करता है।

के.स.स्वा.यो. डाक्टरों की प्रेसक्रिप्शन पर, प्रयोगशाला जांच अथवा अन्य किसी सत्यापन के दैनिक आधार पर फार्मूलरी से बाहर की दवाईयां खरीदता है।

6.3.4 पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा संसदीय समिति की रिपोर्ट

2006-07 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन औषधियों तथा चिकित्सा उपकरणों के प्रापण की एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। संबंधित निष्कर्षों को नवम्बर 2007 में संसद में प्रस्तुत 2007 का प्रतिवेदन सं. 20 में प्रस्तुत किया गया था।

प्रतिवेदन में साथ-साथ दवाईयों की स्थानीय खरीद और ऐसे प्रापणों में अनियमितताओं के बड़े विस्तार पर भी चर्चा की गई थी।

[9] संयुक्त सचिव (अध्यक्ष), चिकित्सा अधीक्षक, तथा अ.भा.अ.वि.सं. एवं रा.म.लो.अस्पताल का वि.अ. औषधी, निदेशक अ.भा.अ.वि.सं.,पी.जी.आई.एम.ई.आर. चण्डीगढ़ तथा जे.पी.एम.ई.आर. पांडिचेरी से मनोनीत, अतिरिक्त अ.नि. भण्डार (चि.भ.डि.) तथा अतिरिक्त निदेशक (मु.) के.स.स्वा.यो.

लोक लेखा समिति ने विषय को विस्तृत जांच हेतु उठाया। इस विषय पर अपने प्रतिवेदन (प्रन्द्रहवीं लोक सभा का चौबीसवां प्रतिवेदन) में समिति ने डाक्टरों के प्रेसक्रिप्शन पेटर्न, जो दवाईयों की स्थानीय खरीद के बड़े विस्तार का कारण बना, पर चिंता व्यक्त की है। समिति ने मंत्रालय को औषधियों की अनावश्यक स्थानीय खरीद से बचने हेतु उपाय करने की सलाह दी।

मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में बताया कि स्थानीय खरीद के विस्तार को कम करने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

आगे, संसदीय समिति[10] ने अगस्त 2010 में संसद को प्रस्तुत अपनी 45वें प्रतिवेदन में पाया कि दवाईयों के कई ब्रांडों के वर्तमान मूल्य उनकी लागत से बिना किसी संबंध के काफी अधिक बढ़ गए थे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया हैः

ब्रांड का नाम	उत्पादक का नाम	दवा संघटन	10 गोलियों का मूल्य
ओर्थोबिड	एबोट हेल्थ केयर प्राई.लि.	नीमूलाईड 100 मि.ग्रा.	29.19
नीमोलिड	पैनएशिया बायोटेक	नीमूलाईड 100 मि.ग्रा.	38.72
नीसिप	सिपला लिमिटेड	नीमूलाईड 100 मि.ग्रा.	21.00
नाईस	डा. रेड्डी लेबोरेट्री	नीमूलाईड 100 मि.ग्रा.	48.00

संसदीय समिति ने पाया कि नामूलाईड की 10 गोलियों के एक पत्ते की उत्पादन लागत ₹1.40 से अधिक नहीं थी। यह सुस्पष्ट था कि दवा कम्पनियों तथा व्यापारियों दोनों द्वारा काफी अधिक गुंजाइश रखी जा रही है। ऐसे मूल्य प्रभावों के कई उदाहरण होगें।

संसदीय समिति ने यह भी पाया कि डाक्टरों को स्वास्थ्य देखभाल उद्योग से किसी भी प्रकार के उपहार, आतिथ्य, विदेशी एवं घरेलू स्थान का भ्रमण आदि को स्वीकार करने से रोकने वाली दिसम्बर 2009 में शामिल भारतीय चिकित्सा परिषद में नीति संहिता होने के बावजूद इस खराब प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है तथा औषधी कम्पनियों ने कई डॉक्टरों के विदेश भ्रमण का खर्च उठाने तथा प्रदेष्टाओं जो महंगी दवाईयों की सलाह देते हैं को प्रतिकार के रूप में एयर कंडिशनर, कार, म्यूजिक सिस्टम, सोने की चेन आदि जैसे उच्च मूल्यों के उपहार से आभार प्रकट करना जारी रखा।

वर्तमान लेखापरीक्षा के.स.स्वा.यो. में एलोपैथिक दवाईयों के प्रापण की प्रणाली की जांच करने का प्रयत्न करती है।

---

[10] प्रजातिगत, प्रजातिगत ब्रांडड तथा ब्रांडड औषधियों की उपलब्धता से संबंधित मामले पर संसदीय स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन, पैरा 30 तथा 31

6.3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

दवा फार्मूलरी का उद्देश्य अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों के उपचार हेतु आमतौर पर आवश्यक दवाईयों की पहचान करना है। यह फार्मूलरी डाक्टरों को इन दवाईयों के अन्तर्गत उपचार नियम को नियंत्रित करने तथा अन्य दवाईयों की स्थानीय खरीद के विस्तार को कम करने में सहायता करती है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.3.6 ब्रांडड दवाईयों हेतु दवा फार्मूलरी तैयार करना/संशोधन

मंत्रालय ने ब्रांडड दवाईयों हेतु वर्तमान दवा फार्मूलरी को तैयार करने/संशोधन हेतु एक समिति[11] गठित की (सितम्बर 2008)। समिति ने उन दवाईयों, जिनका सामान्यतया 2008 के दौरान के.स.स्वा.यो., दिल्ली में स्थानीय खरीद के माध्यम से प्रापण किया गया था, की पहचान करके फार्मूलरी में नई मदों को शामिल करने का निर्णय लिया। विभिन्न दवाईयों का समावेश आगे वैध दवा लाइसेंस, चि.भ.सं. में उत्पादनकर्ता फर्म के पंजीकरण के तहत था। परिणामस्वरूप, समिति ने मौजूदा 350 दवाईयों के अतिरिक्त 382 अन्य दवाईयों को शामिल करने की सिफारिश की (दिसम्बर 2009)। बाद में, सितम्बर 2010 में संशोधित फार्मूलरी मे कुल 622 दवाईयों को अधिसूचित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समिति ने फार्मूलरी में शामिल करने हेतु दवाईयों का चयन करते समय आमतौर पर सलाह दिए गए दवा संघटक का चयन करने के बजाए आमतौर पर सलाह दिए जाने वाले दवाईयों के ब्रांड को चुना। इस प्रकार, समिति द्वारा चुना गया विधि तंत्र डाक्टरों द्वारा विशिष्ट ब्रांडों के प्रेसक्रिप्शन पर मुख्य रूप से आधारित था। दवा संघटन पद्धति को चुन कर मदों का चयन कई विकल्प प्रदान कर सकता था जो लागत प्रभावी होते क्योंकि उसी दवा संघटन के कई ब्रांड बाजार मे विभिन्न दरों पर उपलब्ध थे।

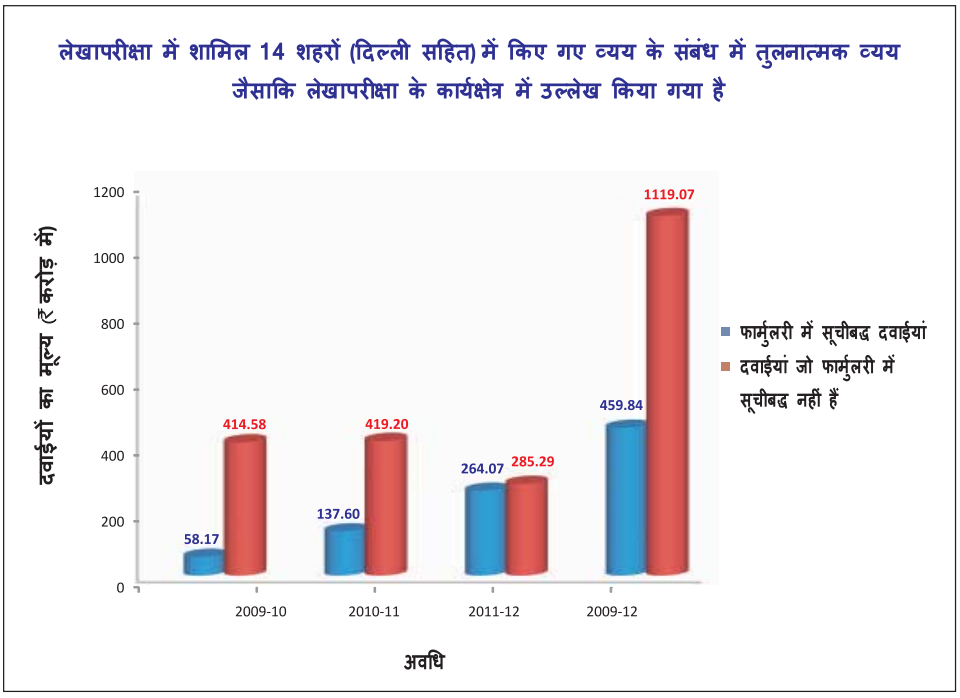
ब्रांड दवा फार्मूलरी में 21 मामलों की नमूना जांच ने दवाईयों की एक ही श्रेणी में कुछ कम लागत के ब्रांडों की उपलब्धता को प्रकट किया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि चयनित ब्रांड का छूट मूल्य भी बाजार में उपलब्ध कम लागत के अन्य ब्रांड के अ.क्र.मू. से काफी अधिक था। लेखापरीक्षा ने इन 21 नमूना जांच किए ब्रांडों के मूल्यों की तुलना

[11] संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति अ.भा.अ.वि.सं. तथा रा.म.लो. अस्ताल के चिकित्सा अधीक्षक तथा वि.अ. औषधी, निदेशक अ.भा.अ.वि.सं., पी.जी.आई.एम.ई.आर. चण्डीगढ़ तथा जे.आई.पी.एम.ई. आर. पांडिचेरी से मनोनीत, अतिरिक्त म.नि. भण्डार (चि.भ.सं.) तथा अतिरिक्त निदेशक (मु.) के.स. स्वा.यो. से बनी है।

समान दवाईयों के अन्य ब्रांडों के साथ की तथा पाया कि के.स.स्वा.यो. दिल्ली ने उच्च मूल्य के ब्रांडों को चुन कर 2011-12 के दौरान ₹ 9.25 करोड़ परिहार्य व्यय किया **(अनुबंध-4)**।

6.3.7 फार्मूलरी में असूचीबद्ध दवाईयों का प्रापण

वर्ष 2009-12 के दौरान मंत्रालय द्वारा फार्मूलरी तथा गैर फार्मूलरी दवाईयों के प्रापण पर किया गया व्यय नीचे चार्ट में दिया गया है:



प्रापण प्रतिमान का विश्लेषण दर्शाता है कि 2009-10 से 2011-12 के दौरान, कुल व्यय के 71 *प्रतिशत* उन दवाईयों के प्रापण पर किया गया था जो फार्मूलरी में सूचीबद्ध नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, के.स.स्वा.यो. दिल्ली ने फार्मूलरी में से केवल 19 *प्रतिशत* मदों का प्रापण किया जबकि 81 *प्रतिशत* मदें फार्मूलरी के बाहर की थी जैसा कि ब्यौरा **अनुबंध-5** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने शामिल दिल्ली से बाहर के शहरों में, के.स.स्वा.यो. ने 2009-12 के दौरान कुल व्यय का लगभग 50 *प्रतिशत* फार्मूलरी के बाहर की दवाईयों के प्रापण पर किया।

लेखापरीक्षा ने फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवाईयों की स्वीकृत दरों का विश्लेषण किया तथा पाया कि 2011-12 के दौरान मंत्रालय इन दवाईयों के अधिकतम क्रय मूल्य पर 12 से 50 *प्रतिशत* के बीच छूट प्राप्त करने में समर्थ था। तुलना में, के.स.स्वा.यो. फार्मूलरी के बाहर की दवाईयों पर 10 *प्रतिशत* से 30 *प्रतिशत* के बीच छूट प्राप्त करने में समर्थ था।

इस प्रकार फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवाईयां वास्तविक रूप से सस्ती हैं। तथापि, लेखापरीक्षा इस कारण यथार्थ वित्तीय विवरण का निर्धारण करने में असमर्थ है क्योंकि गैर-फार्मूलरी दवाईयों की दरों का अनुरक्षण नहीं किया गया है तथा इसलिए वह तुलना के लिए उपलब्ध नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित घटकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो फार्मूलरी के बाहर की दवाईयों के प्रापण का कारण बनी।

(क) फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवाईयों की प्रापण दरों का गैर-निर्धारण

अच्छे किस्म की दवाईयों की सामयिक आपूर्ति हेतु एक अति महत्वपूर्ण घटकों में से एक, मंत्रालय द्वारा फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवाईयों की प्रापण दरों का शीघ्रता से निर्धारण है। लेखापरीक्षा ने पाया कि बड़ी संख्या में दवाईयों की दरें, विशेष रूप से 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान, मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं की गई थीं। विवरण नीचे दिए गए हैं:

फार्मूलरी	वर्ष	फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवा की कुल सं.	दवा जिसके लिए दरें निर्धारित की गई थी	दवा जिसके लिए दरें निर्धारित नहीं की गई थी	दवा की प्रतिशतता जिसके लिए दरें निर्धारित नहीं की गई थीं
ब्रांडड दवाईयां	2009-10	504	350	154	30.56 %
	2010-11	504	339	165	32.74 %
	2011-12	622	592	30	4.82 %

दवा नियंत्रक द्वारा मदों को पंजी से निकाला जाना, दवाईयों की दरों का विक्रेय न होना, रा.औ.मू.प्रा.[12] को अनदेखा करने हेतु फर्मों द्वारा दवा संघटन का बदला जाना विभिन्न दवाईयों की दरों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार, फार्मूलरी के अंतर्गत दवाईयों की दरों की अनुपलब्धता फार्मूलरी के बाहर से दवाईयों के प्रापण का कारण बन सकती है जो बदले में अतिरिक्त व्यय का कारण बनेगी जैसा पहले ही ऊपर के पैरा 6.3.7 में उल्लेख किया गया है।

(ख) अपर्याप्त तथा अपूर्ण दवा फार्मूलरी

लेखापरीक्षा ने पाया कि संसदीय समिति के प्रतिकूल अनुशंसाओं के बावजूद डाक्टरों ने फार्मूलरी से बाहर की दवा की सलाह देना जारी रखा। परिणमस्वरूप, 2009-12 के

[12] राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (रा.औ.मू.प्रा.) विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है तथा दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (द.मू.नि.आ.) के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। द.मू.नि.आ. सरकार द्वारा कुछ अनिवार्य दवाईयों का मूल्य निर्धारित करने तथा उनके सूत्रीकरण हेतु जारी एक आदेश है।

दौरान फार्मूलरी के बाहर से ₹ 1,119 करोड़ के मूल्यों की दवाईयां खरीदी गई थीं जैसा कि विवरण ऊपर के पैरा 6.3.7 में दिया गया है। तथ्य यह है कि 2009-12 के दौरान व्यय का 71 *प्रतिशत* फार्मूलरी से बाहर की दवाईयों पर किया गया था जो व्यापक बीमारियों/रोगों हेतु दवाईयों को शामिल करने के लिए दवा फार्मूलरी के अधिक व्यापक नहीं होने को इंगित करता है।

6.3.8 प्रजातिगत दवाईयों का प्रापण

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कई दवाईयों प्रजातिगत तथा ब्रांडड दोनों ही संस्करण में उपलब्ध है। प्रजातिगत दवाईयां ब्रांडड संस्करण से काफी सस्ती है।

निम्नलिखित उदाहरण विषय को स्पष्ट करेगें:

प्रजातिगत दवाईयां					ब्रांडड दवाईयां		
सामान्य नाम	क्षमता	प्रकार	पैक	मूल्य	ब्रांड	उत्पादक	मूल्य
नीमूलाईड	100मि.ग्रा.	गोली	10	2.70	नीमूलाईड	पैनेसिया बायोटेक	29.00
					नाईस	डा.रेड्डी लैब	32.00
एमिकासीन	100 मि.ग्रा. /2मि.ग्रा.	वीयाल	2 मि.ली. वीयाल	6.25	जाएसिन	जयडस केडिला	19.50
					एमक्सल	नीकोलस प्रीमल	15.10
स्रोत:www. janaushidhi.gov.in							

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्रांडड दवाईयों की संशोधित फार्मूलरी को स्वीकृत करते समय (सितम्बर 2010) डाक्टरों द्वारा प्रजातिगत संस्करण के बजाए ब्रांडड दवाईयों की सलाह देने पर गंभीर चिंता व्यक्त की तथा एक वर्ष के भीतर प्रेसक्रिप्शन तथा आपूर्तियों दोनों में प्रजातिगत दवाईयों की ओर पूर्ण परिवर्तन का निर्देश दिया था। प्रजातिगत दवाईयों को प्रोत्साहित करने के क्रम में मंत्रालय ने मई 2011 में अपनी प्रजातिगत दवा फार्मूलरी में 818 से 1128 दवाईयों तक संशोधित किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मंत्रालय ने प्रजातिगत फार्मूलरी में सूचीबद्ध अधिकांश दवाईयों के प्रापण दरों को अंतिम रूप नहीं दिया था जिसका नीचे विवरण दिया गया है:

फार्मूलरी	वर्ष	फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवा की कुल सं.	दवा जिसकी दरों को अंतिम रूप दिया गया	दवा जिनकी दरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया	दवाईयों की प्रतिशतता जिनकी दरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था
सामान्य दवाईयों	2009-10	818	264	554	67.73 %
	2010-11	818	127	691	84.47 %
	2011-12	1128	279	849	75.26 %

सामान्य दवाईयों की दरों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने का कारण मुख्य रूप से दवा उत्पादकों से अपर्याप्त उत्तर था।

परिणामस्वरूप, के.स.स्वा.यो. ने फार्मूलरी में सूचीबद्ध प्रजातिगत दवाईयों का केवल 2 से 55 *प्रतिशत* तक का प्रापण किया जैसा कि नीचे तालिका में विवरण दिया गया है :

लेखापरीक्षा में शामिल शहर का नाम	वर्ष	प्रजातिगत सूची से प्रापण की गई दवाईयों की प्रतिशतता
दिल्ली	2009-10	2.08
	2010-11	2.20
	2011-12	5.14
अहमदाबाद	2009-10	54.5
	2010-11	8.17
	2011-12	4.43
कोलकाता	2009-10	27.63
	2010-11	9.90
	2011-12	8.33
चैन्नई	2009-10	14.18
	2010-11	3.45
	2011-12	4.26
मुम्बई	2009-10	40.61
	2010-11	16.78
	2011-12	24.59
भुवनेश्वर	2009-10	6.80
	2010-11	6.80
	2011-12	5.07

इसके अतिरिक्त, 2009-12 के दौरान के.स.स्वा.यो.,दिल्ली ने प्रजातिगत दवाईयों के प्रापण पर केवल 0.19 *प्रतिशत* का व्यय किया।

नमूना जांच ने प्रकट किया कि ब्रांडड दवा फार्मूलरी हेतु चयनित 59 दवाईयां पहले से ही प्रजातिगत फार्मूलरी में सूचीबद्ध थी (**अनुबंध-6**)। इसके अतिरिक्त, जनेसिद्धि[13] योजना में प्रजातिगत दवाईयों की दरों के साथ 30 ब्रांडड दवाईयों की दरों की एक तुलना से स्पष्ट हुआ कि आगर ब्रांडड दवाईयों के स्थान पर प्रजातिगत दवाईयों को प्रापण किया गया होता तो 2011-12 के दौरान के.स.स्वा.यो. दिल्ली द्वारा ₹ 11.81 करोड़ की बचत की जा सकती थी। जैसा कि ब्यौरा (**अनुबंध-7**) में दिया गया है।

6.3.9 फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवाईयों के प्रापण में विलम्ब

हास्पीटल सर्विस कन्सल्टेन्सी कोर्पोरेशन (हा.स.क.को.) मंत्रालय द्वारा पहले से निर्धारित की गई दरों पर विकेताओं को आपूर्ति आदेश देता है। हा.स.क.का. जांच तथा निरीक्षण हेतु दवा को तैयार रखने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को 60 दिन प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चि.भ.डि. में दवाईयां हा.स.क.का. को आवश्यकता के सम्प्रेषण के दो से छः महीनों के विलम्ब के पश्चात प्राप्त हुई थीं। इसके अतिरिक्त, चि.भ.डि. से के.स.स्वा.यो. स्वास्थ्य केन्द्रों को दवाईयां जारी करनी में अतिरिक्त तीन से पांच महीने लगे (**अनुबंध-8**)। प्रभाव में के.स.स्वा.यो. स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाईयाँ काफी विलम्ब से प्राप्त हुई थीं।

इसी प्रकार, के.स.स्वा.यो. चैन्नई, जयपुर, कोलकाता, चण्डीगढ़, तिरूवनन्तपुरम, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर में संबंधित चि.भ.डि. से दवाईयां आदेश देने के दो से दस महीनों के विलम्ब के पश्चात प्राप्त हुई थीं।

के.स.स्वा.यो. हैदराबाद, तिरूवनन्तपुरम, चण्डीगढ़, मुम्बई तथा भुवनेश्वर में 2009-10 से 2011-12 के दौरान स.चि.भ.डि. से मांगी गई दवाईयों का 85 *प्रतिशत* तक की कम-आपूर्ति/गैर-आपूर्ति थी।

के.स.स्वा.यो. स्वास्थ्य केन्द्रों में फार्मूलरी दवाईयों के प्रापण में विलम्ब तथा गैर-उपलब्धता के.स.स्वा.यो. केन्द्रों द्वारा इन दवाईयों का अधिक दरों पर स्थानीय कैमिस्टों से प्रापण का कारण बनी जो ₹ 3.05 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का कारण बना जैसा नीचे विवरण दिया गया हैः

[13] जनेसिद्धी योजना के अंतर्गत प्रजातिगत दवाईयां, जो कम मूल्यों पर उपलब्ध हैं परन्तु ब्रांडड महंगी दवाईयों के बराबर क्षमता की है, को जनेसिद्धी भण्डारों के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई जाती है।

स्थानीय कैमिस्टों से फार्मूलरी दवाईयों को अधिक दरों पर खरीदे जाने पर अतिरिक्त व्यय

(₹ लाख में)

के.स.स्वा.यो. में शामिल शहर का नाम	किए गए अतिरिक्त व्यय की राशि
दिल्ली	231.83*
कोलकाता	0.18
हैदराबाद	12.77
जयपुर	14.44
चैन्नई	45.58
योग	**304.80**

*** विवरण अनुबंध-9 में**

6.3.10 दिल्ली में हॉ.स.कं.का. के माध्यम से फार्मूलरी दवाईयों के प्रापण में ₹ 13.52 करोड़ का परिहार्य व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 165 तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सलाहकार नियुक्ति नीतियां एवं प्रक्रिया नियमपुस्तिका के पैरा 1.2.1 के अनुसार, अपेक्षित आंतरिक विशेषज्ञ के अभाव की परिस्थिति में तथा जब इसे पूर्णतया अनिवार्य समझा जाए तभी सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकती है।

चि.भ.डि. दिल्ली नोडल कार्यालय है जो दिल्ली के सभी के.स.स्वा.यो. स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु दवाईयों का प्रापण करता है। स्वीकृत दवा फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवा की प्रापण दरें तथा संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। तथापि, चि.भ.डि. इन दवाईयों का सीधे अधिसूचित आपूर्तिकर्ताओं से प्रापण करने के बजाए हॉ.स.कं.का. के माध्यम से इनका प्रापण करता है। चि.भा.डि. ने इस प्रापण हेतु अक्तूबर 2008 तक हॉ.स.कं.को. को 4.5 *प्रतिशत* तथा उसके पश्चात 2.5 *प्रतिशत* परामर्शी प्रभार का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हॉ.स.कं.को. ने प्रापण प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं जोड़ा तथा मंत्रालय तथा आपूर्तिकर्ता के बीच एक वाहक के रूप में सामान्य कार्य किया। यह इसलिए है क्योंकि हॉ.स.कं.को. के माध्यम से प्रापण की गई दवाईयों के लिए दरें तथा आपूर्तिकर्ता पहले से ही निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार, चि.भ.डि. दिल्ली ने 2002-03 से 2010-2011 के दौरान हॉ.स.कं.को. को अदा किए परामर्शी प्रभारों पर ₹ 13.52 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

6.3.11 दवाईयों के प्रापण के सरल एवं कारगर बनाने हेतु प्रारम्भिक परियोजना

के.स.स्वा.यो. ने के.स.स्वा.यो. में दवाईयों के प्रापण को सरल एवं कारगार करने हेतु एक प्रारम्भिक परियोजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया (जनवरी 2007)। परियोजना में के.स.स्वा.यो. केन्द्रों में दवाईयों की मासिक खपत का निर्धारण करने की अभिकल्पना

की गई थी। इस प्रकार निर्धारित आवश्यकताओं को माह के अंत में आपूर्तिकर्ता को सूचित किया जाना था। आपूर्तिकर्ता द्वारा दवाईयों को प्रत्येक माह के प्रारम्भ में सीधे के.स.स्वा.यो. को सूपूर्द किया जाना था। इस परियोजना में दिल्ली में हॉ.स.कं.को. के माध्यम से तथा दिल्ली से बारह के शहरों में मु.चि.भ.डि. के माध्यम से मौजूदा केन्द्रीय प्रापण प्रणाली में उपस्थित दवाईयों की आपूर्ति में विलम्बों को दूर करने की कल्पना की गई थी।

मंत्रालय ने प्रारम्भ में दिल्ली में 10 के.स.स्वा.के. हेतु प्रारम्भिक परियोजना स्वीकृत की (मार्च 2007)। परियोजना जुलाई 2008 से कार्यान्वित की गई थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रस्ताव जिसमें फार्मूलरी तथा गैर-फार्मूलरी दवाईयों दोनों के प्रापण की अभिकल्पना की गई थी, के विपरीत प्रारम्भिक परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत सूची में केवल गैर-फार्मूलरी दवाईयां ही शामिल थी। इसमें 235 दवाईयां शामिल थी जिन्हें के.स.स्वा.यो. में आमतौर पर सलाह दी गई बताया गया था। सितम्बर 2009 तक परियोजना को सभी के.स.स्वा.यो. केन्द्रों तक फैला दिया गया था। बाद में प्रारम्भिक परियोजना में दवाईयों की सूची को 272 दवाईयों तक संशोधित किया गया था तथा उन्हें मंत्रालय की ब्रांडड फार्मूलरी में शामिल किया गया था (सितम्बर 2010)।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि चि.भ.डि. ने प्रस्तुत किया (सितम्बर 2010) कि मंत्रालय द्वारा यथा स्वीकृत नई दवा फार्मूलरी की सभी 622 दवाईयों को प्रारम्भिक परियोजना में शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य हॉ.स.कं.को. के माध्यम से प्रापण में विलम्बों को कम करने के साथ-साथ हॉ.स.कं.को. को अदा किए जा रहे 2.5 *प्रतिशत* कमीशन की बचत करना था। तथापि, प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया तथा इसके कारण अभिलेख में नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि के.स.स्वा.यो. चैन्नई, कोलकाता, जयपुर तथा हैदराबाद में, यहां तक की प्रारम्भिक परियोजना में शामिल की गई दवाईयों का प्रापण भी स्थानीय खरीद के माध्यम से अधिक दरों पर किया गया था जो ₹ 85.22 लाख के अतिरिक्त व्यय का कारण बना।

6.3.12 जीवन रक्षक दवाईयों का प्रापण

के.स.स्वा.यो. जीवन रक्षक दवाईयों के वर्ग के अंतर्गत 382 दवाईयों का अनुरक्षण करती है। यह मंत्रालय की स्वीकृत दवा फार्मूलरी से अलग है। इस दवाईयों में कैंसर, किडनी रोग, ओस्टीओपोरिस, डायलेसिस, हैमोफीला आदि के लिए दवाईयां शामिल हैं।

चि.भ.डि. उत्पादकों से प्राप्त निविदाओं के आधार पर इन दवाईयों की प्रापण दरों को अंतिम रूप देता है। चि.भ.डि. के.स.स्वा.यो. के डाक्टरों द्वारा लिखे गए प्रेसक्रिप्शनों के आधार पर स्वीकृत दरों पर दवाईयों का प्रापण करता है।

जैसा कि अन्य ब्रांडड दवाईयों के मामले में पाया गया कि समान दवा संघटन के एक से अधिक ब्रांड थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसम्बर 2011 तक जीवन रक्षक दवाईयों की सूची में 72 तथा संघटकों के ऐसे 206 ब्रांड थे। इसके अतिरिक्त, समान दवा संघटन वाले विभिन्न ब्रांडों के मूल्य में बहुत अधिक अंतर था।

के.स.स्वा.यो. दिल्ली, तिरूवंतपुरम, इलाहाबाद तथा कोलकाता में जीवन रक्षक दवाईयों के प्रापण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि के.स.स्वा.यो. ने स्वयं की सूची के कम लागत के ब्रांडों की उपलब्धता के बावजूद अधिक मूल्य के ब्रांड दवा का प्रापण करने पर ₹ 6.26 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया (**अनुबंध-10**) के.स.स्वा.यो. ने जीवन रक्षक दवाईयों की सूची में उसी संघटन की दवा के कुछ ब्रांडों को शामिल करने के कारण प्रदान नहीं किए थे। इस कारण मनमाने ढंग से दवाओं का प्रापण हुआ।

के.स.स्वा.यो. हैदराबाद में, यह पाया गया कि जीवन रक्षक दवाईयों को प्राधिकृत सूची के दरों से अधिक दरों पर खरीदा गया था जिसका परिणाम ₹ 20.22 लाख के परिहार्य अतिरिक्त व्यय में हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि चि.भ.डि. दिल्ली ने प्रजातिगत दवाईयों के प्रापण हेतु एक खुली निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की (जून 2009)। तथापि, निविदा दस्तावेजों में धाराओं के संशोधन से संबंधित मामलों के कारण निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस प्रकार चि.भ.डि. जुलाई 2012 तक खुली निविदा के माध्यम से जीवन रक्षक दवाईयों का प्रापण करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में विफल रहा।

6.3.13 गुणवत्ता आश्वासन

चि.भ.डि. द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाईयों की, के.स.स्वा.यो. को आपूर्ति से पहले, प्रयोगशाला में जांच अनिवार्य है।

के.स.स्वा.यो. कोलकाता में जांच रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले ही रोगियों को दवाईयां जारी की गई थीं जिन्हें बाद में मु.चि.भ.डि. द्वारा निम्न कोटि की बताया गया था। के.स.स्वा.यो. मुम्बई में, 2009-2012 के दौरान मु.चि.भ.डि. से प्राप्त ₹ 28.45 लाख मूल्य की औषधियों को निम्न कोटि की घोषित किया गया था। इनमें से ₹ 15.66 लाख

की कीमत की औषधियां पहले ही रोगियों को जारी कर दी गई थीं। ऐसे मामले गुणवत्ता आश्वासन हेतु एक सख्त क्रिया विधि के अभाव को इंगित करते हैं जो रोगियों को निम्न कोटि की औषधियों तथा दवाईयों के जोखिम को उजागर करती हैं।

के.स.स्वा.यो. हैदराबाद में मु.चि.भ.डि. से प्रापण की गई ₹ 21.39 लाख मूल्य की दवाईयों में निधान जीवन नियत नहीं किया गया था तथा निधान जीवन में कमियां एक से तीन महीनों के बीच थीं।

चण्डीगढ़ में ₹ 13.53 लाख की कीमत की दवाईयां अप्रैल 2009 से नवम्बर 2011 के बीच कालातीत हो गई जो सूचित करती है कि दवाईयों की आवश्यकता का उचित रूप से निर्धारण नहीं किया गया था।

6.3.14 निष्कर्ष

यह स्वीकृत है कि फार्मूलरी में दवाईयों के मूल्य गैर-फार्मूलरी दवाईयों से कम है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रापण की गई दवाईयों में 71 *प्रतिशत* दवाईयां फार्मूलरी से बाहर की थी।

इसके अतिरिक्त, दवाईयों के प्रापण से संबंधित प्रकियाएं अधिकतम किफायत लागू करने का निर्देश नहीं देती थी। परिणामस्वरूप, क्रय लागत के ब्रांड की उपलब्धता के बावजूद उच्च मूल्य की ब्रांडड दवाईयों का प्रापण किया गया था।

संसदीय समिति की प्रतिकूल अभ्युक्तियों के बावजूद प्रजातिगत दवाईयों की जगह ब्रांडड दवाईयों को प्राथमिकता दिया जाना जारी रहा। इसने राजकोष पर भारी वित्तीय भार डाला। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित मौद्रिक मूल्य केवल नमूना जांच किए गए मामलों से संबंधित है जो वास्तविक प्रापण का केवल एक छोटी प्रतिशतता है। इसलिए, अगर पूर्ण प्रापण की गणना की जाए तो ऐसी अनियमित प्रक्रिया का वित्तीय प्रभाव काफी अधिक होगा।

मंत्रालय लेखापरीक्षा निष्कर्षों के परिपेक्ष मे दवाईयों के प्रापण हेतु वर्तमान की मौजूदा प्रबंधन की समीक्षा करे।

महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

6.4 क्षयरोधी दवाओं के कालातीत होने के कारण हानि

मंत्रालय के केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग द्वारा क्षयरोधी दवाईयों के प्रापण में अनुचित योजना का परिणाम ₹ 5.06 करोड़ की कीमत की दवाईयों के कालातीत होने के कारण हानि में हुआ।

क्षय रोग (टी.बी.) भारत में एक बड़ी लोक स्वास्थ्य समस्या है। टी.बी. के लिए दवाईयों की कमी तथा अनियमित आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का निपटान करने हेतु 1997 में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम (सं.रा.क्ष.का.) प्रारम्भ किया गया था। स.रा.क्ष.का. विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अनुप्रयोग है जिसने प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित उपचार की लघु क्रम योजना की अनुशंसा की।

स.रा.क्ष.का. के अंतर्गत दवाईयां की निरंतर अविरत आपूर्ति के सिद्धात का अनुपालन किया जाता है जबकि गैर -डाट्स[14] खुराक हेतु खुली क्षयरोधी दवाईयों को प्रापण किया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग (के.क्ष.प्र) अपेक्षित प्रमात्रा के निर्धारण के आधार पर डाट्स तथा गैर-डाट्स खुराकों दोनों के लिए प्रापण ऐजेन्टों के माध्यम से क्षयरोधी दवाईयों का प्रापण करता है।

प्रापण एजेंटों के माध्यम से दवाईयां छः सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो[15] (स.चि.भ.डि.) द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, के.क्ष.प्र. संबंधित राज्य दवा भण्डारों तथा जिला टी.बी. नियंत्रण समितियों की दवाईयों के संवितरण हेतु स.चि.भ.डि. को निर्गम आदेश जारी करता है।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 2005 के प्रतिवेदन सं. 2 में, फरवरी तथा नवम्बर 2002 के दौरान स.चि.भ.डि., कोलकाता में ₹ 28.67 लाख की कीमत की क्षयरोधी दवाईयों की निधानजीवन की समाप्ति के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिए गए थे। अपनी कार्रवाई टिप्पणी (मार्च 2007) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवाईयों को कालातीत होने के लिए मुख्य रूप से करते हुए टी.बी. कार्यक्रमों की योजना में बदलाव को आरोपित किया। इसने यह सुनिश्चित करते हुए कि अधिकतम निधान जीवन पाने के लिए दवाईयों का विभिन्न चरणों में प्रापण किया है तथा स्टॉक के इस्टतम उपयोग के माध्यम से दवा प्रबंधन को सुधारने का आश्वासन भी दिया।

के.क्ष.प्र. के अभिलेखों की अनुवर्ती जांच ने प्रकट किया कि 2004-05 से 2005-06 के दौरान छः स.चि.भ.डि. ने ₹ 16.64 करोड़ की कीमत की गैर-डाट्स खुराक हेतु 25.09 करोड़ खुली क्षयरोधी दवाईयों की गोलियां प्राप्त की थी। खुली क्षयरोधी दवाईयों का इस निर्धारण के आधार पर प्रापण किया गया था कि कम से कम 10 *प्रतिशत* रोगियों को गैर-डाट्स खुराक, अर्थात खुली दवाईयों के रूप में, दिए जाने की आवश्यकता होगी।

---

[14] डाट्स पद्धति का मतलब प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित उपचार लघु क्रम योजना है जिसकें अंतर्गत एक रोगी हेतु रोगी-वार बाक्स चिह्नित किया जाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि रोगी उपचार की पूर्ण अवधि के लिए दवाईयां प्राप्त करता है। जबकि गैर-डाट्स खुराक के अंतर्गत रोगियों को खुली गोलियां संवितरित की जाती है।

[15] मुम्बई, कोलकाता, करनाल, हैदराबाद, गुवाहटी तथा चैन्नई में स.चि.भ.डि.

10 *प्रतिशत* का निर्धारण यह कल्पना करने के पश्चात किया गया था कि कुछ रोगियों को डाट्स के अंतर्गत उपचार लेने में कठिनाई होगी या वह अन्य कारणों से डाट्स को स्वीकार नहीं करेंगे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने मंत्रालय में संबंधित दस्तावेजों से पाया कि 10 *प्रतिशत* के आंकड़ों पर पहुंचने हेतु विस्तृत विश्लेषण अथवा पर्यालोचन के अभिलेख मौजूद नहीं थे। इस प्रकार, 10 *प्रतिशत* गैर-डाट्स के आवश्यकता की कल्पना का कोई उचित आधार नहीं था। यह विश्लेषण महत्वपूर्ण था क्योंकि दो खुराकों के अंतर्गत दवाईयां आपस में बदलने योग्य नहीं थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स.चि.भ.डि. में ₹ 5.06 करोड़ मूल्य की 11.09 करोड़ गोलियों की पांच वर्षों की निधान जीवन अक्तूबर 2011 तक समाप्त हो गई थी। यह उपलब्ध कुल प्रमात्रा का 46 *प्रतिशत* था।

इस प्रकार, मंत्रालय ने क्षयरोधी दवाईयों के निधान जीवन की समाप्ति के कारण ₹ 5.06 करोड़ की हानि उठाया। इसमें से ₹ 2.75 करोड़[16] की कीमत की दवाईयों को 2007-11 के दौरान बट्टे खाते डाला गया था। शेष कालातीत दवाईयों के नियमन हेतु प्रक्रिया मंत्रालय के केन्द्रीय टी.बी.प्रभाग द्वारा प्रारम्भ की जा रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त मंत्रालय ने दवाईयों के कालातीत होने के कारण हानि को बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्ताव को सहमति प्रदान करते समय पाया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ऐसी गलतियों के गैर-आवर्तन को सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को खुली क्षयरोधी दवाईयों के कालातीत होने के कारण को बताते हुए उल्लेख किया कि दवाईयां योजना में बदलाव, जिसमें कार्यक्रम में पहले रोगियों के लिए इस्तेमाल की गई गैर-डाट्स खुराक के स्थान पर वि.स्वा.सं. अनुशंसित डाट्स योजना का अनुपालन करना अपेक्षित है, के कारण कालातीत हुई। मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि वि.स्वा.सं. अनुशंसित डाट्स योजना, सामान्यता सं.रा.अ.का. के रूप में नामित, 1997 से परिचालन में है। इसके अतिरिक्त, तथ्य यह है कि पहले के लेखापरीक्षा पैरा के संबंध में अपनी का.टि. में मंत्रालय द्वारा यही कारण प्रस्तुत किया गया था जो दर्शाता है कि मंत्रालय द्वारा इस महत्वपूर्ण मामले का निपटान करने हेतु उपयुक्त शोधक उपाय नहीं किए गए हैं।

[16] दिसम्बर 2011 में वित्त मंत्रालय द्वारा ₹ 2.59 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए तथा नवम्बर 2007 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ₹ 15.68 लाख बट्टे खाते में डाले गए।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2013) कि इसने अनुमान लगाया था कि 10 *प्रतिशत* टी.बी. रोगियों को गैर-डाट्स खुराक दिया जाना जारी रहेगा जबकि एक *प्रतिशत* से कम रोगियों को इसे दिया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि ऐसे आवर्तनों से बचने हेतु उसने कदम उठाए थे।

बाद में, मंत्रालय ने दोहराया (जुलाई 2013) कि डाट्स कार्यक्रम को अपनाना योजना में एक बड़ा बदलाव था। सम्पूर्ण कार्यक्रम के परिणाम तथा विस्तार की तुलना में हानि महत्वपूर्ण नहीं थी। आगे इसने बताया कि खुली दवाईयों का कालातीत होना तथा उनका अपूर्ण उपयोग डाट्स के त्वरित विस्तार तथा गैर-डाट्स खुराक की विलम्बित आपूर्तियों से भी जुड़ा था।

मंत्रालय के उत्तर स्थापित करता है कि प्रापण योजना अनुचित थी। गैर-डाट्स खुराक हेतु रोगियों का निर्धारण यादृच्छिक था जो बड़ी हानियों का कारण बना। परिणामस्वरूप, लोक लेखा समिति को दिया गया आश्वासन पूर न‍हीं किया गया है। यह अनुशंसा की जाती है कि इस गलती हेतु जिम्मेदारी का अवश्य पता लगाया जाए।

अध्याय VII : गृह मंत्रालय

सशस्त्र सीमा बल

7.1 आवासीय परिसरों के निर्माण में अत्यधिक खर्च

गृह मंत्रालय से प्राधिकृत मापदण्डों की स्वीकृति मिलने के बाद सशस्त्र सीमा बल ने नियत समय पर आवासीय मकानों को बनाने के लिए मानक निश्चित नहीं किए थे। यह 108 आवासीय परिसरों के निर्माण में ₹ 5.19 करोड़ ज्यादा खर्च का कारण बना।

2012-13 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.13 के पैरा सं. 4.3 में सहायक आसूचना ब्यूरो, लखनऊ द्वारा स्टॉफ के आवासीय परिसरों के निर्माण में अनावश्यक देरी से ₹ 2.17 करोड़ की लागत वृद्धि को शामिल किया गया था।

गृह मंत्रालय ने कार्यवाही टिप्पणी में बताया (मई 2013) कि सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.) को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) से मुख्यालय स्तर पर विलंबित प्रस्तावों पर चर्चा हेतु हर महीने सम्मेलन करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, लागत/समय विस्तार वाली परियोजनाओं की सूची को मासिक आधार पर के.स.पु.ब. मुख्यालय द्वारा के.लो.नि.वि. मुख्यालय को उनके हस्तक्षेप से मुद्दे के निपटान हेतु प्रेषित किया जाए।

एक अलग प्रकरण में, सशस्त्र सीमा बल (स.सी.ब.) के आवासीय परिसर के निर्माण की लेखापरीक्षा जांच करने पर अनावश्यक देरी प्रकट हुई जो कि निम्न प्रकार से हैः

स.सी.ब. ने मुख्यालय वाहिनी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 371 आवासीय मकानों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया (जून 2004)। स.सी.ब. की वित्तीय शाखा ने इस तथ्य के आधार पर कि आवासीय मकानों की श्रेणीवार जरूरत गृह मंत्रालय (गृ.मं.) में अंतिम प्रक्रिया में थी, आवश्यकता का संसोधन करके आवासीय मकान (**टाईप-I-140, टाईप-II-48, टाईप-V-I**) 189 कर दिए गए। गृ.मं. ने प्रस्तावित आवासीय मकानों के निर्माण के लिए ₹11.78 करोड़ की मंजूरी प्रदान की (फरवरी 2005)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गृ.मं. ने स.सी.ब. के आवासीय भवनों (**टाईप-I-25, टाईप-II-269, टाईप-V-2**) के लिए प्राधिकृत मापदंडों का अनुमोदन किया (फरवरी 2006)। परिणामस्वरूप यह भवनों की मंजूरी अब 296 हो गई। स.सी.ब. ने प्रारम्भ में स्वीकृत और बाद में प्राधिकृत मकानों की संख्या में वृहत अंतर का अवलोकन करने पर, यथा निम्न वर्णित मात्र 52 मकानों का निर्माण कराने का निर्णय लियाः

टाईप	स्वीकृत मकानों की संख्या	अब प्राधिकृत मकानों की संख्या	उपलब्ध मकानों की संख्या	बनाए जाने वाले मकानों की संख्या
I	140	25	22	**03**
II	48	269	-	**48**
V	1	2	-	**1**

तदनानुसार, स.सी.ब. ने के.लो.नि.वि. से केवल 52 मकानों के बनाने के लिए निवेदन किया (मार्च 2006)। इसने के.लो.नि.वि. को यह भी सूचित किया कि गृ.मं.से अनुमोदित प्राधिकरण प्रतिमानों के अनुसार संशोधित संस्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात शेष श्रेणी के मकानों के लिए निर्णय बता दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने स.सी.ब. की तरफ से संशोधित संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए मंत्रालय से मामले को उठाने में विलम्ब पाया। स.सी.ब. ने इस मुद्दे को जनवरी 2009 में उठाया और वो भी के.लो.नि.वि. द्वारा मामले को जल्दी निपटाए जाने के अनुरोध करने के बाद। इसमें 33 माह (अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2008) तक विलम्ब हुआ। के.लो.नि.वि. ने ये भी बताया कि 52 मकान ₹ 4.10 करोड़ की लागत पर बनाए गए।

तदपरांत, स.सी.ब. ने गृ.मं. को अतिरिक्त मकानों के निर्माण हेतु संस्वीकृति के संशोधन के लिए संपर्क किया (जनवरी 2009)। जैसा कि विवरण नीचे दिया गये हैं:

क्र.सं.	टाईप	पूर्व में संस्वीकृत मकानों की सं.	बनाए गए मकानों की सं.	अन्य प्रकारों में/से अंतरण हेतु प्रस्तावित मकानों की सं.	अंतरण के पश्चात कुल सं.
1.	टाईप I	140	03	137[1]	03
2.	टाईप II	48	48	108	156 (48+108)
3.	टाईप V	01	01	-	1
	योग	**189**			**160**

गृह मं. ने 160 आवासीय मकानों के निर्माण हेतु संशोधित संस्वीकृति प्रदान की (मार्च 2009)। तथापि लो.नि.वि. ने पुरानी दरों पर निर्माण कार्य शुरू करने में अपनी असमर्थता जताई और ₹ 21.06 करोड़ का एक संशोधित प्रारंभिक प्राक्कलन प्रस्तुत किया। के.लो.नि.वि. ने प्राक्कलन में वृद्धि के लिए सामग्री एवं श्रम के बढ़े हुए कीमत को जिम्मेदार ठहराया। स.सी.ब. ने ₹ 21.06 करोड़ के संशोधित व्यय संस्वीकृति को प्राप्त करने के लिए गृ.मं. से संपर्क किया (अगस्त 2010) जिसे सितम्बर 2010 में प्रदान

[1] न्याधार क्षेत्र के समतुल्य को दृष्टि में रखते हुए 137 टाईप-I मकानों को 108 टाईप-II मकानों में बदलना प्रस्तावित था।

किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि के.लो.नि.वि. द्वारा ₹ 16.75 करोड़ की लागत से 91 *प्रतिशत* निर्माण कार्य जनवरी 2013 तक पूरा कर लिया गया था।

इस प्रकार, स.सी.ब. की एक समयबद्ध तरीके से मामले के निपटाने में विफलता परियोजना पर ₹ 5.19 करोड़ के उल्लेखनीय कीमत वृद्धि में परिणत हुआ। (**विवरण अनुबंध-11 में**)।

स.सी.ब. ने बताया (मई 2013) कि गृ.मं. द्वारा लागत के संसोधन मे लिया गया समय प्रक्रियात्मक था और इसमें के.लो.नि.वि. से परियोजना की प्रकृति एवं विशेष परिस्थितियों जिसमें यह शुरू किया गया था, के संबंध में पत्राचार एवं स्पष्टीकरण मांगना शामिल था।

स.सी.ब. ने अपने तर्क के समर्थन में दस्तावेजीप्रमाण उपलब्ध नहीं कराया था। इसके अतिरिक्त उत्तर स.सी.ब. के अभिलेखों से मेल नहीं खाता है जो स्पष्टतः स्थापित करता है कि मार्च 2006 के बाद और दिसम्बर 2008 तक मंत्रालय से संशोधित संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु विषय को उठाया नहीं गया था जो ₹ 5.19 करोड़ के लागत वृद्धि में परिणत हुआ।

सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब)

7.2 अनियमित प्रापण

फील्ड दूरभाष केबल का प्रापण करते समय सी.सु.ब. का निर्धारित प्रावधानों का अनुसरण करने में विफलता के परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 1.45 करोड़ की हानि हुई।

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 150 निर्धारित करता है कि ₹ 25 लाख या अधिक के अनुमानित कीमत के सामान के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए। सा.वि.नि. केवल इन मामलों में प्रक्रिया से विचलन की अनुमति देता हैः (i) जहां मंत्रालय या विभाग में सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि अत्यावश्यकता की दृष्टि से विज्ञापति निविदा पूछताछ के माध्यम से प्रापण नहीं किए जाने के कारण किया गया कोई भी अतिरिक्त व्यय न्यायसंगत है या (ii) आपूर्ति के स्त्रोत निश्चित रूप से ज्ञात है तथा पहले से ही उपयोग हो रहे स्त्रोतों से परे नए स्त्रोत की संभावना, अल्प है। आगे,

सा.वि.नि. का नियम 154 मंत्रालय या विभाग से एकमात्र स्त्रोत से माल के प्रापण से पूर्व उपयुक्त वस्तु प्रमाणपत्र[2] (उ.व.प्र.) प्रदान करने की अपेक्षा करता है।

संचार उद्देश्यों हेतु सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) फील्ड दूरभाष केबल जे.डब्ल्यू.डी.-I का उपयोग करता है।

महानिदेशक, सी.सु.ब. ने मैसर्स ऑर्डिनेंस केबल फेक्टरी (ओ.सी.एफ.), चण्डीगढ़ से ₹ 5.43 करोड़ की लागत (₹ 7384 प्रति कि.मी. की दर) पर 7290 किलोमीटर (कि.मी.) की फील्ड दूरभाष केबल जे.डब्ल्यू.डी.-I (एच.डी.पी.ई.) का प्रापण किया (जून 2009)। यह प्रापण उ.व.प्र. आधार पर किया गया था।

सी.सु.ब. ने उ.प.प्र. आधार पर 2000 कि.मी. की अतिरिक्त लम्बाई की फील्ड दूरभाष केबल जे.डब्ल्यू.डी.-I (एच.डी.पी.ई.) के प्रापण हेतु उसी कम्पनी से नई निविदाएं आमंत्रित की (सितम्बर 2010)। हांलाकि, ओ.सी.एफ. द्वारा परिनिर्धारित क्षति (प.क्ष.) तथा वितरण अवधि उपधाराओं की अस्वीकृति के कारण, केबल के प्रापण की निविदा को खत्म कर दिया गया था (अक्तूबर 2010)। तत्पश्चात सी.सु.ब. ने केबल के प्रापण हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2011)। फरवरी 2011 में आमंत्रित खुली निविदा के प्रति चार कम्पनियों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की थीं। मैसर्स नेटवर्क केबल जिसने ₹ 5462 प्रति किलोमीटर की दर उद्धरित की थी, उसे सबसे कम बोली (एल-1) लगाने वाला घोषित किया गया था। सी.सु.ब. ने ₹ 1.09 करोड़ की निविदा में दी गई राशि पर कंपनी को आपूर्ति आदेश दिया (अक्तूबर 2011)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009 में सी.सु.ब. द्वारा प्रापण की गई फील्ड दूरभाष केबल जे.डब्ल्यू.डी.-I (एच.डी.पी.ई.), उ.व.प्र. मद नहीं थी, जैसा कि फरवरी 2011 में सी.सु.ब. द्वारा आमंत्रित खुली निविदा पर प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है। इस प्रकार, इस मामले में सा.वि.नि. के नियम 154 में निहित प्रावधान लागू नहीं होते थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सी.सु.ब. द्वारा उपयुक्त उ.व.प्र., 2008 के दौरान ओ.सी.एफ. द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार, जून 2009 में ओ.सी.एफ. को आपूर्ति आदेश देने से पूर्व सी.सु.ब. द्वारा उ.व.प्र. की प्रयोज्यता की पुष्टि नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, 2009-10 के दौरान ओ.सी.एफ. से सी.सु.ब. द्वारा प्राप्त किया गया केबल 2011[3] में मैसर्स नेटवर्क केबल द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में ₹ 1922 (₹ 7384 -₹ 5462) प्रति

---

[2] इसका प्रमाणपत्र कि केवल एक विशेष कंपनी ही आवश्यक सामान की निर्माता है।

[3] यह तुलना इस तथ्य की दृष्टि में न्यायसंगत है कि सितम्बर 2010 में ओ.एफ.सी. द्वारा उद्धिष्ट केबल का मूल्य ₹ 8800 प्रति कि.मी. था जिसने वृद्धि की प्रवृति प्रदर्शित की।

कि.मी. अधिक था। अतः, ओ.सी.एफ. से फील्ड दूरभाष केबल (जे.डब्लयू.डी.) के प्रापण पर सी.सु.ब. को कम से कम ₹ 1.45 करोड़ की हानि हुई।

सी.सु.ब. ने बताया (सितम्बर 2012) कि यद्यपि एल-1 कंपनी विशिष्टताओं को पूरा करता था, लेकिन ओ.सी.एफ. चण्डीगढ़ द्वारा आपूर्ति की गई फील्ड दूरभाष केबल जे.डब्लयू.डी-I (एच.डी.पी.ई.) की मजबूती एंव बनावट, परिष्कार, गुणवत्ता, खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जो आपूर्ति की गई है, में सर्वथा ज्यादा बेहतर एवं श्रेष्ठतर है।

सी.सु.ब. का तर्क, तथ्यों से नहीं निकला है क्योंकि मैसर्स नेटवर्क केबल के आवश्यक तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के पश्चात ही उसे फील्ड दूरभाष केबल (जे.डब्लयू.डी.) का आपूर्ति आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एक स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा मैसर्स नेटवर्क केबल द्वारा प्रदान किया गया केबल का नमूना, सी.सु.ब. की विशिष्टताओं का अनुपालन करता हुआ पाया गया था।

सी.सु.ब. ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय ने तत्पश्चात् ओ.सी.एफ. से एकल स्त्रोत आधार पर 1000 कि.मी. लम्बाई की कैरियर क्वाड केबल के इसी प्रकार के प्रापण की अनुमति दी थी (अगस्त 2011)। मंत्रालय ने देखा कि इस मामले में उ.व.प्र. की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कंपनी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग थी।

यह उत्तर सा.वि.नि. के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता क्योंकि उनमें सरकारी विभाग से प्रापण हेतु विशेष व्यवस्था प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, बोली की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह राय बनाने मे असमर्थ है कि क्या इस प्रापण हेतु कीमत प्रतिस्पर्धात्मक थी।

अध्याय VIII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

8.1 आकाश टेबलेट परियोजना में कमियां

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत, मंत्रालय ने उनकी कार्य प्रचालन क्षमता का पता लगाए बिना ही भा.प्रौ.सं., राजस्थान (भा.प्रौ.सं.रा.) द्वारा एल.सी.ए.डी.-आकाश को लॉंच करने का निर्णय लिया था। इसने परियोजना को पूरा करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। मंत्रालय ने विवेकपूर्ण मूल्यांकन किए बिना ही भा.प्रौ.सं.रा. को ₹ 47.42 करोड़ आवंटित कर दिए। इससे वित्तीय औचित्व पर सवाल उठे। इससे ₹ 1.05 करोड़ के परिहार्य व्यय के साथ परियोजना को पूरा करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (सू.सं.प्रौ.शि.रा.मि.) की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम के अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्री ने 'आकाश नामक उपयोग सहित कंप्यूटिंग के कम कीमत वाले उपकरण (एल.सी.ए.डी.-टेबलेट)' परियोजना को लॉंच किए जाने की घोषणा की (जुलाई 2010)। परियोजना के अन्तर्गत देश भर में उच्चतर शिक्षण संस्थानों के छात्रों तथा अध्यापकों को शैक्षिक उद्देश्यों हेतु टेबलेट को 35 अमरीकी डॉलर अर्थात् ₹ 1500 की लागत पर प्रदान करना परिकलित किया गया था।

मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान (भा.प्रौ.सं.रा.) द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर परियोजना हेतु भा.प्रौ.सं.रा. को कार्य में लगाने का निर्णय लिया था (जुलाई 2010)। प्रस्ताव के अनुसार, जनवरी 2011 तक संस्थान द्वारा एल.सी.ए.डी. की आपूर्ति की जानी थी तथा सफलतापूर्वक परीक्षण के पश्चात, एक वर्ष के भीतर ही छात्र तथा अध्यापकों को एक मिलियन एल.सी.ए.डी. प्रदान किए जाने थे।

सू.सं.प्रौ.शि.रा.मि. योजना पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्राप्ति, क्षेत्र परीक्षण तथा एक लाख एल.सी.ए.डी. के व्यापक परीक्षण को अनुमोदित किया था (सितम्बर 2010)। मंत्रालय द्वारा परियोजना को भा.प्रौ.सं.रा. को ₹ 41.50 करोड़[1] की अनुमानित लागत पर दिया गया था (अक्तूबर 2010)।

मंत्रालय ने परियोजना हेतु भा.प्रौ.सं.रा. को प्रथम किस्त के रूप में 15 करोड़ जारी किए थे (अक्तूबर 2010)। भा.प्रौ.सं.रा. ने निविदा प्रक्रिया शुरू की थी (अक्तूबर 2010)।

[1]परीक्षण हेतु ₹ 25 करोड़ तथा एक लाख डिवाइसों के प्रापण के लिए ₹16.50 करोड़

निविदा में भाग लेने वाले सात बोलीदाताओं में से केवल एक को परियोजना को शुरू करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य पाया गया था। इसी दौरान, भा.प्रौ.सं.रा. ने एक लाख एल.सी.ए.डी. के प्रापण हेतु तथा अतिरिक्त श्रमशक्ति और परीक्षण सुविधाओं के लिए मंत्रालय से ₹ 26.50 करोड़ की शेष निधियों को जारी करने का अनुरोध किया (नवम्बर 2010)। मंत्रालय ने भा.प्रौ.सं.रा. को ₹ 10 करोड़ जारी कर दिए (दिसम्बर 2010)।

आगे, स्थायी समिति की बैठक (मार्च 2011) में भा.प्रौ.सं.रा. ने सूचित किया कि पहले चयनित बोलीदाता द्वारा निविदा की शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण उसे नए सिरे से निविदा आरंभ करनी पड़ेगी। तत्पश्चात्, निविदा के दूसरे दौर में मैसर्ज डाटाविंड को सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में चयनित किया गया था। भा.प्रौ.सं.रा. ने सूचित किया कि सबसे कम स्वीकृत बोली[2] के आधार पर, द्वितीय निविदा में, एक लाख एल.सी.ए.डी. की प्रापण लागत में ₹ 6.22 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, कुल परियोजना लागत ₹ 47.22 करोड़ तक बढ़ गई थी (₹ 41.50 करोड़ + ₹ 6.22 करोड़)। मंत्रालय ने स्थायी समिति के अनुमोदन पर भा.प्रौ.सं.रा. को ₹ 22.72 करोड़ की शेष निधियाँ जारी की थी (मार्च 2011)।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विक्रेता मैसर्ज डाटाविंड अगस्त 2011 तथा नवम्बर 2011 के बीच भा.प्रौ.सं.रा. को केवल 6440 डिवाइस की आपूर्ति कर पाया था। वितरण विवरण के अनुसार, आपूर्ति की गई 6440 उपकरणों में से, 5790 उपकरणों को भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था तथा शेष 650 उपकरणों को आगे के क्षेत्र परीक्षण हेतु सशर्त स्वीकार किया गया था। इसी दौरान, एल.सी.ए.डी. की 366 उपकरणों को छात्रों में प्रतिपुष्टि हेतु वितरित किया गया था। उपकरणों के गर्म होने, उपकरण की बैटरी 3 घंटे तक नहीं चलने, उपकरणों के संचालन में धीमी गति तथा उसके प्रतिरोधी टच स्क्रीन के संबंध में शिकायतें थीं। इन मुद्दों के समाधान के लिए, मामले को कम्पनी के समक्ष उठाया गया था, जो कि उपकरण के कार्यों में सुधार लाने के लिए लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी के बिना ही उपकरण में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गई थी।

भा.प्रौ.सं.रा. ने मंत्रालय (नवम्बर 2011) को चयनित विक्रेता मैसर्ज डाटाविंड के खराब निष्पादन के बारे में सूचित किया और कहा कि उन्हें आगे का कार्य देना एक निष्फल अभ्यास होगा। उसने आगे बताया कि अनुबंध के अनुसार, संशोधित अनुसूची के अनुसार

[2] ₹45.45 प्रति अमरीकी डॉलर की विनिमय दर पर परिकलित अमरीकी डॉलर 49.48 की उपकरण लागत।

उपकरणों की आपूर्ति में असमर्थता तथा विलंब के कारण मैसर्ज डाटाविंड को दिया गया आदेश रद्द किया जा सकता है तथा बयाना जब्त कर लिया जाएगा।

उपकरणों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रालय में बैठक को आयोजित किया गया था (15 नवम्बर 2011)। यह निर्णय लिया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उपकरण बिना किसी दोष के थे, मैसर्ज डाटाविंड आपूर्ति किए गए प्रत्येक लॉट हेतु एक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा उपकरणों की सुपुर्दगी मार्च 2012 तक ही करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विक्रेता और भा.प्रौ.सं.रा. के बीच के विवाद को सुलझाया नहीं जा सका था। फलस्वरूप, भा.प्रौ.सं.रा. ने मंत्रालय को सूचित किया कि (फरवरी 2012) योजना के कार्यान्वयन के संबंध में उठने वाले असाध्य मुद्दों के कारण, परियोजना का अंतरण किसी अन्य उपयुक्त संगठन को करना चाहिए। परिणामतः मंत्रालय ने परियोजना का अंतरण भा.प्रौ.सं., बॉम्बे (भा.प्रौ.सं.बो.) को करने का निर्णय लिया ओर भा.प्रौ.सं.रा. से (अप्रैल 2012) शेष राशि का अंतरण भा.प्रौ.सं.बो. को करने का अनुरोध किया।

तदनुसार, अप्रैल 2012 से मई 2012 के बीच भा.प्रौ.सं.रा. ने तब तक के अर्जित ब्याज (₹ 5.10 करोड) और किए गए व्यय (₹ 1.05 करोड़) को समायोजित करने के पश्चात् भा.प्रौ.सं.बो. को ₹ 51.77 करोड़ का अंतरण कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने एल.सी.ए.डी. परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पाई:

1) भा.प्रौ.सं.रा. को परियोजना को संदिग्ध रूप से दिया जाना

(क) परियोजना हेतु भा.प्रौ.सं.रा. का चयनः मंत्रालय इस परिणाम की परियोजना को शुरू करने से पूर्व एक संभाव्यता अध्ययन करने में विफल रहा था। परियोजना को निष्पादित करने के लिए भा.प्रौ.सं.रा. का चयन करने के लिए मंत्रालय के अभिलेखों ने किसी भी प्रकार का औचित्य प्रदान नहीं किया था। इस प्रकार, भा.प्रौ.सं.रा. का चयन मनमाने ढंग से किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की यह राय इस तथ्य से निकली है कि प्रारंभिक चर्चा के दौरान, अन्य स्थापित भा.प्रौ.सं. अर्थात् भा.प्रौ.सं. कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बॉम्बे तथा भा.वि.सं. बैंगलौर ने भाग लिया था। हालांकि, इन संस्थानों को अनदेखा कर दिया गया था, तथा अन्य भा.प्रौ.सं. से पूर्व भा.प्रौ.सं.रा. को जोकि अपेक्षाकृत नया भा.प्रौ.सं. था, को मंत्रालय की इस प्रमुख परियोजना के लिए चयनित कर लिया गया था।

(ख) परियोजना के लिए भा.प्रौ.सं.रा. की तत्परता: मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग (ए.वि.प्र.) ने भा.प्रौ.सं.रा. को निधियों की संस्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव को सहमति देते समय परियोजना का कार्य करने के लिए भा.प्रौ.सं.रा. की तत्परता के बारे में पूछताछ की थी। यह मुद्दा इस तथ्य के प्रकाश में उठाया गया था कि भा.प्रौ.सं.रा. अस्थायी परिसर से परिचालन कर रहा था। ए.वि.प्र. की इस महत्वपूर्ण अभ्युक्ति को नजरअंदाज कर दिया गया था तथा परियोजना को शुरू करने की भा.प्रौ.सं.रा. की तत्परता का मूल्यांकन किए बिना ही भा.प्रौ.सं.रा. को कार्य आवंटित कर दिया गया था। मंत्रालय के अभिलेखों से यह स्थापित नहीं हो पाया कि परियोजना को शुरू करने के लिए भा.प्रौ.सं.रा. के पास उपलब्ध अवसंरचना तथा संसाधनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया था। अंत में, भा.प्रौ.सं.रा. परियोजना को पूरा करने में असमर्थ रहा क्योंकि वह सक्षम नहीं था। अतः, शुरू में, मंत्रालय द्वारा यथोचित परिश्रमशील अभ्यास द्वारा भा.प्रौ.सं.रा. की इन कमियों को पहचाना जा सकता था।

2) भा.प्रौ.सं.रा. को असावधानीपूर्वक निधियों को जारी कर दिया जाना: मंत्रालय ने पिछली किस्त के व्यय के विवरण तथा परियोजना की प्रगति पर रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति को सुनिश्चित किए बिना ही किस्तों में, परियोजना हेतु पांच माह की अवधि में अर्थात् अक्तूबर 2010 और मार्च 2011 के बीच में अविवेकी रूप से ₹ 47.72 करोड़ की राशि संस्वीकृत एवं जारी कर दी थी। इस प्रकार, मंत्रालय परियोजना कार्यान्वयन तथा भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा निधियों की उपयोगिता को प्रभावी रूप से मॉनीटर करने में विफल रहा। विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में, कि जारी की गई 97.80 *प्रतिशत* निधियों का ब्याज सहित अंतरण भा.प्रौ.सं.बो. को कर दिया गया था। अवधि जिसके लिए निधियां भा.प्रौ.सं.रा. के पास अवरूद्ध रही थी, वह 12 से लेकर 18 महीनों तक थी। सामान्य वित्तीय नियमावली प्रदान करती हैं कि खजाने से धन का आहरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि तुरंत संवितरण हेतु उसकी आवश्यकता न हो। बजट अनुदान की चूक को रोकने के लिए या मांगों की प्रत्याशा में खजाने से धन का आहरण अनुमेय नहीं है। आगे, यह देखा गया था कि मार्च 2011 के माह में बड़ा हिस्सा जारी किया गया था। इस प्रकार मंत्रालय की कार्रवाई सामान्य वित्तीय नियमावली की अनुपालन नहीं करती है।

3) भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा किया गया निष्फल व्यय

भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा किया गया ₹ 1.05 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा उसका कार्यान्वयन छोड़ दिया गया था। भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा किए गए व्यय के उदाहरण नीचे बॉक्स में दिए गए हैं।

भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा ₹1.05 करोड़ का निष्फल व्ययः कुछ उदाहरण

- परियोजना हेतु प्राप्त ₹ 20.67 लाख की कीमत के पी.सी. तथा टेबलेटों का अंतरण नए पी.आई. अर्थात्, भा.प्रौ.सं.बो. को नहीं किया गया था बल्कि इन्हें भा.प्रौ.सं.रा. में विभिन्न अन्य परियोजना प्रयोगशालाओं को जारी कर दिया गया था।
- जून-जुलाई 2011 के दौरान विक्रेता के स्थल पर मंत्रालय प्रतिनिधि के कनाडा दौरे से संबंधित ₹ 0.77 लाख के यात्रा व्यय की उपयोगिता को स्थापित नहीं किया जा सका था क्योंकि अभिलेखों में दौरे की कोई प्रतिपुष्टि/निष्पादन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।
- एल.सी.ए.डी. के नमूनों की जाँच के लिए ताइवान और चीन की यात्रा हेतु चार अधिकारियों के लिए वीजा शुल्क के रूप में ₹ 0.31 लाख का व्यय किया गया था। इस निर्णय के लिए कारणों को अभिलेखबद्ध किए बिना ही इस मिशन को निरस्त कर दिया गया था।
- सरकारी आदेशों के उल्लंघन में, 29 नमूना परीक्षित मामलों में निजी विमान सेवाओं में हवाई यात्राओं को नियमविरूद्ध अनुमति दी गई थी।
- भा.प्रौ.सं.रा. ने सरकारी आदेशों के उल्लंघन में हवाई टिकट सेवाओं के लिए मैसर्ज पर्ल इंटरनेशनल (लखनऊआधारित निजी कम्पनी) को नियुक्त किया था। इस प्रकार, कम्पनी को किया गया ₹ 5.02 लाख का भुगतान अनियमित था।
- मा.सं.वि.मं. के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को महीने में 15 दिनों के लिए कार्य करने की आरामदायक शर्तों के साथ ₹ 0.50 लाख के पारिश्रमिक पर तीन माह की अवधि हेतु भा.प्रौ.सं.रा. के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, रोजगार के लिए विज्ञापन में यह उपधारा उल्लिखित नहीं थी। बाद में, अनुबंध की समाप्ति पर, उसे तीन महीनों के लिए @3300 प्रतिदिन के मानदेय आधार पर पदासीन रखा गया था जिसके कारण मासिक अनुबंधित राशि ₹ 15000 से बढ़ गई।

इस प्रकार, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु भा.प्रौ.सं.रा. का चयन उचित रूप से नियोजित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप टेबलेटों की सुपुर्दगी अनुसूची पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा (मार्च 2012)। उपरोक्त दर्शाई गई वित्तीय एवं अन्य अनियमितताएं आगे दर्शाती है कि मंत्रालय ने परियोजना को कार्यान्वित करने में यथोचित परिश्रम का अभ्यास नहीं किया था। इसके अलावा, भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा किया गया ₹ 1.05 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि भा.प्रौ.सं.रा. द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन छोड़ दिया गया था तथा इसका अंतरण भा.प्रौ.सं.बो. को करना पड़ा।

मामले को मंत्रालय में मई 2013 में भेजा गया था; जुलाई 2013 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

8.2 अनुदान का अनियमित निर्गम

मंत्रालय ने मदरसाओं में अच्छी शिक्षा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत, योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति को सुनिश्चित किए बिना 372 मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसका परिणाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार को कुल ₹ 8.86 करोड़ की अनुदानों के अनियमित निर्गम में हुआ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मॉनीटरिंग समिति (रा.अ.शि.मॉ.स.) गठित की गई थी (2004)। रा.अ.शि.मॉ.स. की सिफारिशों पर मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (म.गु.शि.प्र.यो.) की पुनः रचना की गई थी।

म.गु.शि.प्र.यो. पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित थी। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मदरसाओं की वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित योग्यता शर्तें निर्धारित की गई थी:

- कम से कम तीन वर्षों से मदरसाओं का अस्तित्व होना, तथा
- केन्द्र अथवा राज्य सरकार अधिनियम अथवा मदरसा बोर्ड/वक्फ बोर्ड अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (रा.मु.वि.सं.) के अंतर्गत मदरसाओं का पंजीकरण।

योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता हेतु मदरसों से सभी अनुरोध की प्राप्ति शामिल थी। प्रस्तावों की संवीक्षा तथा सिफारिश हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को एक राज्य स्तरीय सहायता-अनुदान समिति गठित (स.अ.स.) करना अपेक्षित था, जिसमें मंत्रालय का मनोनीत शामिल था। राज्य सरकार की सिफारिशों सहित प्रस्ताव को निर्धारित प्रारूप में संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित किया जाना था। इसके पश्चात वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर मंत्रालय की स.अ.स. द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत 372 मदरसाओं[1] को वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए (जनवरी 2010)। राज्य सरकार स.अ.स. ने प्रस्तावों की जांच करते समय राज्य शिक्षा विभाग को सलाह दी (फरवरी 2010) कि आवेदनकर्ता मदरसाओं के प्रत्यायकों को पुनः सत्यापित किया जाए तथा

[1] कश्मीर में 235 तथा जम्मू में 137

प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले वास्तविक तथ्यों को सूचित किया जाए। मंत्रालय ने प्रस्ताव की संवीक्षा करते समय राज्य सरकार को मदरसाओं की संख्या, जिनके लिए अनुदान अपेक्षित था, को स्पष्ट करने का अनुरोध किया (जनवरी 2011)।

मंत्रालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने 372 मदरसाओं के अस्तित्व तथा पंजीकरण के विवरण प्रदान नहीं किए थे, जैसा कि योजना के अंतर्गत अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय के अभिलेखों में अनुदानग्राही मदरसाओं द्वारा योजना के अंतर्गत योग्यता शर्तों की पूर्ति के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण शामिल नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मंत्रालय ने मदरसाओं के प्रत्यायको का निर्धारण किए बिना 372 मदरसाओं को वित्तीय सहायता के रूप में कुल ₹ 8.86 करोड़ की अनुदानें जारी करने की स्वीकृति दी (मार्च 2011)। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार को मार्च 2011 तथा मई 2011 में क्रमशः ₹ 3.48 करोड़ तथा ₹ 5.39 करोड़ की सहायता अनुदान जारी की गई थी। इस प्रकार मंत्रालय द्वारा शर्तों की पूर्ति का निर्धारण किए बिना ₹ 8.86 करोड़ की अनुदान जारी करना अनियमित था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि राज्य स.अ.स. के सदस्य सचिव ने प्रमाणित किया था कि प्रस्ताव, योजना के मापदण्ड के अंतर्गत था। आगे, राज्य सरकार के उपयोग प्रमाणपत्र के अनुसार यह पाया गया था कि ₹ 8.86 करोड़ के अनुदान में से राज्य सरकार के पास ₹ 7.37 करोड़ का अव्ययित शेष था (जनवरी 2013 तक)। मंत्रालय ने राज्य सरकार को योजना के अंतर्गत निधियों के गैर-उपयोग के कारण प्रस्तुत करने तथा यह सत्यापित करने कि क्या राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए 372 मदरसाओं ने योग्यता मापदण्ड को पूरे किए थे, का भी अनुरोध किया था।

मंत्रालय का उत्तर यह तथ्य स्थापित करता है कि मंत्रालय ने अनुदान जारी करते समय मदरसाओं की योग्यता शर्तों की पूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग दर्शाता है कि निर्गम अनुपयुक्त था तथा इसका परिणाम निधियों के अवरोधन में हुआ।

अध्याय IX : खनन मंत्रालय

भारतीय खनन ब्यूरो, नागपुर

9.1 रॉक ड्रिलिंग रिग के उपयोग न होने के कारण हुआ निष्फल व्यय

उत्तर पूर्वी राज्यों के अवसंरचनात्मक विकास की सहायता के लिए केन्द्र सरकर द्वारा घोषित उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 20 मार्च 2006 तक उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल, को परेषिती द्वारा मैसर्ज के.एल.आर. इंडिस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद (आपूर्तिकर्ता) को उनके सबसे कम उद्धृत दर को स्वीकार करते हुए ₹ 58.16 लाख की लागत पर एक रॉक ड्रिलिंग रिग (बड़ा आकार) की आपूर्ति हेतु भारतीय खनन ब्यूरो (भा.ख.ब्यू.) नागपुर ने आदेश दिया (फरवरी 2006)।

रॉक ड्रिलिंग रिग (बड़ा आकार) का अंत में भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण, दक्षिण क्षेत्र, हैदराबाद, तथा भारतीय खनन ब्यूरो (भा.ख.ब्यू.) हैदराबाद द्वारा 22 मई 2006 को आपूर्तिकर्ता परिसर में निरीक्षण किया गया था तथा परेषिती को प्रेषित कर दिया गया था और उसे 26 जून 2006 को उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल को प्राप्त हुआ बतलाया गया था।

आपूर्तिकर्ता ने परेषिती से 'रिग' के संस्थापन एवं उसे चालू करने के लिए सुविधाजनक तिथि निर्धारित करने का निवेदन किया था तथा भा.ख.ब्यू. नागपुर ने उद्योग निदेशालय, मिजोरम को सूचित किया (19 जुलाई 2006) कि वह आपूर्तिकर्ता से रिग के संस्थापन एवं चालू करवाए और उसकी रिपोर्ट को भा.ख.ब्यू. नागपुर को प्रस्तुत करे। हालांकि, उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल ने भारतीय खनन ब्यूरो, नागपुर को सूचित किया कि आपूर्ति किया गया रिग स्थानांतरण समस्याओं के कारण पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं था तथा उन्हें ड्रिलिंग मशीन को खड़ा करने हेतु ट्रक चेसिस की आवश्यकता थी, तथा जब तक उनके प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया जाता तथा निष्पादित नहीं किया जाता, तब तक आपूर्ति किए गए रिग को चालू करना तथा भा.ख.ब्यू. को सूचना/रिपोर्ट भेजना अनुचित होता। हालांकि, इस पहलू को ठीक से निपटाया नहीं गया था तथा फाइल को केन्द्रीय भंडार द्वारा रखा नहीं गया था, जैसा कि भा.ख.ब्यू. द्वारा नोट किया गया था।

उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल (27 सितम्बर 2006) द्वारा ट्रक चेसिस की आवश्यकता एवं रिग की अनुपयुक्तता की सूचना की तिथि से छह

वर्षों से अधिक बीत जाने के पश्चात् केवल 29 फरवरी 2012 को भा.ख.ब्यू. द्वारा रिग के संस्थापन/चालू करने का मामला आपूर्तिकर्ता के साथ उठाया था। आपूर्तिकर्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तथा आज तक (अक्तूबर 2012) आपूर्ति किया गया उपकरण कार्यालय उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल में व्यर्थ पड़ा हुआ था।

बोलीकर्ताओं के लिए निर्देश और निविदा प्रस्तुत करने के नियम व शर्तें जो निविदा दस्तावेज का भाग थीं, में यह निर्दिष्ट था कि "मद की अच्छी हालत में प्राप्ति और प्रेषिती द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर उनके अधिष्ठापन/चालू करने और प्रशिक्षण के बाद रसीद सहित बिल के प्रति 30 दिनों के भीतर 100% भुगतान किया जाएगा"। तथापि यह पाया गया कि निविदा में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हुए आपूर्तिकर्ता के परिसर में उपकरणो के संयुक्त निरीक्षण (22 मई 2006), आपूर्तिकर्ता को भा.ख.ब्यू., नागपुर द्वारा प्रेषण निर्देश जारी करने (23 मई 2006) और प्रेषिती के परिसर में उपकरण की वास्तविक प्राप्ति (26 जून 2006) से पूर्व ही उद्योग निदेशालय, भूविज्ञान एवं खनन स्कंध, मिजोरम, आइजोल से प्राप्त उपकरण की प्राप्ति संबंधी पावती के प्रति (9 मार्च 2006) एक प्रारूप बीजक पर आपूर्तिकर्ता को पूर्ण और अंतिम भुगतान (₹ 58.16 लाख) कर दिया गया (17 मार्च 2006)।

इस प्रकार पहाड़ी भूभाग के लिए अनुपयुक्त उपकरण का चयन करने और समय पर आवश्यक कार्यवाही न करने से उपकरण पिछले छः वर्ष से अप्रयुक्त पड़ा रहा। भुगतान के नियमों व शर्तों का उल्लंघन करते हुए आपूर्तिकर्ता को भुगतान जारी करने से ठेकेदार अप्रवर्तनीय हो गया। परिणामस्वरूप प्रापण पर किया गया व्यय (₹ 58.16 लाख) निष्फल रहा और उत्तर-पूर्वी प्रदेशों हेतु सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रापण का विचारित उद्देश्य निष्फल सिद्ध हुआ। उत्तर में भा.ख.ब्यू. नागपुर (दिसम्बर 2012) ने तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि करते हुए यह बताया कि यह मामला प्रमुख सतर्कता अधिकारी, भा.ख.ब्यू. को भेजा गया है और निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

मामला जनवरी 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतिक्षित है।

अध्याय X : भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय

10.1 भारतीय समुदाय कल्याण योजना के लिए आत्मनिर्भर समग्र निधि का सृजन न किया जाना

भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय समुदाय कल्याण योजना हेतु संचित किए गए ₹ 23.95 करोड़ की आत्मनिर्भर समग्र निधि का सृजन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.00 करोड़ तक की राशि के ब्याज का नुकसान हुआ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2012-13 के प्रतिवेदन संख्या 13 के पैरा 3.1.2 से पता चला था कि 17 मिशनों तथा पोस्टों में "भारतीय सुमुदाय कल्याण निधि योजना" के कार्यान्वयन में विलंब के कारण अतिरिक्त शुल्क के रूप में ₹ 15.29 करोड़ की राशि संचित नहीं की गई थी।

भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय (भा.प्र.का.मं.) प्रशासनिक मंत्रालय है, जो कि भा.स.क.नि.यो. हेतु आवश्यक राजस्व सृजन तथा व्यय सहित सभी संबंधित मुद्दों को मॉनीटर एवं परिचालन हेतु दिशानिर्देश जारी करता है।

दिसम्बर 2010 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना का उद्देश्य संकटग्रस्त भारतीय प्रवासी नागरिक कल्याण गतिविधियों हेतु आकस्मिकता व्यय की पूर्ति करना था। योजना के लिए अपेक्षित निधियों का सृजन भारतीय मिशनों द्वारा वाणिज्यदूत संबंधी सेवाओं पर सेवा प्रभार द्वारा, भारतीय समुदाय द्वारा स्वैच्छिक अंशदान तथा भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय के बजटीय सहायता के माध्यम से किया जाएगा। शुरू में, बजटीय सहायता तीन वर्ष के लिए थी या फिर जब तक निधि आत्मनिर्भर हो जाए, जो भी पहले हो समग्र निधि[1] अपनी स्थापना के तीन वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर आत्मनिर्भर होने के लिए अभिप्रेत थी। इसके अतिरिक्त, विदेशी मामलों पर स्थायी समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में भा.स.क.नि. की कार्यपद्धति पर चिंता व्यक्त की, और प्रत्येक मिशन/पोस्ट में अंशदान तथा बजटीय सहायता द्वारा कुल संचित निधि की स्थिति, लाभान्वित श्रमिकों की संख्या तथा प्रत्येक स्थान पर हुए व्यय के बारे में जानना चाहा (मार्च 2011)। योजना में समग्र निधि का प्रावधान बनाते हुए उन्होंने इस बात को दोहराया ताकि संकट में श्रमिकों को निधि की कमी के कारणवश परेशानी न उठानी

[1] समग्र निधिः निधि का अर्थ है एक स्थायी निधि जिसको संगठन के अस्तित्व एवं प्रशासन हेतु अपेक्षित मूल व्यय के लिए रखा गया हो।

पड़े। भा.स.क.नि. के अंतर्गत समग्र निधि का सृजन करने की जिम्मेदारी भा.प्र.का.मं. की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 मिशनों एवं पोस्ट में, भा.स.क.नि. लेखाओं के अंतर्गत, मार्च 2012 तक ₹ 23.95 करोड़ संचित किया गया था। इन मिशनों में किसी ने भी अभी तक संचित राशियों में से समग्र निधि का सृजन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, यह शेष राशियाँ भा.स.क.नि. के चालू खातों में से दो माह से लेकर बाइस महीनों तक भिन्न अवधियों तक निष्क्रिय पड़ी रही थी। मिशनों ने इसमें से ₹ 76.95 लाख का उपयोग किया था (मार्च 2012 - **अनुबंध 12**)। इस प्रकार, किसी भी आपातिक आवश्यकता के बिना चालू खातों में राशि को रखकर, मंत्रालय ने ब्याज द्वारा ₹ 1.00 करोड़ के अतिरिक्त निधि को प्राप्त करने के अवसर को गंवाया था (मार्च 2012)। साथ ही संकट में श्रमिकों के कल्याण हेतु स्थायी निधि के सृजन का उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका था।

मामला मई 2013 में भा.प्र.का.मं. को भेजा गया था, उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय-XI :पोत परिवहन मंत्रालय

प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत निदेशालय

11.1 सुनामी से अब तक अं.सा.स्थि.नि.प्र.की पुनः स्थापना न करना तथा ₹ 75.14 लाख का निष्फल व्यय

विभाग द्वारा त्रूटिपूर्ण योजना के कारण सुनामी के आठ वर्षों के पश्चात भी आवश्यक मार्गनिर्देशन सहायता को पुनःस्थापित नहीं किया जा सका था जो आगे दिसंबर 2006 में उपकरण, जिसे अभी तक स्थापित नहीं किया गया था, की खरीद पर ₹ 75.14 लाख के निष्फल व्यय का कारण बना[#]

दिसम्बर 2004 के भूकंप तथा सूनामी ने कैम्पल बे, अण्ड़मान एवं निकोबार द्वीपसमूह में इंदिरा पाईंट प्रकाशस्तंभ पर स्थापित अंतरीय सार्वभौमिक स्थिति निर्धारण प्रणाली (अं.सा.स्थि.नि.प्र.), जिसने आवश्यक मार्गनिर्देशन सहायता के रूप में कार्य किया। इस स्टेशन की पुनःस्थापना के लिए, पोतपरिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (पो.स.प.रा.मं.) ने नवम्बर 2005 में ₹83.50 लाख[*] की पुरानी स्वीकृति दर पर एक फर्म को अं.सा.स्थि.नि.प्र. उपकरण की आपूर्ति, स्थापना तथा चालू करने हेतु इस अनुबंध के साथ आदेश दिया कि 13 महीनों अर्थात दिसंबर 2006 के भीतर उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना तथा चालू किया जायेगा। उपकरण, जिनकी जीवन-अवधि 10 वर्षों की है, की फर्म द्वारा निर्धारित समय अर्थात दिसंबर 2006 के भीतर आपूर्ति कर दी गई थी। ₹ 75.14 लाख की 90 *प्रतिशत* राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को मार्च 2007 में किया गया था।

इसी बीच, मार्गनिर्देशन सहायता की पुनःस्थापना हेतु अण्ड़मान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने, मार्च 2005 में किये गये अनुरोध के आधार पर, निदेशक प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत, पोर्ट ब्लेयर, (नि.प्र.प्र.) को कैम्पल बे में एक हैक्टर भूमि आबंटित की जिसे अगस्त 2006 में अधिकार में लिया गया था। तथापि, नि.प्र.प्र. ने पाया कि भूमि उनकी आवश्यकता के लिये अनुपयुक्त थी क्योंकि यह समुद्र से 60 मीटर की दूरी तथा लगभग समुद्र के स्तर पर थी तथा लगभग 30 मीटर ऊँचाई के पहाड़ के सामने थी जो अं.सा.स्थि.नि.प्र.सिग्नलों के संचारण में बाधा डालेगी। नि.प्र.प्र. ने प्रशासन को वायु में 360° परिधि के बिना बाधा वाले अधिक ऊँचे स्थान पर भूमि के पुनः आबंटन हेतु अनुरोध किया। नि.प्र.प्र.तथा प्रशासन के बीच लम्बे पत्राचार के पश्चात सितम्बर 2007 में भूमि

[*] केवल अं.सा.स्थि.नि.प्र. उपकरण की लागत

आबंटित की गई थी तथा निदेशालय द्वारा जनवरी 2008 में अधिकार में ली गई थी। अगस्त 2008 में, वन्य अनुमति तथा भू-तकनीकी उप-मृदा जांच के पश्चात ₹ 1.92 करोड़ के कैम्पल बे में अं.सा.स्थि.नि.प्र.स्टेशन की स्थापना, कैम्पल बे में स्टाफ क्वार्टरों, निरीक्षण क्वार्टरों तथा तकनीकी भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। निर्माण का कार्य समाप्त हो गया था तथा दिसम्बर 2012 में कैम्पल बे में अं.सा.स्थि.नि.प्र.को ट्रायल आधार पर स्थापित कर दिया गया है। तथापि, अं.सा.स्थि.नि.प्र. अभी तक भी चालू नही किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- अं.सा.स्थि.नि.प्र.उपकरण अनुमानित थे तथा उचित भूमि की उपलब्धता से पहले सुपूदर्गी ली थी ।.
- अं.सा.स्थि.नि.प्र. पोर्ट ब्लेयर में पड़ी थी । इसे लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर कि उपकरण पोर्ट ब्लेयर में व्यर्थ पड़ा था,के पश्चात केवल अक्तूबर 2012 में जाकर ही कैम्पल बे भेजा गया था ।
- यहां तक की स्थापना तथा ट्रायल रन से पहले ही अं.सा.स्थि.नि.प्र.की वारंटी समाप्त हो चुकी थी।

इस प्रकार, दिसबंर 2006 में प्रापण की गई तथा 10 वर्षों की जीवन अवधि वाली एक महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन सहायता को स्थल चयन तथा निर्माण में विलम्ब के कारण 6 वर्षों के पश्चात ही स्थापित किया गया था। उपकरण पहले ही अपनी 60% जीवन अवधि खो चुका था। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 2004 से आवश्यक मार्गनिर्देशन सहायता की पुनःस्थापना का मुख्य उदेश्य विफल था।

प्रकाशस्तम्भ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय, नौएडा (प्र.प्र.म.नि.) ने अपने उत्तर में बताया (मई 2013) कि क्षेत्र में सुनामी के कारण हानियाँ विशाल तथा अपूर्व थी जिसकी योजना के समय लगभग कल्पना नहीं की गई थी। तथापि, तथ्य यह है कि अं.सा.स्थि.नि.प्र. हेतु आदेश नवम्बर 2005 में, सुनामी आने के लगभग एक वर्ष पश्चात दिया गया था। इस प्रकार प्र.प्र.म.नि. के पास सुनामी द्वारा क्षेत्र में हुई हानि की सीमा का निर्धारण करने तथा तदनुसार योजना तैयार करने हेतु पर्याप्त समय था। उत्तर ने यह भी बताया गया कि आबंटित भूमि में "अकल्पनीय विकास" अपेक्षित था, पर्यावरणीय प्रतिबंधों/बाधाओं के कारण पहुंच सड़क नहीं बनाई जा सकी, वन अनुमति अपेक्षित थी, जिसका परिणाम असामान्य विलम्ब तथा पहुँच सड़क को अभी तक वाहन योग्य नहीं बनाये जा सकने में हुआ तथा इसलिए 24X7 परिचालन को सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित डीजल जनरेटर सेटों को केवल अब ले जाया जा सका था। उत्तर ने स्वंय

दर्शाया कि विभाग ने विभिन्न अन्य वास्तविकताओं जो अं.सा.स्थि.नि.प्र.स्टेशन के निर्माण में देरी कर सकते हैं, को ध्यान में रखे बिना अं.सा.स्थि.नि.प्र.का प्रापण किया था[$].

इस प्रकार, विभाग द्वारा त्रूटिपूर्ण योजना के कारण सुनामी के आठ वर्षों के पश्चात भी आवश्यक मार्गनिर्देशन सहायता को पुनःस्थापित नहीं किया जा सका था जो आगे दिसम्बर 2006 में उपकरण, जो अपनी 60 *प्रतिशत* जीवन अवधि के लिए व्यर्थ रहा तथा अभी तक चालू नहीं किया गया है, की खरीद पर ₹75.14 लाख के निष्फल व्यय का कारण बना।

मामला अप्रैल 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतिक्षित था।

अध्याय XII : कपड़ा मंत्रालय

12.1 निर्मित फ्लैटों के क्रय में अत्यधिक बिलंब के परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हुई

गुवाहाटी में आवासीय फ्लैटों के निर्माण में विलंब के कारण ₹ 1.67 करोड़ की ब्याज की हानि एवं लागत में वृद्धि के अलावा सात वर्षों से अधिक समय तक ₹ 2.38 करोड़ अवरुद्ध हुए।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) {वि.आ.(ह)}, नई दिल्ली को अपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (उ.पू.क्षे.का.), गुवाहाटी से क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र (क्षे.डि.त.वि.के.), गुवाहाटी तथा उ.पू.क्षे. कार्यालय के स्टाफ एवं कर्मचारियों हेतु ₹ 5.36 करोड़ की कुल लागत पर आवासीय क्वार्टरों के लिए 40 निर्मित फ्लैटों को क्रय करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था (फरवरी 2006)। बेलटोल, गुवाहाटी में एक राज्य सरकार संगठन, असम राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड (अ.रा.स.आ.सं.लि.) द्वारा इन फ्लैटों का निर्माण किया जाना था। 24 महिनों के भीतर कार्य को पूर्ण करना था तथा फ्लैटों को उ.पू.क्षे.का. को सौंपा जाना था। ₹ 3.54 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर 40 से 24 संख्या के फ्लैटों में संशोधन के पश्चात मार्च 2006 में कपड़ा मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। अनुमोदन में 24 अलग-अलग तरह के फ्लैटों के निर्माण हेतु ₹ 2.31 करोड़ की निर्माण लागत एवं ₹ 1.23 करोड़ की भूमि लागत शामिल थी। उपरोक्त में से, मार्च 2006 में अ.रा.स.आ.सं.लि. को ₹ 2.38 करोड़ की अग्रिम राशि (भूमि की 100 *प्रतिशत* लागत के रूप में ₹ 1.23 करोड़ तथा निर्माण लागत के 50 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 1.15 करोड़) को जारी कर दिया गया था।

संबंधित अभिलेखों/फाइलों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों को उजागर किया:

1. अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी निधियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अ.रा.स.आ.सं.लि. एवं उ.पू.क्षे.का. के बीच कार्य शुरू करने के लिए समझौता विलेख पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।

2. 24 महीनों के लक्षित समापन के प्रति, 07 वर्षों की देरी के पश्चात (अप्रैल 2013) कार्य अंशिक रूप से पूरा हुआ था (केवल चारदीवारी, इमारत की नींव का काम, गहरे नलकूप का संस्थापन)।

3. उ.पू.क्षे.का. से कार्य की भौतिक एवं वित्तिय प्रगति को मॉनिटर करना तथा वि.आ.ह., नई दिल्ली को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। चूकिं कार्य

की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थीं, वि.आ.ह. के कार्यालय, नई दिल्ली ने अ.रा.स.आ.सं.लि. से परियोजना में विलंब/समापन न होने तथा उनसे क्यों ₹2.38 करोड़ की राशि को दांडिक ब्याज के साथ वसूली न करने के कारण बताने को कहा (जून 2009)। अपने उत्तर में, अ.रा.स.आ.सं.लि. ने सूचित किया कि स्थानीय विधायक द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण विलंब हुआ था। भूमि के क्रय, चारदीवारी बनाने तथा इमारत की नींव का कार्य करने में पहले ही व्यय किया जा चुका था। विधायक के साथ विवाद को अगस्त 2009 में सुलझाया गया बताया गया था।

4. अ.रा.स.आ.सं.लि. ने (अक्तूबर-2009) उ.पू.क्षे.का. को सूचित किया कि कार्य स्थल पर पहुँच पुलिया को गुवाहाटी नगर निगम (गु.न.नि.) द्वारा नष्ट कर दिया गया था तथा कार्य स्थल तक निर्माण सामग्री ले जाने के लिए अन्य पुलिया बनानी पड़ेगी।

5. अ.रा.आ.सं.लि. ने उ.पू.क्षे.का, गुवाहाटी को सूचित किया (नवम्बर 2010) कि पूर्व/मूल संस्वीकृत लागत पर कार्य जारी रख पाना संभव नहीं हो पाएगा तथा 93 *प्रतिशत* की मूल्य वृद्धि के साथ ₹ 4.47 करोड़ (₹ 2.32 करोड़ के अनुमान से ऊपर) का संशोधित निर्माण लागत अनुमान प्रस्तुत किया था। लागत में बढ़ोत्तरी के लिए अ.रा.आ.सं.लि. द्वारा बताए गए कारणों में से एक, मूल प्रस्ताव में लिफ्ट, जनरेटर, ट्रांसफोर्म, मोटर पम्प, स्टील का दरवाजा आदि जैसी मदों का समावेश न किया जाना था।

6. अ.रा.आ.सं.लि. द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित अनुमान (नवम्बर 2010) वि.आ.ह के कार्यालय द्वारा मई 2013 तक लो.नि.वि. द्वारा सत्यापन की मांग हेतु अनुमोदित नही किए गए थे।

7. अभिलेखों पर नवम्बर 2011 से अ.रा.आ.सं.लि. के साथ पत्र-व्यवहार नहीं पाया गया था।

परियोजना को संस्वीकृत/अनुमोदित करते समय उ.पू.क्ष.का. के कार्यालय द्वारा अ.रा.आ.सं.लि. द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक प्रस्ताव की उचित संवीक्षा से उपरोक्त मदों के छूटने को रोक सकती थी। वि.आ.ह, नई दिल्ली ने स्वीकार किया कि यह बात अनजाने में अनुमानों को अनुमोदित करते समय विभाग द्वारा नोट नहीं की गई थी। इस प्रकार, उ.पू.क्षे.का. द्वारा प्रस्ताव के प्रसंस्करण में कमी, लापरवाही तथा उसके पश्चात

अपर्याप्त मॉनीटरिंग ₹ 1.67 करोड़ (10[1] प्रतिशत की दर पर परिकलित) के ब्याज की परिणामी हानि के साथ 7 वर्षों (अप्रैल 2013) की अवधि हेतु ₹ 2.38 करोड़ की राशि के अवरूद्ध रहने का कारण बनी। इसके अतिरिक्त, उ.पू.क्षे. कार्यालय एवं क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र (क्षे.डि.त.वि.के.), गुवाहाटी के स्टाफ को आवास प्रदान करने का उद्देश्य अधूरा रहा।

मामले को जनवरी 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जून, 2013 तक प्रतिक्षित था।

[1] निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने में अनुदेयी द्वारा विफलता के मामले में अनुदानों की वसूली हेतु सा.वि.नि. नियम 209 में निर्धारित दर।

अध्याय XIII : पर्यटन मंत्रालय

13.1 विज्ञापन अभिकरण को अभिकरण सेवा शुल्क का अनियमित भुगतान

भारतीय पर्यटन के फ्रैंकफर्ट, पेरिस, अम्सटरडम और मिलान स्थित कार्यालय ने विज्ञापन अभिकरण को पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के विपरीत प्रावधान वाले एक कार्य-साधक समझौते के आधार पर अभिकरण सेवा शुल्क का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2009 से मई 2012 तक के दौरान ₹ 88.67 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

फ्रैंकफर्ट के भारतीय पर्यटन कार्यालय (आई.टी.एफ.) के क्षेत्रीय निदेशक (क्षे.नि.) ने यूरोप क्षेत्र (यू.के. के अतिरिक्त) के फ्रैंकफर्ट, पेरिस, अम्सटरडम और मिलान स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों के लिए एक संप्रेषण प्रणाली के विकास व क्रियान्वयन हेतु विज्ञापनदाता एजेंसियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की (जून 2009)। आइ.टी.एफ. का यह कदम भारत को एक पसंदीदा पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने का विचार करता था जिससे भारत के वैश्विक पर्यटन बाजार में हिस्से और विदेशी मुद्रा विनियम से होने वाले अर्जन में वृद्धि हो। पांच एजेंसियों से प्राप्त बोलियों में से आई.टी.एफ. ने तीन एजेंसियों अर्थात मेसर्स सर्विस-प्लान, म्यूनिख, ग्रे कांसेल, फ्रैकफर्ट और वरबीगटूर फ्रैंकफर्ट का अंतिम रूप से चयन किया और एक एजेंसी नियुक्त करने हेतु पर्यटन मंत्रालय को सिफारिश की।

पर्यटन मंत्रालय, विदेशी विपणन विभाग ने मेसर्स सर्विस-प्लान, म्यूनिख को यूरोप क्षेत्र के लिए आई.टी.एफ के लिए विज्ञापनकर्त्ता एजेंसी के रूप में एक वर्ष के लिए नियुक्ति किए जाने को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया (नवम्बर 2009) कि एजेंसी कार्यालय से कोई शुल्क नहीं लेगी और इसे संचार एजेंसियों से कमीशन के रूप में अपना भुगतान प्राप्त होगा। मंत्रालय/आई.टी.एफ. द्वारा प्रदान किए गए क्रिएटिव्स के साथ किए गए प्रचार अभियान का प्रबंध करने के लिए कोई मूल्य प्रभारित नहीं किया जाएगा। जिन सेवाओं पर वास्तविकता में प्रभार लिया जाएगा, उनमें आवश्यक होने पर नए अभिकल्प/क्रिएटिव प्रदान करना, प्रदत्त क्रिएटिव में परिवर्तन करना, पाठ्यवस्तु का अनुवाद, वर्तमान प्रारूप का रूपांत्तर और प्रस्तुतीकरण संबंधी अन्य सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने आई.टी.एफ. को उपरोक्त् शर्त को जोड़ते हुए भारतीय पर्यटन कार्यालय, लंदन, के पुनरीक्षित किए जा चुके समझौते की तर्ज पर एक समझौता तैयार करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आई.टी.एफ. ने मंत्रालय के निर्देशानुसार समझौता किए बगैर मैसर्स सर्विसप्लान की सेवाओं का उपयोग करना आरंभ कर दिया। एक वर्ष के विलम्ब के बाद और मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बगैर क्षे.नि. आई.टी.एफ. ने एजेंसी के साथ एक कार्यकारी समझौता 7 दिसम्बर 2010 को किया जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि विज्ञापन तथा संचार माध्यम की लागत की इनवॉयस प्रति पखवाड़े बनाई जाएगी और भुगतान 14 दिनों के भीतर किया जाएगा जिसमें 15% एजेंसी सेवा शुल्क सम्मिलित होगा।

क्षे.नि., आई.टी.एफ. ने एजेंसी के साथ 16 दिसम्बर 2010 को एक अन्य समझौता भी किया, जो मंत्रालय के निर्देशानुसार भारतीय पर्यटन कार्यालय लंदन (आई.टी.एफ.) द्वारा किए गए समझौते के समान था और जिसमें कोई शुल्क अदा न किए जाने का प्रावधान था, परंतु इसे लागू नहीं किया गया। सहायक निदेशक (लेखों), आई.टी.एफ. ने 16 दिसम्बर 2010 को हस्ताक्षरित समझौतें के अंतर्गत इनवॉयस के लिए एजेंसी द्वारा शुल्क के दावे के लिए स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि ऐसे भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था । तथापि क्षे.नि., आई.टी.एफ. ने कार्यसाधक समझौतें के अनुसार शुल्क अदा करने का निर्देश दिया। क्षे.नि., आई.टी.एफ. ने कार्यकारी समझौते को आगे 11 जनवरी 2011 को नवीकृत कर दिया। हालांकि, 19 जुलाई 2011 को एक अन्य समझौता 31 मार्च 2012 की अवधि के लिए मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में किया गया, परंतु इसे भी लागू नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, आई.टी.एफ. और पेरिस, अम्सटरडम और मिलान के पर्यटन कार्यालयों ने मैसर्स सर्विसप्लान को नवम्बर 2009 से मई 2012 को ₹ 88.67[1] लाख (137860.62 यूरो) के शुल्क का भुगतान कार्यकारी समझौते के आधार पर किया जो मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं था। इसके अतिरिक्त अक्तूबर 2011 से मार्च 2011 की अवधि हेतु शुल्क के लिए ₹18.35 लाख के इनवॉयस का भुगतान मैसर्स सर्विसप्लान को जारी करना लंबित था।

यह मामला मंत्रालय को जनवरी 2012 को सूचित किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों (मार्च 2013) के आधारभूत तथ्यों और आंकड़ों को स्वीकार करते हुए यह बताया कि:

[1] फ्रैंकफर्ट ₹ 76.62 लाख, पेरिस ₹ 9.45 लाख, अम्सटरडम ₹ 2.28 लाख, मिलान ₹ 0.32 लाख

- निवर्तमान क्षे.नि., आई.टी.एफ. ने एजेंसी के साथ एकपक्षीय रूप से कार्य साधक समझौता किया और मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना एजेंसी सेवा शुल्क के रूप में 15% एजेंसी कमीशन अदा करने का प्रावधान सम्मिलित किया।

- दोषी सरकारी कर्मचारी अर्थात निवर्तमान क्षे.नि., आई.टी.एफ., जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु एक अनुशासनात्मक मामला आरंभ किया जा रहा है और सेवानिवृत्ति की देय राशि का निपटान व्यक्तिगत वसूली संबंधी लेखापरीक्षा आपत्तियों के निबटान होने पर ही की जाएगी ।

- 15% एजेंसी शुल्क घटाकर लंबित बिलों का भुगतान मैसर्स सर्विसप्लान को जारी कर दिया गया है।

- कार्यसाधक समझौते द्वयर्थक होने के कारण और उनकी विश्वसनीयता संदेहप्रद होने के कारण विधि मंत्रालय की सलाह मांगी गई है जिससे मैसर्स सर्विसप्लान द्वारा मुकदमा करने की स्थिति में विधिक सहायता लेने की संभावना पर विचार किया जा सके ।

ये तथ्य मंत्रालय द्वारा क्षे.नि., आई.टी.एफ. की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की कमी की ओर संकेत करते है, जिससे विज्ञापनकर्त्ता एजेंसी की ₹ 88.67 लाख का अनियमित भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा में ₹ 18.35 लाख के अदा न किए गए इनवॉयस का भुगतान 15% एजेंसी शुल्क घटाकर जारी किए जाने के मंत्रालय के उत्तर की पुष्टि नहीं हो पाई।

अध्याय XIV : संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

अण्डमान लोक निर्माण विभाग

14.1 निष्फल व्यय

अण्डमान लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य के आरंभ से पूर्व, तटीय विनियमन क्षेत्र अनुमति प्राप्त न करने की चूक के कारण एवं अपर्याप्त डिजाइन के परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा दो बाँधों के निर्माण पर ₹ 0.31 करोड़ की अतिरिक्त देयता हुई।

कृषि भूमि में समुद्री जल के प्रवेश को रोकने की दृष्टि से निर्माण विभाग, अण्डमान लोक निर्माण विभाग, केम्पबेल बे द्वारा दो निर्माण कार्यों, कैम्पबैल बे में गाँधी नगर तथा शास्त्री नगर में (प्रत्येक 500 मीटर) में बाँधों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी।

प्रत्येक कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (प्र.अ. एवं व्य.सं.) ₹ 1.70 करोड़ की दर पर दिये गये थे (जनवरी 2008)। अनुमानों को गाँधी नगर हेतु ₹ 3.19 करोड़ तथा शास्त्री नगर हेतु ₹ 3.20 करोड़ के लिए संशोधित (अप्रैल 2009) किया गया था। संशोधित अनुमानों को संस्वीकृत नहीं किया गया तथा उन्हें प्रचलित निर्माण स्थल परिस्थितियों के अनुरूप पुनः तैयार करने हेतु मार्च 2010 में लौटा दिया गया।

संशोधित प्र.अ. एवं व्य.सं. प्राप्त किए बिना ही, एक ठेकेदार को गाँधी नगर का निर्माण कार्य ₹ 1.85 करोड़ पर (अक्तूबर 2010) तथा शास्त्री नगर का निर्माण कार्य एक अन्य ठेकेदार को ₹ 1.76 करोड़ पर प्रदान किए गए। दोनों निर्माण कार्यों के आरंभ एवं समापन की निर्धारित तिथियां क्रमशः 9 नवम्बर 2010 तथा 8 जुलाई 2011 थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गाँधी नगर में ₹ 1.14 करोड़ की कीमत का 47 *प्रतिशत* निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था जिसके प्रति ठेकेदार को ₹ 0.97 करोड़ का भुगतान किया गया तथा शास्त्री नगर में ₹ 0.75 करोड़ की कीमत का 16 *प्रतिशत* निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, जिसके प्रति ठेकेदार को ₹ 0.61 करोड़ का भुगतान किया गया था।

इस बीच, पर्यावरण एवं वन विभाग (जून 2011) ने निर्माण कार्यों हेतु तटीय विनियमन क्षेत्र (त.वि.क्षे.) की अनुमति मांगी, तथा इसके अभाव में विभाग द्वारा दोनों निर्माण कार्यों को रोक दिया गया (अक्तूबर 2011)। चक्रवाती मौसम (नवम्बर-दिसम्बर 2011) के

दौरान, दीवारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी तथा यह मत दिया गया कि खुले समुद्र के समक्ष केवल कंक्रीट संरचना गंभीर लहरों के प्रभाव को झेल नहीं सकेगी।

विभाग ने (फरवरी 2012) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन (के.ज.वि.अ.स्टे.) के समक्ष दोनों स्थलों हेतु बांध के उपयुक्त डिजाइन हेतु प्रस्ताव रखा, जो कि अभी प्राप्त किया जाना बाकी है।

वास्तविकता ये है कि अनुपयुक्त डिजाइन और विभाग की तरफ से कार्य आरंभ होने से पहले त.वि.क्षे. अनुमति प्राप्त न करने की चूक के परिणामस्वरूप दो बाँधों के निर्माण पर ₹ 0.31 करोड़ की अतिरिक्त देयता के साथ ₹ 1.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। साथ ही, इसने कृषि भूमि की रक्षा का एकमात्र उद्देश्य भी विफल हो गया।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2012 में सूचित कर दिया गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय

14.2 निष्फल व्यय

सुरक्षा मुद्दों एवं लागू होने वाले अधिनियमों तथा पो.प.मं., भा.स. और म.नि.पो.प. के निर्देशों की उपेक्षा करते हुए, पो.प.से.नि. ने दो जहाजों के लिए इंजन के दोषपूर्ण डिजाइन अनुमोदित कर दिए जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों से अधिक के लिए जनता को उनकी सेवाओं से वंचित रखने के अलावा ₹16.35 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोतपरिवहन सेवाएं निदेशालय (पो.प.से.नि.) ने अंतर्देशीय जहाज अधिनियम, 1917 (अं.ज. अधिनियम) के अंतर्गत दो 100 यात्री-सह-वाहन नौका (जहाज) का निर्माण प्रस्तावित किया (मई 2005) तथा तदनुसार, व्यय के आवश्यक अनुमोदन एवं संस्वीकृति हेतु पोतपरिवहन मंत्रालय (पो.प.मं.), भा.स. को लिखा। इन जहाजों को एक ओर बारतंग एवं मध्य जलडमरूमध्य तथा दूसरी ओर गांधी घाट एवं उत्तरा जेट्टी को अलग करती हुई ज्वारीय खाड़ियों पर चलाया जाना था।

जनवरी, 2006 में स्थायी वित्त समिति (स्था.वि.स.) की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जहाँ पर यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या परिचालन के प्रस्तावित क्षेत्रों को अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित किया गया था या नहीं[1]। अं. एवं. नि. प्रशासन (प्रशासन)

[1] अंतर्देशी जहाज अधिनियम, 1917 की धारा 70 के अंतर्गत, केवल केन्द्र सरकार 'ज्वारीय जल' को परिभाषित कर सकती है तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पारिभाषित कर सकता है कि इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु कितने ज्वारीय जल को अंतर्देशीय जल माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, "अंतर्देशीय जल" का अभिप्राय किसी भी नहर, नदी, सरोवर या अन्य नैगम्य जल से है।

द्वारा शीघ्र ही (फरवरी 2006) यह स्पष्ट किया गया कि ज्वारीय खाड़ी का जल सीमा क्षेत्र, अंतर्देशीय जहाज सीमा के अंतर्गत नहीं आता था। इसका अर्थ था कि वहाँ चलाए जा रहे वाहनों को अं.ज. अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। तदनुसार, स्था.वि.स. ने खाड़ी जल क्षेत्र में जहाजों के परिचालन की सुरक्षा के बारे में महानिदेशालय पोतपरिवहन (म.नि.पो.प.) से एक रिपोर्ट मांगे जाने की अनुशंसा की, क्योंकि उनका निर्माण अं.ज. अधिनयम के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था न कि व्यापारिक पोतपरिवहन (व्या.पो.प.) अधिनियम में जोकि अं.ज. सीमाओं से बाहर चलाए जाने वाले सभी जहाजों के निर्माण पर लागू होता था। अनुमोदन केवल म.नि.पो.प. से सुरक्षा मंजूरी के उपरांत दिया जाना था।

तदनुसार, पो.प.मं. ने प्रशासन को अवगत कराया (मार्च 2006) कि अं.ज. श्रेणी के अंतर्गत निर्माण केवल म.नि.पो.प. द्वारा पूर्व सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात ही किया जा सकता था।

म.नि.पो.प. ने स्पष्टतः बताया (मार्च 2006) कि अं.ज. सीमाओं से परे परिचालन करने के इच्छुक यात्री जहाजों को परिचालन क्षेत्र के अनुसार श्रेणी पर लागू प्रासंगिक व्या.पो.प. नियमों का पालन करना पड़ेगा।

यह तथ्य कि पो.प.से.नि. को पो.प.मं. के निर्देशों एवं म.नि.पो.प. के स्पष्टीकरण की जानकारी थी, प्रशासन के साथ उसके पत्राचार (जून 2006) से स्पष्ट था जिसमें उपरोक्त दोनों तथ्यों को स्वीकार करते हुए, उसने तर्क दिया कि व्या.पो.प. श्रेणी जहाजों में परिचालन बाध्यताएं थी और इसलिए, खाडियों में अं.ज. श्रेणी जहाजों का प्रचालन आवश्यक था। इसके बावजूद, म.नि.पो.प. से सुरक्षा अनुमति के मुद्दे का समाधान किए बिना ही, पो.प.से.नि. ने ₹15.50 करोड़ की कुल लागत पर अंतर्देशीय जहाज अधिनियम के अंतर्गत जहाजों के निर्माण एवं वितरण के लिए मैसर्ज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स तथा इंजीनीयर्स लिमिटेड, कोलकाता (निर्माता) के साथ अनुबंध किया (अक्तूबर 2006)।

पो.प.से.नि. ने (मई 2007) जहाज के निर्माण के दौरान उसके आरेखन, डिजाइन एवं विनिर्देशन को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में राष्ट्रीय जहाज डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र, विशाखापटनम (रा.ज.डि.अ.के.) को नियुक्त किया। इस प्रकार पो.प.से.नि. ने तथ्यों से अवगत होने के बावजूद भी रा.ज.डि.अ.के. को प्रक्षेपित किया कि जहाजों का परिचालन अं.ज.सीमाओं में किया जाना था। तदनुसार,

रा.ज.डि.अ.के. ने जहाज को 200 कि.वा. की क्षमता की मोटर चालित एच.आर.पी. हाइड्रोजेट्स के साथ डिजाइन किया था।

दोनों जहाजों की सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि जनवरी 2008 थी। इन्हें वास्तव में ₹ 16.35 करोड़ की लागत पर जनवरी 2009 में सुपुर्द किया गया तथा इनका नाम एम.वी. एफरा बे तथा एम.वी. कर्मातंग रखा गया था।

जहाजों के परीक्षण (जनवरी 2009) से पता चला कि जहाजों को डिजाइन करते समय परिचालन क्षेत्र के वर्तमान पवन एवं प्रवाह कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया था। 200 कि.वा. विद्युत चालित मोटरें इतनी प्रभावी नहीं थी कि वह इन जहाजों पर पवन के प्रभाव एवं ज्वारीय बल का सामना कर सके और इस प्रकार उन्हें प्रचंड पवन/प्रवाह की परिस्थितियों में, जो कि पोर्ट ब्लेयर में साल के सात से आठ माह के लिए रहती थीं, उनका परिचालन नहीं किया जा सकता था। यदि जहाजों को म.पो.प. श्रेणी के लिए डिजाइन एवं निर्माण किया गया होता जैसा कि म.नि.पो.प. द्वारा सुझाव दिया गया था, तो इन समस्याओं को टाला जा सकता था।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, विज़ाग परिसर (भा.स.वि.) (भूतपूर्व रा.ज.डि.अ.के.) ने जहाजों का निरीक्षण किया (फरवरी 2010) और इन जहाजों के परिचालन हेतु इन्हें काफी परिवर्धन और परिवर्तन के साथ पुनः डिजाइन करने का सुझाव दिया। भा.स.वि. द्वारा परीक्षा एवं परीक्षण अभी भी चल रहे थे (दिसम्बर 2012) जिसके कारण जहाज निष्क्रिय पड़े हुए थे।

पो.प.से.नि. ने जहाजों के निर्माण हेतु अपने प्रारंभिक प्रस्ताव को तैयार करते समय अंतर्देशीय जहाज एवं व्यापारिक पोतपरिवहन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की उपेक्षा की थी तथा निर्माता को कार्य आदेश देने से पूर्व म.नि.पो.प. से सुरक्षा अनुमति लेने से संबंधित स्था.वि.स. तथा पो.प.मं., भा.स. के निर्देशों का उल्लंघन किया था। इस प्रकार, उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा एवं हिफाजत से समझौता किया। संगत प्रावधानों का गैर-अनुपालन और उसके कारण किए गए गलत प्रक्षेपण के परिणामस्वरूप जहाजों का डिजाइन दोषपूर्ण था तथा उनकी निष्क्रियता के कारण ₹ 16.35 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों से अधिक के लिए जनता को उनकी सेवाओं से वंचित रखा गया था।

मामले को मंत्रालय को अक्तूबर 2012 में और फिर से जुलाई 2013 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर जुलाई 2013 तक प्रतीक्षित था।

14.3 क्षति सुधार कार्य एवं मरम्मत की लागत सहित ₹ 3.73 करोड़ के जुर्माने की गैर-वसूली

पोतपरिवहन सेवाएं निदेशालय की निष्क्रियता के कारण ₹ 3.73 करोड़ के जुर्माने सहित जहाज की मरम्मत की लागत मैनिंग एजेंट से वसूल नहीं की जा सकी।

एम.वी. लॉंग आइलैण्ड जहाज की मैनिंग के लिए पोतपरिवहन सेवाएं निदेशालय (पो.प.से.नि.) ने मैसर्स ए.बी.एस. मरीन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, चैन्नई, (मैनिंग एजेंट) के साथ अनुबंध (दिसम्बर 2008) किया। मैनिंग एजेंट को प्रति माह ₹ 12.67 लाख का भुगतान 12.36 *प्रतिशत* के सेवा कर सहित किया जाना था।

अनुबंध के अनुसार, मैनिंग एजेंट या उसके कर्मचारी वर्ग की ओर से लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के कारण जीवन की हानि, दुर्घटना या जहाज को हुए वित्तीय नुकसान को चूक माना जाना था। पो.प.से.नि. के पास इस प्रकार की चूक के कारण हुए वित्तीय नुकसान की वसूली करने का अधिकार था। साथ ही, यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय पर मैनिंग एजेंट की गलती के कारण यदि जहाज अनुपलब्ध हुआ, तो इस अवधि के लिए प्रति दिन वार्षिक शुल्क के 0.75 *प्रतिशत* का जुर्माना लगाया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जुलाई 2009 में जहाज केम्पबेल बे के निकट समुद्र तल से टकरा गया था। जहाज का तल बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गया था, तथा चार ताजे पानी के टैंक फट गये थे। इस दुर्घटना के कारण, जहाज की भारी मरम्मत करनी पड़ी तथा वह जुलाई 2009 से जुलाई 2010 (367 दिन) की अवधि के लिए अनुपलब्ध रहा।

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में, तकनीकी प्रबंधक, भारतीय पोत परिवहन निगम (भा.पो.प.नि.) ने (अगस्त 2009) जहाज के समुद्र तल से टकराने की घटना का कारण कई चूकों के पीछे मैनिंग एजेंट के मास्टर तथा ड्यूटी अधिकारियों की ओर से की गई अनेक चूकों तथा नौवहन त्रुटियों को जिम्मेदार ठहराया।

चूंकि, जहाज़ 367 दिनों की अवधि हेतु अनुपलब्ध था, भा.पो.प.नि. से ब्यौरा प्राप्त होने पर मरम्मत व सुधार की लागत के अलावा, मैनिंग एजेंट से ₹ 3.73 करोड़[2] का जुर्माना

[2] मैनिंग शुल्क 12.36% प्रतिमाह सेवा कर सहित ₹ 12,67,200 की दर पर भुगतान किया जाना था। अतः, सेवा कर को हटाने के पश्चात, प्रतिमाह देय निवल राशि ₹ 11,27,803 होगी। जुर्माना= भुगतान किया गया वार्षिक शुल्क (12 माह X ₹ 11,27,803 = ₹ 1,35,33,636) X 0.75% = =1,01,502 X367 दिन = ₹3,72,51,234 अर्थात् ₹3.73 करोड़

वसूल किया जाना था। तथापि, पो.प.से.नि. ने मैनिंग एजेंट पर न तो कोई जुर्माना लगाया और न ही मरम्मत की लागत को वसूल किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने पो.प.से.नि. को भा.पो.प.नि. के साथ मामले का अनुसरण करने तथा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार मैनिंग एजेंट पर जुर्माना लगाने के निर्देश (फरवरी 2010) दिए थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (सितम्बर 2012) से पूर्व तक पो.प.से.नि. ने भा.पो.प.नि. के साथ किसी भी समय मामले का आगे अनुसरण नहीं किया। पो.प.से.नि. द्वारा मैनिंग एजेंट से वसूली हेतु कोई भी कार्रवाई प्रारंभ न किए जाने का कारण भा.पो.प.नि. से विवरणों की प्राप्ति न होना बताया गया था (अक्तूबर 2012)।

पो.प.से.नि., न तो भा.पो.प.नि. से क्षति की मात्रा से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त कर सका और न ही भा.पो.प.नि. ने अपने द्वारा प्राप्त बीमा की राशि के बारे में सूचित (अप्रैल 2013) किया।

पो.प.से.नि. ने आगे बताया (मई 2013) कि मैनिंग एजेंट के बिलों से 367 दिनों हेतु जहाज की अनुपलब्धता के प्रति ₹ 3.73 करोड़ के जुर्माने के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा क्षति मरम्मत लागत की वसूली भा.पो.प.नि. से विवरणों की प्राप्ति के पश्चात कर ली जाएगी।

मामला नवम्बर 2012 में गृह मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर मई 2013 तक प्रतीक्षित था।

14.4 जुर्माने की गैर-वसूली

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय द्वारा जुर्माना करने में निष्क्रियता के कारण भारतीय पोत परिवहन निगम से ₹ 2.18 करोड़ की राशि की गैर वसूली के अतिरिक्त द्वीपों के मध्य उचित संयोजकता से आम जनता को वंचित रखा गया।

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय (पो.प.से.नि.) ने अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) के 75/100 यात्री क्षमता के 18 जलयानों के तकनीकी प्रबंधन हेतु अप्रैल 2004 में पांच वर्षों की अवधि के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम लि. (भा.पो.प.नि.) के साथ एक अनुबंध किया। प्रबंधन शुल्क ₹ 1.50 लाख प्रतिमाह प्रति जलयान था। सभी 18 जलयानों को जून 2004 तथा मार्च 2010 के बीच भा.पो.प.नि. को सुपुर्द कर दिया गया था। भा.पो.प.नि. ने अक्तूबर 2010 तथा अक्तूबर 2011 के बीच नए ठेकेदार, मेसर्स ए.बी.एस. मरीन सर्विस प्रा.लि., चैन्नई को सुपुर्द किए जाने तक, प्रबंधन जारी रखा था।

अनुबंध के अनुसार, भा.पो.प.नि. को अप्रत्याशित घटनाओं को छोड़कर वार्षिक यात्री सर्वेक्षण (वा.या.स.)/मरम्मत हेतु, 50 दिनों को अनुमत करने के पश्चात एक वर्ष में 315 दिनों की न्यूनतम अवधि हेतु जलयानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था, जिसकी विफलता पर भा.पो.प.नि. को अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार दण्डित किया जाना था। अनुबंध में यह भी प्रावधान था कि डॉकिंग तथा अन्य सर्वेक्षणों, जिसके लिए जलयानों को बंद किये जाने की आवश्यकता थी, हेतु भा.पो.नि.न. द्वारा योजना बनाई जानी थी तथा शुष्क डॉकिंग इत्यादि के लिए प्रबंध करने हेतु पो.प.से.नि. को कम से कम तीन महीने पहले सूचित करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि जून 2004 से फरवरी 2012 की अवधि के दौरान जलयान वा.या.स./मरम्मत के कारण 56 से 258 दिनों के बीच गैर-परिचालनात्मक थे। भा.पो.प.नि. ने न तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार पो.प.से.नि. को डॉकिंग हेतु पहले से अनुरोध किया था और न ही जलयान की गैर-उपलब्धता के लिए कभी अप्रत्याशित घटना वाली धारा का आवहान किया था। दूसरी ओर पो.प.से.नि. ने कोई जलयान-वार अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया जिसमें वा.या.स./मरम्मत के परिणामस्वरूप हुई रूकावटों के पूर्ण ब्यौरे दर्शाए जाते जिससे भा.पो.प.नि. के कारण हुए विलम्बों को सत्यापित कर सिद्ध किया जा सकता तथा इस प्रकार भा.पो.प.नि. के लिए आरोपनीय विलम्बों को नकारने हेतु व्यापक गुंजाइश छोड़ी। 50 दिनों की स्वीकार्य गैर-परिचालनात्मक अवधि के पश्चात की अवधि हेतु भा.पो.प.नि. पर कुल जुर्माना ₹ 2.18 करोड़ परिकलित हुआ।

इस प्रकार योजनाबद्ध कमियों तथा जुर्माना लगाने में पो.प.से.नि. की ओर से निष्क्रियता के कारण ₹ 2.18 करोड़ भा.पो.प.नि. से वसूल नहीं की जा सकी तथा अ.नि.द्वी. में आम जनता को सामयिक सेवा तथा द्वीपसमूहों के बीच उचित संयोजकता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ समझौता किया गया था।

पो.प.से.नि. ने बताया (मार्च 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मामलों पर टिप्पणियों/ उत्तर हेतु भा.पो.प.नि. को दिसम्बर 2012 में नोटिस जारी कर दिया गया था, परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। भा.पो.प.नि. से उत्तर की प्राप्ति लम्बित होने के कारण पो.प.से.नि. द्वारा भा.पो.प.नि. को देय अग्रिम भुगतान में से जुर्माने की वसूली के प्रयास प्रक्रियाधीन थे।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2012 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।

14.5 मैनिंग एजेन्ट को किया गया अधिक भुगतान

पोत-परिवहन सेवाएं निदेशालय, समझौते के अनुसार पूर्ण योग्य अधिकारियों तथा अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले अधिकारियों के वेतन के अंतर को वसूल करने में असफल रहा, जिसके कारण ₹ 78.96 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

अण्डमान निकोबार प्रशासन के पास व्यापारिक पोत परिवहन (व्या.पो.प.) श्रेणी-VI के अधीन पंजीकृत सत्रह 75/100/150 यात्री पोतों का स्वामित्व तथा संचालन है। प्रत्येक पोत की मैनिंग के लिए निदेशक पोतपरिवहन सेवायें (नि.पो.प.से.) और मैसर्स ए.बी.एस. मरीन सर्विस प्रा.लि. चैन्नई (मैनिंग एजेंट) के मध्य समझौते समय-समय पर एक से नियमों एवं शर्तों के अनुसार क्रियान्वित किये गये।

मार्च 2007 के बाद किए गए समझोते के अनुसार, मैनिंग एजेन्ट के लिए प्रत्येक पोत के बोर्ड पर छः अधिकारियों[3] को उपलब्ध कराना अपेक्षित था। बोर्ड पर उपलब्ध कराये गए अधिकारियों के लिए यह अपेक्षित था कि वे फ्लैग स्टेट आवश्यकता (फ्ले.स्टे.आ.)[4] के अनुसार पूर्ण योग्यता सहित विधिवत प्रमाणित, अर्हता प्राप्त और पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। समझौता में यह भी प्रावधान था कि यदि मैनिंग एजेंट अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले अधिकारी को नियुक्त करता है बशर्ते कि महानिदेशक पोतपरिवहन द्वारा उचित व्यवस्था छूट[5] प्रदान की गई हो, पूर्ण योग्य अधिकारी तथा अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले अधिकारियों (जैसा कि समझौते की अनुसूची-3 में निर्धारित किया गया है) के वेतन के अंतर को मैनिंग एजेंट द्वारा किए गए दावों में से कटौती होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि म.नि.पो.प. व्यवस्था छूट प्रदान करने के लिए कोई शुल्क लगाते हैं, तो वेतन के अंतर की कटौती को उस शुल्क द्वारा कम किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा पता चला है कि अप्रैल 2007 से अगस्त 2012 के दौरान मैनिंग एजेंट ने कई अवसरों पर अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले अधिकारियों को नियुक्त किया था। जुलाई 2007 से अगस्त 2012 के दौरान म.नि.पो.प. को व्यवस्था छूट के रूप में कुल ₹ 51.82 लाख चुकाया गया था।

---

[3] मास्टर, मुख्य अधिकारी, द्वितीय अधिकारी, मुख्य अभियंता, द्वितीय अभियंता तथा तृतीय अभियंता।

[4] फ्ले.स्टे.आ. के अनुसार, प्रत्येक जहाज के मुख्य अधिकारी एवं मुख्य अभियंता के पास क्रमशः मेट (तटीय जहाजों के समीप) तथा एम.ई.ओ.III मुख्य अभियंता (एन.सी.वी) की योग्यता होनी चाहिए जबकि द्वितीय अधिकारी तथा द्वितीय अभियंता के पास क्रमशः जी.एम.डी.एस.एस. के पृष्ठांकन सहित रात्रि प्रहरी अधिकारी (एन.सी.वी.) तथा एम.ई.ओ.III द्वितीय अभियंता की योग्यता होनी चाहिए।

[5] व्यवस्था छूट का अर्थ सामान्य आवश्यकता या नियम में ढील/छूट होता है।

इस अवधि के लिए वेतन अंतर ₹ 138.50 लाख था। इस प्रकार, मैनिंग एजेंट से वेतन अंतर के रूप में ₹ 86.68[6] लाख वसूल किया जाना था। तथापि, पो.प.से.नि. ने जुलाई 2007 से जुलाई 2008 के दौरान केवल ₹ 7.72 लाख ही वसूल किए थे, परिणामस्वरूप मैनिंग एजेंट को ₹ 78.96 लाख का निवल अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, ₹ 29.03 लाख की राशि, जो अप्रैल 2011 से सितम्बर 2012 की अवधि से संबंधित थी, को नवम्बर 2012 में वसूल कर लिया गया। मंत्रालय ने (जनवरी 2013) पो.प.से.नि. को मैनिंग एजेंट को देय भुगतान में से शेष राशि की वसूली करने का निर्देश दिया। तदनुसार पो.प.से.नि. ने अप्रैल 2013 में ₹ 49.93 लाख की शेष राशि वसूल की।

पोतपरिवहन सेवा निदेशालय

14.6 ठेकेदारों को ₹ 58.43 लाख के अनियमित भुगतान

पोतपरिवहन सेवाएं निदेशालय ने उस खाद्य सामग्री के लिए ठेकेदारों को ₹ 58.43 लाख के अनियमित भुगतान होने दिये, जिसकी वास्तव में आपूर्ति नहीं की गयी थी।

पोतपरिवहन सेवाएं निदेशालय (पो.प.से.नि.) ने मैसर्स फरीध ट्रेडर्स, पोर्ट ब्लेयर एवं मैसर्स वाई.ए.आर. शिपिंग एंड कैटरिंग प्राईवेट लिमिटेड (ठेकेदारों) के साथ क्रमशः एम. वी. नेनकॉवरी एवं एम.वी. स्वराज द्वीप पोतों पर खान-पान प्रतिष्ठान चलाने हेतु समझौता (दिसम्बर 2007) किया। समझौता शुरू में सितम्बर 2007 से पूर्व प्रभाव से एक वर्ष के लिए था तथा समय-समय पर इनका विस्तार जनवरी 2010 तक किया गया।

समझौतों के नियमों एंव शर्तों के अनुसार, ठेकेदार इस पोत पर तैनात नाविक दल को रसद के प्रचलित पैमाने के अनुसार दर ₹ 200 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से राशन/खाद्य सामग्री[7] की आपूर्ति करनी थी तथा प्रत्येक कैलेण्डर माह के लिए पो.प.से.नि. को भुगतान के लिए पोत के मास्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित बिल प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि एम. वी. नेनकॉवरी एवं एम. वी. स्वराज द्वीप के नाविक दल ने ठेकेदारों से खाद्य सामग्री की प्राप्ति रोक दी तथा क्रमशः 1 मार्च 2008 तथा 4 सितम्बर 2008 के बाद से स्वयं की खान-पान व्यवस्था शुरू की, क्योंकि आपूर्ति की गयी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त थी। यह मामला

[6] ₹ 138.50 लाख (वास्तविक मजदूरी में अंतर) - ₹ 51.82 लाख (पहले से ही भुगतान की गयी व्यवस्था छूट) ₹ 86.68 लाख

[7] भोजन अथवा रसद

संबंधित जहाजों के मास्टरों द्वारा पो.प.से.नि. को सूचित किया गया तथा इसकी पुष्टि ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों/लघु अधिकारियों[8] के लिए प्रस्तुत किए गए बिलों में भी की गयी थी।

ठेकेदारों ने एम. वी. नेनकॉवरी[9] तथा एम.वी. स्वराज द्वीप[10] पोतों के कर्मी दलों को आपूर्ति की गयी खाद्य सामग्री के संबंध में पो.प.से.नि. को ₹ 58.43 लाख के बिल (अप्रैल - मई 2009) प्रस्तुत किये। ये दावे संबंधित पोतों के कर्मी दल की उपस्थिति सूची के साथ ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, लेकिन मेसिंग प्रमाणपत्र द्वारा पुष्टीकृत नहीं थे, जो कि समझौते के उपबंध 43 के अनुसार आवश्यक था। इस तथ्य के बावजूद कि दावों की अवधि के दौरान नाविक दल ने खान-पान की स्वयं व्यवस्था की थी, पो.प.से.नि. द्वारा मई से जुलाई 2009 के बीच ₹ 58.43 लाख के बिल स्वीकृत कर भुगतान किये। उपर्युक्त तथ्य के विषय में एम. वी. नेनकॉवरी के नाविक दल द्वारा अप्रैल 2009 अर्थात ठेकेदारों के बिल के भुगतान (मई/जुलाई 2009) से पहले पो.प.से.नि. को सूचित भी किया गया था। इस प्रकार का अनियमित भुगतान, ठेकेदारों के लिए अनुचित पक्षपात को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने पो.प.से.नि. से (जुलाई 2012) इस चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व नियत करने तथा ठेकेदारों से पूरा भुगतान वसूल करने को कहा ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा मामला उठाये जाने के चार माह पश्चात् से, पो.प.से.नि. ने ठेकेदारों से ₹ 33.76 लाख वसूल कर लिये थे (अर्थात् नवम्बर 2012 तक), जो कि मई 2009[11] से 39 माह से अधिक समय से लंबित थे।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में यह तथ्य स्वीकार किया कि ठेकेदारों को भुगतान करने में अधिकारियों से चूक हुई थी और आगे कहा गया कि उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कार्यवाही आरंभ की जा रही है।

---

[8] नौसेना में नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों का एक रैंक, मुख्य नाविक अथवा नाविक से ऊपर तथा मुख्य लघु अधिकारी से नीचे

[9] 1 मार्च 2008 से 28 फरवरी 2009 तक की अवधि के लिए।

[10] 4 सितम्बर 2008 से 28 फरवरी 2009 तक की अवधि के लिए।

[11] ठेकेदारों को भुगतान की तिथि

लक्षद्वीप प्रशासन

14.7 लैंडिंग नौकाओं के प्रापण में निष्फलता के परिणामस्वरूप ₹ 12.21 करोड़ का अपव्यय

सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन द्वारा अनुबंध उपनियम के अनुसार बैंक गारंटी के सामयिक नवीकरण में निष्फलता के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता से ₹ 12.21 करोड़ की राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

भारत सरकार, पोतपरिवहन मंत्रालय ने लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र, (सं.शा.क्षे.ल.) प्रशासन को छह द्वीपों[12] में से प्रत्येक के लिए ₹51.06 करोड़ की लागत पर छह 200 यात्रियों की क्षमता वाली लैंडिंग नौकाओं[13] के अभिग्रहण हेतु मंजूरी दी (अप्रैल 2007)। नौकाओं के प्रापण का उद्देश्य जौखिमों को कम करना तथा यात्रियों के आरोहण एवं अवरोहण, जो कि जहाज से किनारे तक छोटी नौकाओं के माध्यम से किया जाता था, को आसान करना था।

छह नौकाओं के निर्माण एवं आपूर्ति हेतु सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने मैसर्स विपुल शिपयार्डस प्राइवेट लिमिटेड, गोवा के साथ जहाज निर्माण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए (नवम्बर 2007)। अनुबंध के अनुसार सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने सुपुर्दगी की तिथि तक मान्य, बराबर की राशियों के लिए बैंक गारंटी (बैं.गा.) के प्रति आपूर्तिकर्ता को सात किस्तों में चरणबद्ध भुगतान किये। तीसरी किस्त का भुगतान 100 *प्रतिशत* पतवार निर्माण होने पर किया जाना था। अनुबंध के निरीक्षण उपनियम के अनुसार, क्रेता अथवा क्रेता के पर्यवेक्षकों को निर्माणकार्य तथा कारीगरी की निगरानी तथा निरीक्षण करने हेतु आवश्यक समझ पर जहाजों से संबंधित ऐसी परीक्षा एवं निरीक्षण में उपस्थित होने का अधिकार था।

इससे पहले मार्च 2006 में, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने नौकाओं की स्वीकृति तथा सुपुर्दगी तक नौकाओं को मंगाने में सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन की सहायता हेतु प्रबंधकीय सेवाएँ प्रदान करने, योजनाओं तथा आरेखणों के अनुमोदन और एक चुनिंदा पोतप्रांगण पर नौकाओं के निर्माण के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण हेतु भारतीय पोतपरिवहन निगम (भा.पो.प.नि.) के साथ अनुबंध किया था।

---

[12] अगत्ती, आमिनी, आन्द्रोथ, कदामत, कावरत्ती तथा मिनीकॉय

[13] पतवार सं. 165 से 170

पहली एवं दूसरी नौका[14] का निर्माण जनवरी 2008 में शुरू होना था तथा अक्तूबर 2008 एवं नवम्बर 2008 में सुपुर्द किया जाना निर्धारित था। तदनुसार, 25 नवम्बर 2010 तथा 28 जनवरी 2011 तक मान्य समान राशि के लिए बैंक गारंटी के प्रति भा.पो.प.नि. द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर, नौकाओं के निर्माण हेतु ₹ 12.21 करोड़ तक की राशि के चरणबद्ध भुगतान[15] जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने महानिदेशक पोतपरिवहन (म.नि.पो.प.) से नौकाओं पर आगे वाला मस्तूल[16] (मार्च 2010), जीवन-तरामों के लिए दवित (जून 2010), सरलीकृत जलयात्रा डाटा रिकॉर्डर (स.ज.डा.रि.) तथा लंबी दूरी पहचान एवं ट्रैकिंग (लं.दू.प.ट्रै.) (अक्तूबर 2010) तथा न्यूनतम एक दिन की क्षमता हेतु सीवेज टैंक प्रदान करने में (अक्तूबर 2010) छूट मांगी थी, क्योंकि ये विशिष्टताएं, अनुमोदित डिजाइन में शामिल नहीं थे।

चूंकि आपूर्तिकर्ता ने निर्धारित समय में नौका की आपूर्ति नहीं की, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने निरीक्षण हेतु अपने प्रतिनिधि को दो बार (नवम्बर 2010 एवं फरवरी 2011) प्रतिनियुक्त किया। तत्पश्चात, शिपयार्ड पर नौकाओं के निर्माण की प्रगति को रिपोर्ट करने के लिए भा.पो.प.नि. के प्रतिनिधियों एवं अपने अधिकारियों को शामिल करते हुए एक टीम[17] भी प्रतिनियुक्त की थी (जुलाई 2011)। जहाँ दोनों प्रतिनिधियों ने कार्य की धीमी प्रगति को इंगित किया, टीम ने अनुमोदित विशिष्टताओं से काफी विचलन/संशोधन, विभिन्न मापदंडों अर्थात प्रारूप की लंबाई, जहाज का वजन, जहाज की गति, आदि में विसंगतियां इंगित की थी। टीम ने एकमत से माना कि इन नौकाओं को वर्तमान स्थिति में सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए यह नौकाएं अभिप्रेत थी, वह उसे पूरा करने में सक्षम नहीं थीं। तदनुसार, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने नौकाओं को अस्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया

---

[14] पतवार सं. 165 तथा 166

[15]

किस्त	पतवार सं. 165 राशि लाख में	जारी की गई किस्त	पतवार सं. 166 राशि लाख में	शुरूआत एवं सुपुर्दगी की प्रस्तावित तिथि
प्रथम (15%)	126.60	15.03.2008	126.60	10.09.2008
द्वितीय (15%)	126.60	10.09.2008	126.60	10.09.2008
तृतीय (15%)	126.60	30.12.2008	126.60	20.11.2008
चतुर्थ (20%)	168.80	30.12.2008	168.00	30.12.2008
पंचम (15%)			126.00	06.05.2010
योग	**548.60**		**671.80**	

[16] पाल, बल्ली, रस्सियों आदि को पकड़ने के लिए जहाज के ऊपरी भागों तथा पतवार के ऊपर उठी हुई बल्लियां संरचना

[17] अभियांत्रिकी अधीक्षक (सितम्बर 2010), गोवा शिपयार्ड का सेवानिवृत्त सी.एम.डी. (मार्च 2011), टीम (जुलाई 2011)

तथा आपूर्तिकर्ता के साथ हुए अनुबंध को रद्द कर दिया (जनवरी 2012)। चूंकि बैंक गारंटियों की वैधता को नवीकृत नहीं किया गया था। सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने आपूर्तिकर्ता को 12 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर पर दंडात्मक ब्याज के साथ पूरी राशि की वापसी का निर्देश (जनवरी 2012) दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सं.शा.प्र.ल. प्रशासन ने भा.पो.प.नि. द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के आधार पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया था। नवम्बर 2010 तक, वास्तविक स्थिति के आकलन हेतु सं.शा.क्षे.ल. द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सुपुर्दगी में विलंब के बावजूद सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन सरकार के हित को सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटियों को नवीकृत करने में विफल रहा।

मामले को गृह मंत्रालय को प्रेषित (अगस्त 2012) किया गया। अपने उत्तर में, मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2012) कि सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने भा.पो.प.नि. एवं शिपयार्ड के समक्ष अनुमोदित डिजाइन/विशिष्टता से विचलित न होने हेतु मामला उठाया था। अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार भा.पो.प.नि. द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के आधार पर सभी चरणबद्ध भुगतान किए गए थे। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बताया कि सं.शा.क्षे.ल. ने सभी बैं.गा. को नवीकृत करने के लिए भा.पो.प.नि. के साथ समय पर पत्राचार किया था।

मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित जवाबदेही वाले मुद्दों को स्पष्ट नहीं करता:

- हालांकि, मंत्रालय ने बैं.गा. की पुनर्वैधता से संबंधित मुद्दा भा.पो.प.नि. के समक्ष उठाया था, अनुबंध भा.पो.प.नि. को अनुबंध उपनियम के माध्यम से बैं.गा. को रखने और जहाजों की सुपुर्दगी तक उन्हें पुनर्वैधता/नवीकृत करने की जिम्मेदारी के साथ बाध्य नहीं करता था।

- यह कथन कि सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने मूल डिजाइन में कोई संशोधन नहीं किया था गलत है क्योंकि सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने म.नि.पो.प. से मूल डिजाइन में छूट/संशोधन की मांग की थी। नौकाएं जोकि शुरू में प्रत्येक द्वीप में यात्रियों को जहाज से किनारे तक लाने के लिए अभिप्रेत थी, उनका निर्माण वास्तव में समुद्र में जाने वाले जहाजों के रूप में किया गया था।

- भा.पो.प.नि. द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन द्वारा कोई स्वतंत्र नियंत्रण नहीं लगाये गए।

वास्तविकता यह है कि कंपनी को भुगतान किए गए ₹ 12.21 करोड़ की राशि पिछले पांच वर्षों से निष्फल रही थी, क्योंकि सं.शा.क्षे.ल. बैंक गारंटियों के समय पर नवीकरण को सुनिश्चित न कर पाने के कारण इस राशि की सुरक्षा में विफल रहा।

14.8 रडार ट्रांसपोंडरों को संस्थापित न किया जाना

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) से बेतार परिचालन लाइसेंस (बे.प.ला.) को प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप रॉयल्टी/स्पेक्ट्रम प्रभारों के प्रति ₹ 1.17 करोड़ के व्यय के बावजूद ₹ 1.52 करोड़ की कीमत के रडार ट्रांसपोंडरों को संस्थापित नहीं किया जा सका।

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप (सं.शा.क्षे.ल.) प्रशासन, लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों से गंभीर रूप से बीमार रोगियों को निकालकर मुख्य भूमि (कोची) तक अत्यावश्यक तथा विशेषीकृत चिकित्सकीय उपचार हेतु पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टरों को चिकित्सा एम्बुलेंस के रूप में उपयोग करता है। हेलीकॉप्टरों की हवाई सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए तथा खराब मौसम की परिस्थितियों में भी द्वीपों/गंतव्य स्थलों का पता लगाने में हेलीकॉप्टर पायलट हेतु सहायता सुनिश्चित करने के लिए, सं.शा.क्षे.ल. (जुलाई 2005) ने पांच द्वीपों[18] हेतु पांच रडार ट्रांसपोंडरों के प्रापण हेतु ₹ 1.52 करोड़ संस्वीकृत किए। भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण (भा.ह.प.प्रा.) को बिना किसी औपचारिक अनुबंध के ही सं.शा.क्षे.ल. द्वारा ट्रांसपोंडरों का प्रापण सौंप दिया गया था।

सितम्बर 2006 में भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण (भा.ह.प.प्रा.) तथा मई 2007 में दूरसंचार विभाग (दू.वि.), संचार मंत्रालय (सं.मं.) ने सं.शा.क्षे.ल. को स्पष्ट किया कि दू.वि. से बेतार परिचालन लाइसेंस (बे.प.ल.) को प्राप्त करने के पश्चात ही परिचालन हेतु ट्रांसपोंडरों को संस्थापित किया जा सकेगा। बे.प.ला. प्रदान किये जाने की पूर्व शर्तें थीं; स्थल के लिए अनुमति तथा दू.वि. के निर्णय पत्र को जारी किए जाने की तिथि से परिकलित, लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभारों के अग्रिम भुगतान। इसलिए, सं.शा.प्र.ल. को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य था कि बे.प.ला. समय पर प्राप्त कर लिया जाये।

आगे, यह पाया किया गया कि बे.प.ला. देने का दू.वि. का निर्णय सं.शा.क्षे.ल. को 21 मई 2007 को ₹5000/- लाइसेंस शुल्क तथा प्रति वर्ष ₹ 36.00 लाख के स्पेक्ट्रम प्रभारों के भुगतान तथा स्थल की अनुमति तथा उपकरण के प्रापण हेतु तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश सहित सूचित किया। उस समय तक भा.ह.प.प्रा. के माध्यम से पहले से ही प्रापण चालू था। मई 2008 में सभी पांच ट्रांसपोंडर प्राप्त कर लिए गए थे तथा

[18] बित्रा, चेतलग, कावारत्ती, किल्तन तथा मिनीकोय

अगस्त 2008 तथा मई 2009 के बीच उनका संस्थापन कर दिया गया था। मार्च 2009 तथा मई 2009 के बीच उपकरण को परिचालन हेतु तैयार कर दिया गया था। परन्तु यह देखा गया कि स्थल अनुमति हेतु आवेदन पत्र करीब एक वर्ष के पश्चात अर्थात् सितम्बर 2009 में दिया गया था तथा 21 मई 2007 से एक वर्ष हेतु देय ₹ 36.05 लाख के डिमांड ड्राफ्ट के सहित बे.प.ला. को जारी करने हेतु आवेदन पत्र भी साथ में प्रस्तुत किया गया। इसी बीच, दू.वि. ने 01 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 की अवधि हेतु लाईसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभारों हेतु ₹ 92.06 लाख की दूसरी मांग (15 अक्तूबर 2009) जारी कर दी। जिसके प्रति सं.शा.क्षे.ल. ने मई 2010 में 2009-10 हेतु विलम्ब शुल्क को छोड़कर, ₹ 80.66 लाख का भुगतान किया। इस प्रकार, सं.शा.क्षे.ल. ने दू.वि. को मई 2007 से मई 2010 के बीच ₹ 1.17 करोड़ के स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2008 के पश्चात् से चार वर्षों से अधिक बे.प.ला. की प्राप्ति न होने के कारण ट्रांसपोंडरों को परिचालित नहीं किया जा सका तथा ₹ 1.17 करोड़ का व्यय व्यर्थ गया। ₹ 1.52 करोड़ की कीमत के ट्रांसपोंडर भी व्यर्थ पड़े रहे तथा उनकी वारंटी की अवधि जुलाई 2009 में समाप्त हो गई।

गृह मंत्रालय (मार्च 2013) ने उपरोक्त तथ्य स्वीकार करते हुए बताया कि पत्तन, नौवहन एवं उड्डयन महानिदेशालय द्वारा लाइसेंस को जारी करने हेतु दूरसंचार मंत्रालय से लगातार अनुसरण करने के बावजूद भी, इसे प्राप्त नहीं किया जा सका था। मंत्रालय ने आगे बताया कि उन्होंने इस मामले में संपर्क स्थापित करने के लिए दू.वि. में स्टाफ की तैनाती कर दी थी।

इस प्रकार, ₹ 1.17 करोड़ के स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करने के पश्चात भी, विभाग, पायलट को विमान चालन सहायता प्रदान करने एवं हेलीकॉप्टर की हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहा, जैसा कि अभिप्रेत किया गया था। केवल यही राशि व्यर्थ नहीं गई, अपितु ₹ 1.52 करोड़ की कीमत का उपकरण भी, वारंटी समाप्ति पश्चात व्यर्थ पड़ा था।

सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ प्रशासन

14.9 राजस्व हानि

नयी खरीदी गयी 20 वातानुकूलित बसों को शुरूआत में नहीं चलाने और बाद में उन्हें लम्बे रूटों, जिनके लिए उनकी संरचनात्मक रूपरेखा बनायी गयी थी, पर चलाने की बजाय स्थानीय रूटों पर चलाने के कारण चं.प.उ. को ₹ 58.97 लाख की राजस्व हानि हुई थी।

चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (चं.प.उ.) ने चण्डीगढ़ प्रशासन के पास अनुपयोगी साधारण लम्बी रूट की बसों के स्थान पर 20 साधारण वातानुकूलित बसों की खरीद का प्रस्ताव (सितम्बर 2009) भेजा। साधारण बसों को वातानुकूलित बसों से बदलने की आवश्यकता पंजाब इलाके में केवल 10 *प्रतिशत* अतिरिक्त किराये पर चलने वाली लम्बी दूरी की वातानुकूलित बसों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए महसूस की गयी थी। चण्ड़ीगढ़ प्रशासन ने ₹ 3.06 करोड़ की लागत पर 20 चेसिस (साधारण जिला टाइप वातानुकूलित) की खरीद हेतु अनुमोदन (22 फरवरी 2010) प्रदान किया। सितम्बर-अक्तूबर 2010 के दौरान प्राप्त चेसिसों का निर्माण[19] ₹ 2.87 करोड़ की लागत पर लंबे रूट की बसों के मानदंड के अनुसार हुआ था। इन बसों को राज्य परिवहन प्राधिकरण (रा.प.प्रा.) द्वारा जनवरी 2011 से मार्च 2011 के दौरान पारित किया गया था।

राज्य परिवहन प्राधिकरण (रा.प्र.प्रा.) द्वारा इन बसों को पारित करने के बाद, 27 एवं 28 जनवरी 2011 को स्थानीय परिचालन हेतु कुछ बसें सड़क पर उतारी गयीं। स्थानीय परिचालन के दौरान, नीचे बतायी गयीं कुछ संरचनात्मक समस्याएं देखी गयी थीं क्योंकि बसों को लंबे रूट के लिए बनाया गया था।

- इन बसों का निर्माण जिला टाइप की बसों हेतु मानदण्डों के अनुसार किया गया था। इन बसों का परिमाण अर्थात लम्बाई, ऊँचाई तथा दरवाजे स्थानीय बसों से अलग थे।
- इन बसों की ऊँचाई मौजूदा स्थानीय बसों से डेढ़ फुट अधिक थी,
- दरवाजे बहुत छोटे थे जो स्थानीय परिचालन हेतु सुविधाजनक नहीं थे। बस में खड़े यात्रियों की मदद के लिए कोई हैण्डल बार नहीं लगाया गया था। यात्रियों के उतरने और चढ़ने के लिए बस का पायदान निम्न तल वाली स्थानीय बसों से

[19] जिला टाइप बसों का निर्माण लंबे रूट बसों के लिए निर्धारित मानदंड जैसे लम्बाई, ऊंचाई, दरवाजे और आंतरिक साज-सज्जा के अनुरूप किया गया जो स्थानीय रूट बसों से अलग थे।

काफी ऊँचा था जो बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए असुविधाजनक था।

- बस में चालक केबिन था जो बस को खड़ा करते समय और बस चलाते समय चालक के लिए बस के पीछे के हिस्से को देखने में बड़ी बाधा उत्पन्न करते थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संरचनात्मक समस्याओं को देखने के बाद (जनवरी 2011) इन बसों को फरवरी तथा मार्च 2011 की अवधि के दौरान 57 दिनों तक सड़क पर नहीं उतारा गया था, जिसके कारण ₹49.22 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई (**अनुबंध-13**)।

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि चं.प.उ. (अप्रैल 2011) ने 13 बसों को औसतन 23 दिनों की अवधि हेतु स्थानीय रूटों पर चलाया जब कि इन्हें लंबे रूट के लिए बनाया गया था। इसी बीच परिवहन निदेशक ने चण्ड़ीगढ़ प्रशासन से इन वातानुकूलित बसों को लंबे रूटों पर चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया (5 अप्रैल 2011)। चण्ड़ीगढ प्रशासन ने चं.प.उ. की इन बसों को उप-नगरीय इलाकों में परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगाने का निर्देश (15 अप्रैल 2011) दिया ताकि तकनीकी समस्याओं का ध्यान रखा जा सके। तदनुसार, इन 20 बसों को 28 अप्रैल 2011 से उप-नगरीय रूटों पर लगा दिया गया। चूंकि स्थानीय रूट की बसें लंबी रूट की बसों की तुलना में कम राजस्व अर्जित कर रही थीं, लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि इन को लम्बे रूटों की बजाय स्थानीय रूटों पर चलाने से, ₹ 9.74 लाख (**अनुबंध-13**) की कम वसूली प्राप्त हुई। अंततः फरवरी 2012 में, चण्ड़ीगढ़ प्रशासन ने इन बसों को लंबे रूटों पर चलाने की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2012) कि वातानुकूलित बसों को ट्राई सिटी[20] की जनसंख्या में कई गुणा वृद्धि के कारण बस सेवाओं की मांग में वृद्धि होने से लंबे रूटों पर नहीं चलाया जा सका। उत्तर में रा.प.प्रा. द्वारा पारित होने के 57 दिनों बाद भी बसों के नहीं चलने के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि चण्डीगढ़ प्रशासन लंबे रूट की बसे खरीदते/बनाते समय स्थानीय रूटों पर मांग से अच्छी तरह परिचित था। साथ ही, परिवहन निदेशक, जो चं.प.उ. के परिचालन के दैनिक प्रबंधन के प्रभारी थे, ने चण्डीगढ़ प्रशासन को स्पष्टतः सूचित किया था (अप्रैल 2011) कि स्थानीय रूटों पर पहले से ही पर्याप्त बसें थी और इन बसों को लंबे रूटों पर चलाने की आवश्यकता है।

[20] मोहाली, चण्ड़ीगढ़ तथा पंचकुला के शहरों को ट्राई-सिटी कहते हैं।

इस प्रकार, चण्डीगढ प्रशासन की तरफ से खराब योजना के आधार पर वातानुकूलित बसों को प्रारंभ में खड़ी रखने और बाद में लंबे रूटों, जिसके लिए परमिट लिया गया था, पर नहीं चलाने के तदर्थ निर्णयों के परिणामस्वरूप राजकोष में ₹ 58.97 लाख की संभाव्य राजस्व-हानि हुई।

मामला मंत्रालय को मार्च 2013 में सूचित किया गया; उनका उत्तर मई 2013 तक प्रतीक्षित था।

14.10 सरकारी धन का दुर्विनियोजन

सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ के पंजीकरण तथा लाईसेंसिंग प्राधिकरण के रोकड़ काउंटरों से प्राप्त धन को खजाने में प्रेषण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 25.68 लाख के सरकारी धन का दुर्विनियोजन हुआ।

केन्द्रीय सरकार लेखे (प्राप्तियॉ एवं भुगतान) नियमावली 1983 का नियम 13 (ii) प्रावधान करता है कि सभी आर्थिक लेन-देनों को जैसे ही ये किए जाएँ, जल्द से जल्द रोकड़ बही में दर्ज किया जाना चाहिए तथा जांच के प्रमाण में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपनियम (2) की शर्त पर नियम 7 (i) प्रावधान करता है कि सरकार के राजस्वों के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा अथवा को प्रस्तुत सभी धन को बिना अनुचित विलम्ब के समग्र रूप से खजाने में जमा किया जाएगा तथा सरकार के लेखाओं में शामिल किया जाएगा। पंजीकरण तथा लाईसेंस प्राधिकरण (पं.ला.प्रा.), सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ की दैनिक बही के साथ रोकड़ काउंटरों की प्राप्तियों, रोकड़ बही के साथ दैनिक बही तथा खजाना चालान के साथ रोकड़ बही की लेखापरीक्षा के दौरान (दिसम्बर 2011) प्रकट हुआ कि पं.ला.प्रा. ने सितम्बर 2010 तथा मार्च 2011 के बीच मोटर वाहनों के पंजीकरण शुल्क तथा ड्राइविंग लाइसेंसों को जारी करने के प्रति अपने विभिन्न रोकड़ काउंटरों पर ₹ 23.91 लाख[21] की राशि प्राप्त की जिसे न तो दैनिक बही/रोकड़ बही में दर्ज किया गया था न ही खजाने में प्रेषित किया था। पूर्ण राशि, जैसा कि **(अनुबंध-14)** में दर्शाया गया है, का कैशियरों द्वारा दुर्विनियोजन किया गया था।

पं.ला.प्रा. अभिलेखों की अग्रसर संवीक्षा ने यह भी प्रकट किया कि मई 2010 तथा मार्च 2011 के बीच मोटर वाहनों के पंजीकरण शुल्क के प्रति रोकड़ में प्राप्त ₹ 15.91 लाख में से केवल ₹ 14.14 लाख को दैनिक बही/रोकड़ बही में दर्ज तथा खजाने में प्रेषित

[21] ₹ 23,41,705/- पंजीकरण शुल्क तथा ₹ 49,345/- ड्राइविंग लाईसेंस शुल्क

किया गया था। ₹ 1.77 लाख[22] की शेष राशि को न तो दैनिक बही/रोकड़ बही में दर्ज किया गया था, न ही खजाने में प्रेषित किया गया था जैसा कि **(अनुबंध-15)** में दर्शाया गया है। इस प्रकार इस मामले को मिलाकर कुल ₹ 25.68 लाख के सरकारी धन का दुर्विनियोजन हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नोडल अधिकारी (आ.सं.अ.) ने अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा नहीं किया था जिसके अनुसार मूल से खजाना स्तर तक (दैनिक बही के साथ रोकड़ कांउटर प्राप्तियों, रोकड़ बही के साथ दैनिक बही तथा खजाना चालान के साथ रोकड़ बही) प्राप्तियों का समाधान नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी धन का दुर्विनियोजन हुआ।

लेखापरीक्षा को प्रश्न के उत्तर में पंजीकरण तथा लाईसेंसिंग प्राधिकरण ने सूचित किया (अगस्त 2012) कि दुर्विनियोजित राशि को वसूल नहीं किया जा सका तथा मामले के अंतिम परिणाम को जल्द ही सूचित किया जाएगा।

मामला सं.शा.क्षे., चण्डीगढ़ के वित्त सचिव, गृह सचिव तथा उपायुक्त को सूचित (जनवरी 2012, नवम्बर 2012 तथा मार्च 2013) किया गया था तथा उनका उत्तर अप्रैल 2013 तक प्रतीक्षित था।

चण्डीगढ़ प्रशासन-पुलिस विभाग

14.11 पुलिस बल की तैनाती हेतु प्रभारों की वसूली न होना

पंजाब क्रिकेट संघ (पं.क्रि.सं.) एवं किंग्स XI, पंजाब को पुलिस बल उपलब्ध कराने में नियमों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप, के.शा.क्षे. प्रशासन, चण्डीगढ़ द्वारा ₹ 8.92 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

पंजाब पुलिस नियमावली 1934 (के.शा.क्षे. चण्डीगढ़ में लागू) के अनुसार, निजी व्यक्तियों, कार्पोरेट निकायों, अथवा व्यवसायिक कंपनियों द्वारा अतिरिक्त पुलिस के लिए आवेदन करने पर इसकी आपूर्ति, अधीक्षक के निर्णय पर, जिला मेजिस्ट्रेट के सामान्य दिशानिर्देशों के अधीन की जाएगी। इसके अतिरिक्त नियमानुसार, अतिरिक्त पुलिस को अग्रिम में पूरा भुगतान किए बिना प्रदान नहीं किया जा सकता।

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ ने निजी पार्टियों अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंक, पंजाब क्रिकेट संघ मोहाली एवं इण्डियन प्रीमियर लीग टीम-किंग्स XI, पंजाब को सुरक्षा प्रयोजनों हेतु भुगतान के आधार पर पुलिस बल उपलब्ध कराया था।

[22] ₹ 15,91,120/- घटा ₹ 14,14,185/-

पुलिस महानिरीक्षक, सं.शा.क्षे. प्रशासन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पंजाब क्रिकेट संघ (पं.क्रि.सं.), मोहाली एवं किंग्स XI, पंजाब (आई.पी.एल. टीम) के अनुरोध पर सं.शा.क्षे. प्रशासन चण्डीगढ़ (म.नि. पुलिस) ने विश्व कप (2011) एवं 2010, 2011 तथा 2012 में आई.पी.एल. क्रिकेट मैचों में भाग लेने वाली विभिन्न टीमों की सुरक्षा हेतु पुलिस बल प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 8.92 करोड़ का पूरा भुगतान अग्रिम में लिए बिना बल प्रदान किए गये थे (**अनुबंध-16**)। पाँच मामलों में, सं.शा.क्षे. प्रशासन ने आयोजन के पूरा होने के बाद बिल जारी किये थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में भुगतान समय पर प्राप्त हुए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2011), सं.शा.क्षे. प्रशासन चण्डीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षण ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि उन्होंने क्रिकेट टीमों की सुरक्षा हेतु प्रदान किये गये पुलिस बल की राशि की वसूली हेतु संबंधित प्राधिकारियों को बिल जारी कर दिये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सं.शा.क्षे. प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं किया था जिनके अनुसार निजी पार्टियों को अतिरिक्त पुलिस, पूरा भुगतान अग्रिम लिए बिना नहीं दी जा सकती थी।

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने (नवम्बर 2011) के बाद भी, सं.शा.क्षे. प्रशासन मार्च 2012 से मई 2012 के दौरान निजी पार्टियों को अग्रिम में बिल जारी किये बिना पुलिस बल प्रदान करता रहा, जिसके लिए बिल जुलाई 2012 में जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त सं.शा.क्षे. प्रशासन द्वारा निजी पार्टियों से लंबे समय से बकाया राशियों (नवम्बर 2009 के बाद से) की वसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.92 करोड़ की सरकारी प्राप्तियां जारी न हो सकी।

मामला अगस्त 2012 में गृह मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर अप्रैल 2013 तक प्रतीक्षित था।

चण्डीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़

14.12 निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु एकत्रित ₹ 28.04 करोड़ के उपकर का उपयोग नहीं होने के कारण लक्ष्य की उपलब्धि न होना

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभ हेतु कल्याण-योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के कारण, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा अन्य से एकत्रित ₹ 28.04 करोड़ के उपकर अप्रयुक्त रहा।

प्रस्तावना

भारत सरकार (भा.स.) ने 'भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक' (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 का प्रत्येक राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने

के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना हेतु अधिनियमित किया था। भा.स. ने " भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 " का भी अधिनियमन किया जिसके अनुसार अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केवल भा.स. के पास होगी। बोर्ड के संसाधनों का आवर्धन करने के लिए, सितम्बर 1996 में संशोधित उपकर अधिनियम की धारा 3 नियोक्ता पर निर्माण के कुल लागत के एक प्रतिशत के दर से उपकर के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य सरकार[23] से संबंधित कम से कम पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के उपकर के लाभ हेतु कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं उल्लिखित की गयी थी।

श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ ने दिनांक 18 जुलाई 2008 की अधिसूचना के द्वारा "चण्डीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) चण्डीगढ़ " गठित किया। चण्डीगढ़ प्रशासन, श्रम विभाग ने 17 सितम्बर 2009 की अधिसूचना के माध्यम से चण्डीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2009 बनायी और उपकर अधिनियम की आवश्यकतानुसार एक प्रतिशत की दर से (सितम्बर 2009) उपकर लगाया।

निधियों का सृजन एवं इसके उद्देश्य:

चण्ड़ीगढ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तो विनियमन) नियमावली, 2009 के नियम 268 ने निर्धारित किया कि इन नियमों के प्रभाव में आने के तुरंत बाद से ही बोर्ड " चण्डीगढ़ भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण निधि " के नाम से एक निधि का निर्माण करे और इसमें भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत वसूल उपकर की प्राप्तियाँ जमा की जाएँ। इस प्रकार एकत्रित निधियों को भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु पेंशन लाभों, दुर्घटना के मामले में सहायता मकान बनाने के लिए ऋणों, बीमा योजना, बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सकीय सहायता, मातृत्व सहायता आदि योजना पर व्यय करना अपेक्षित था। 18 से 60 वर्षों की आयु वर्ग के बीच के निर्माण श्रमिकों को, ऐसी योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने के पात्र होने के लिए स्वयं को बोर्ड के साथ पंजीकृत करना था।

[23] हि.प्र. 2012 के प्रतिवेदन सं. 1 का पैरा 3.1, ज.एवं क.-2013 के प्रतिवेदन सं.1 का पैरा 2.4, हरियाणा-2013 के प्रतिवेदन सं. 3 का पैरा 2.1, दिल्ली-2013 के प्रतिवेदन सं. 2 का पैरा 3.4 तथा पंजाब-2013 के प्रतिवेदन सं. 3 का पैरा 3.3

बोर्ड के संसाधन:

उपकर अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित उपकर नियोक्ता एवं श्रमिकों से पंजीकरण शुल्क तथा श्रमिकों से प्राप्त मासिक अंशदान, बोर्ड की निधि के प्रमुख स्रोत थे। निधि को बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण योजनाओं, वेतन, भत्ते तथा सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के अन्य परिश्रमिकों और अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि पर लगाना आवश्यक था। वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान प्राप्त निधियों एवं किये गये व्यय की वर्ष-वार स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

(₹ लाख में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
प्राप्तियाँ	746.60	976.67	1166.81	2890.08
व्यय				
कल्याणकारी योजना	27.04	11.72	24.03	62.79
अन्य व्यय	4.99	6.06	12.02	23.07
कुल व्यय	32.03	17.78	36.05	85.86
उपयोग प्रतिशतता	4.29	1.82	3.49	
अप्रयुक्त राशि				**2804.22**

(क) जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान निधियों की उपयोग प्रतिशतता केवल 1.82 और 4.29 के मध्य थी।

(ख) बोर्ड ने 2009-13 की अवधि (31 मार्च 2013 तक) के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम एवं निजी ठेकेदारों से श्रम उपकर की प्राप्ति के रूप में ₹ 28.90 करोड़ की राशि प्राप्त की थी। इसमें ₹ 62.79 लाख अर्थात केवल 2.17 प्रतिशत कल्याण योजनाओं/उपायों पर और ₹ 23.07 लाख प्रशासनिक व्ययों पर उपरोक्त अवधि के दौरान उपयोग हुआ था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कल्याण योजनाओं पर किये गये ₹ 62.79 लाख के व्यय का प्रमुख हिस्सा एम्बुलेंस वैन तथा मोबाइल डिस्पेंसरी की एक बार में की गई खरीद और कंबलों एवं प्रेशर कुकरों के वितरण पर किया गया था। ₹ 28.04 करोड़ की शेष राशि (उस अवधि के दौरान निवेश पर अर्जित ब्याज को छोड़कर) अप्रयुक्त पड़ी रही थी।

योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियाँ:

कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं;

- बोर्ड ने चण्डीगढ़ में कार्यरत भवनों और अन्य निर्माण श्रमिकों की वास्तविक संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया था।
- 9768 पंजीकृत श्रमिकों (सदस्य) में से केवल 12 (31-3-2013 तक) को ₹ 3.32 लाख का लाभ मृत्यु/दुर्घटना/अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत प्राप्त हुआ।
- केवल दो श्रमिकों को मातृत्व लाभ योजना के तहत ₹ 0.10 लाख का लाभ मिला।
- केवल दो श्रमिकों को कन्यादान योजना के अंतर्गत ₹ 0.26 लाख का लाभ मिला।
- 9768 सदस्यों में से केवल 24 श्रमिकों को मासिक पेंशन मिल रही थी और 31.3.2013 तक कुल अदा राशि ₹ 1.04 लाख थी।

इस प्रकार, ₹ 5.12 लाख के अल्प राशि के निर्गम से कल्याण योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को लाभ पहुँचाने का प्रयोजन सिद्ध करने की संभावना नहीं थी।

बोर्ड ने यह स्वीकार करते हुए कि श्रमिकों की वास्तविक संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया, आगे बताया (दिसम्बर 2012) कि बोर्ड का प्रयास होगा कि भवन श्रमिकों को अधिक लाभ पहुँचाया जाए ताकि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम उपकर का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

मामले को सं.शा.क्षे. प्रशासन (अगस्त 2012) और भारत सरकार (फरवरी 2013) को भी सूचित कर दिया गया था; उनका उत्तर अप्रैल 2013 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XV : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

15.1 राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु कार्यालय भवन के निर्माण में असामान्य विलंब

राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए कार्यालय भवन, 2001 में भूमि अधिग्रहित करने के बावजूद भी नहीं बनाया जा सका था। विलंब का कारण मुख्यतः दोषयुक्त योजना थी। परिणामस्वरूप, निर्माण गतिविधियों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को जारी की गयी ₹ 1.47 करोड़ की धनराशि मार्च 2004 से अवरूद्ध रही। काफी समय और अधिक व्यय के बावजूद, परियोजना अभी तक प्रारंभिक चरण में ही थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) वर्तमान समय में एक किराए के भवन में अवस्थित है। इस भवन का वार्षिक किराया ₹ 50 लाख है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने रा.म.आ. तथा राष्ट्रीय महिला कोष के लिए एक संयुक्त भवन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए रा.म.आ. को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया (अक्तूबर 1995) था। प्रस्तावित निर्माण द्वारा रा.म.आ. को एक स्वतंत्र तथा विशाल भवन उपलब्ध कराना था और इसके द्वारा मौजूदा किराये के भवन के किराये की बचत करना भी था।

रा.म.आ. ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) से जसोला सांस्थानिक क्षेत्र में 3080 वर्ग मीटर भूमि ₹ 37.48 लाख की कीमत पर अधिग्रहित की थी (जून 2001)। रा.म.आ. ने आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) को परियोजना हेतु वास्तु संबंधी परामर्श प्रदान करने के लिए नियुक्त किया (अगस्त 2001)। हुडको द्वारा तैयार वास्तु संबंधी आरेखों के आधार पर, रा.म.आ. ने के.लो.नि.वि. से प्रारंभिक प्राक्कलन बनाने का अनुरोध किया (जून 2003)। के.लो.नि.वि. द्वारा प्राक्कलनों को अक्तूबर 2003 में प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने परियोजना हेतु ₹ 6.09 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन किया (मार्च 2004) और प्रथम किस्त के रूप में ₹ 1.80 करोड़ जारी किए । रा.म.आ. ने के.लो.नि.वि. को मार्च 2004 में परियोजना के निष्पादन हेतु ₹ 1.80 करोड़ जारी किए। आगे, स्थानीय निकायों द्वारा आरेखों की संस्वीकृति के पश्चात 24 माह की अवधि में कार्य को पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने निर्माण गतिविधियों में असामान्य विलंब पाये जिसे नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

अवधि	विवरण
सितम्बर 2004	हुडको ने भवन की रूपरेखाएं तैयार की और उन्हें दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया।

अवधि	विवरण
दिसम्बर 2004 तथा फरवरी 2005	दि.वि.प्रा. ने आरेखों पर कुछ अभ्युक्तियां की जिनके उत्तर हुडको द्वारा दिये गये थे।
मार्च 2006	मंत्रालय ने रा.म.आ. को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (रा.बा.अ.सं.आ.) को आबंटित स्थल पर समायोजित करने की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया।
जुलाई 2007	हुडको ने संशोधित योजना बनायी। इसे रा.म.आ. द्वारा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अप्रैल 2008	रा.म.आ. ने मंत्रालय से विभिन्न कार्यालयों को समायोजित करने के लिए एक समग्र योजना बनाने के लिए दि.वि.प्रा., हुडको तथा के.लो.नि.वि. के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया।
मई 2008	मंत्रालय ने रा.म.आ. को रा.बा.अ.सं.आ. के लिए स्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखने का निर्देश दिया।
अगस्त 2009	के.लो.नि.वि. ने रा.म.आ. को सूचित किया कि भूखंड की चार दीवारी का निर्माण हो गया है।
जनवरी 2010	डेढ़ साल व्यतीत होने के बाद, मंत्रालय ने रा.म.आ. को मई 2008 में लिये गये निर्णय पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
मार्च 2010	मंत्रालय के निर्देश का पालन करते हुए, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण तथा राष्ट्रीय महिला कोष ने अपने स्थान की आवश्यकता को प्रस्तुत किया।
जुलाई 2010	मंत्रालय ने निर्णय लिया कि तल क्षेत्र अनुपात की दृष्टि से, भूखंड केवल रा.म.आ. की आवश्यकताओं को ही समायोजित कर सकता है और केवल रा.म.आ. के उपयोग हेतु ही भवन के निर्माण का निर्णय लिया।
जून 2011	रा.म.आ. ने स्थानीय निकायों से अनुमति एवं दि.वि.प्रा. से भवन की स्थल योजना के अनुमोदन के साथ वास्तु संबंधी आरेखों के संपूर्ण कार्य को के.लो.नि.वि. को पुनः सौंप दिया।
नवम्बर 2011	मंत्रालय ने रा.म.आ. से रा.भा.नि.नि. को एक वैकल्पिक कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए कहा।

के.लो.नि.वि. (₹ 18.00 करोड़) तथा रा.भा.नि.नि. (₹ 16.51 करोड़) द्वारा लागत प्राक्कलनों के आधार पर, मंत्रालय ने अंततः रा.भा.नि.नि. के माध्यम से ₹ 16.51 करोड़ की संशोधित लागत पर इस कार्यालय भवन के निर्माण की सैद्धांतिक रूप में संस्वीकृति प्रदान की (जून 2012)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.म.आ. द्वारा अन्य कार्यालयों को समायोजित करने हेतु भवन निर्माण के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाने के विचार, जिसे पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था, के कारण जमीन के अधिग्रहण के पश्चात भी व्यापक विलंब हुआ था। प्रस्तावित स्थल पर संगठनों की संख्या तय करने में मंत्रालय असमर्थ था। निर्णय लेने की प्रक्रिया की तदर्थ भाव बोधता अंततः उभरने वाले अंतिम दृश्य में सुस्पष्ट थी। यह रा.म.आ. को ही भवन उपलब्ध कराने वाले निर्माण के प्रारंभिक दृश्य के समान था। इस अनावश्यक विलंब ने 2006 से 2010 तक के समूचे विकास को निष्फल बना दिया। यह असामान्य विलंब ₹ 9.44 करोड़[1] के उल्लेखनीय लागत वृद्धि तथा के.लो.नि.वि. के पास मार्च 2004 से ₹ 1.47 करोड़ के अवरोध का कारण बना। परिणामस्वरूप, भूमि की अधिप्राप्ति, चारदीवारी के निर्माण तथा हुडको को परामर्श शुल्क की अदायगी पर किया गया ₹ 79 लाख[2] का कुल व्यय भी निष्फल हो गया।

निर्माण में परिहार्य विलंब न केवल पर्याप्त समय एवं लागत वृद्धि में परिणत हुआ अपितु यह रा.म.आ. द्वारा अक्टूबर 2006, अर्थात वह तिथि जिस पर मार्च 2004 में आयोजित स्थायी वित्त समिति बैठक के अनुसार परियोजना को पूर्ण हो जाना चाहिए था, से ₹ 3.92 करोड़ के किराया राशि के परिहार्य भुगतान का कारण भी बना। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण की तिथि से 12 वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद, परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में ही थी।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (जून 2013) कि परियोजना में असामान्य विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त यह बताया कि रा.भ.नि.नि. ने तभी से स्थानीय निकायों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली थी तथा यह अपेक्षा की जाती है कि कार्य को आगे बिना किसी समय अथवा लागत वृद्धि के पूरा कर लिया जाएगा।

---

[1] के.लो.नि.वि. के जनवरी 2004 में प्रस्तुत प्राक्कलनों के अनुसार 3299 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल पर ₹ 9.44 करोड़ की लागत वृद्धि की गणना की गई है।

[2] ₹ 0.37 करोड़ भूमि अधिप्राप्ति पर, ₹0.33 करोड़ चारदीवारी के निर्माण पर तथा ₹ 0.09 करोड़ हुडको को अदा परामर्श शुल्क पर।

अध्याय XVI: युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय

16.1 अनुदानों की अप्रभावी मॉनीटरिंग

मंत्रालय राष्ट्रमण्डल खेल-2010 से संबंधित अनुदानों के निर्गम को प्रभावीरूप से मॉनीटरिंग करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 191.22 करोड़ की निधियां 17 से 26 महीनों के बीच की अवधि तक भा.खे.प्रा. के पास पड़ी थी। इसने अनुदानों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली संस्वीकृतियों के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय भा.खे.प्रा. को अनुवर्ती अनुदानें जारी करते समय अव्ययित अनुदानों पर अर्जित कुल ₹ 22.12 करोड़ के ब्याज पर ध्यान देने में विफल रहा।

XIXवें राष्ट्रमण्डल खेल पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा ने पाया (अगस्त 2011) कि भा.खे.प्रा. को किए गए निर्गमों को भारत सरकार के खातों में व्यय के रूप में माना गया था। तथापि, अंतिम लागत का पता केवल व्यय विवरणी सहित बिल के निपटान/उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के पश्चात लगेगा। युवा मामले मंत्रालय द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) को जारी अनुदानों के संबंध में अनुवर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

मंत्रालय ने भा.खे.प्रा. को राष्ट्रमण्डल खेल 2010 हेतु अनुदानें जारी करते समय निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की थीः

- निधियों की प्राप्ति पर भा.खे.प्रा. उसे तुरंत कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि को जारी करेगा तथा इस संबंध में मंत्रालय को एक अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

- वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित अनुदान, यदि कोई हो, को भा.खे.प्रा. द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अथवा मंत्रालय द्वारा इंगित किए जाने पर मंत्रालय को वापस करनी होगी।

- मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों में से भा.खे.प्रा. द्वारा निधियों को रखा जाने से (जैसा कि मंत्रालय द्वारा मार्च 2008 में पाया गया था) सुनिश्चित रूप से बचना चाहिए।

मंत्रालय तथा भा.खे.प्रा. के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि निम्नलिखित मामलों में रा.म.खे.-2010 हेतु मंत्रालय द्वारा भा.खे.प्रा. को जारी अनुदानें महत्वपूर्ण अवधियों तक अव्ययित पड़ी थी।

अनुदान का उद्देश्य	भा.खे.प्रा. को अनुदान जारी करने की तिथि	जारी राशि (₹ करोड़ में)	अव्ययित पड़ी राशि (₹ करोड़ में)	भा.खे.प्रा. के पास पड़ी रही निधियों की अवधि (महीनों में)
			नवम्बर 2012 को	
वर्ष 2010-11 के लिए स्टेडियम के उन्नयन/नवीकरण हेतु के.लो.नि.वि. को जारी निधियां	सितम्बर 2010	200.00	100.00	26
	मार्च 2011	72.40	22.40	20
वर्ष 2010-11 के लिए भा.खे.प्रा. के स्टेडियम के अलावा परियोजनाओं हेतु के.लो.नि.वि./डी.पी.एस. आर. के. पुरम को जारी निधियां	जून 2011	1.08	0.65	17
	अप्रैल 2011	17.25	17.25	19
	मार्च 2011	0.14	0.14	20
	अप्रैल 2011	0.05	0.05	19
योग		**290.92**	**140.49**	

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-12 के दौरान भा.खे.प्रा. को जारी ₹ 290.92 करोड़ की अनुदान में से ₹ 140.49 करोड़ अर्थात् 48.30 *प्रतिशत* राशि 17 से 26 महीनों के बीच की अवधि तक भा.खे.प्रा. के पास अव्ययित पड़ी थी। यह संस्वीकृति आदेशों में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में थी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अव्ययित अनुदान को वापस करने के मंत्रालय के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद निधियां भा.खे.प्रा. के पास रखी थी।

रा.मं.खे.-2010 हेतु भारतीय दल की तैयारी की योजना

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.म.खे.-2010 हेतु भारतीय दल की तैयारी के उद्देश्य हेतु विशिष्ट अनुदानों के मामले में काफी अधिक अव्ययित शेष भा.खे.प्रा. द्वारा रखा गया था। वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	जारी अनुदान (₹ करोड़ में)	वि.व. की समाप्ति पर अव्ययित शेष (₹ करोड़ में)
2008-09	25	3.98
2009-10	223.77	110.02
2010-11	-	54.93
2011-12	-	50.73

भा.खे.प्रा. द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्रों की जांच ने प्रकट किया कि 31 मार्च 2011 तथा 31 मार्च 2012 को भा.खे.प्रा. के पास पड़े क्रमशः ₹ 54.93 करोड़ तथा ₹ 50.73 करोड़ के अव्ययित शेषों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु वैधीकृत किए जाने की मांग की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदानों को विशिष्ट रूप से रा.मं.खे.-2010 के लिए जारी किया गया था, तथा मंत्रालय द्वारा अव्ययित अनुदानों के पुनः वैधीकरण हेतु कोई औचित्य नहीं था क्योंकि खेल अक्तूबर 2010 में समाप्त हो गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.खे.प्रा. ने रखी गई निधियों से सावधि जमा के रूप में किए गए निवेशों पर ₹ 22.12 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। फिर भी मंत्रालय ने अनुवर्ती अनुदान जारी करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि भा.खे.प्रा. ने ब्याज को अपनी स्वयं की आय के रूप में माना। ₹ 22.12 करोड़ के कुल ब्याज में से, ₹ 6.30 करोड़ को भा.खे.प्रा. के मुख्य खाते में अंतरित किया गया था (मार्च 2012)। भा.खे.प्रा. ने इस कार्य को इस आधार पर उचित ठहराया कि वह मंत्रालय से कमी के आधार पर अर्थात् भा.खे.प्रा. की प्रत्याशित प्राप्तियों का उपदान करने के पश्चात, गैर-योजनागत अनुदानें प्राप्त करता है। तथापि, यह उत्तर वैध नहीं है क्योंकि निधियां खिलाड़ियों की तैयारी के विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने के लिए प्रदान की गई थी। इस प्रकार रा.मं.खे.-2010 के बाद उस पर अर्जित ब्याज सहित उनका रखा जाना अनियमित था।

इसलिए, मंत्रालय भा.खे.प्रा. को जारी अनुदानों के उपयोग को प्रभावी रूप से मॉनीटर करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, निधियां लम्बी अवधि तक भा.खे.प्रा. के पास पड़ी रही।

मामला मई 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XVII : सामान्य

17.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के निरन्तर अनुदेशों/अनुशंसाओं के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने, लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा बीतने के बाद भी 43 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारी/शोधक कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी।

लोक सभा सचिवालय ने, सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत होने के तुरन्त पश्चात इनमें निहित विभिन्न पैराग्राफों पर उपचारी/की गई शोधक कार्रवाई दर्शाते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां भेजने के लिए अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए।

संसद में, 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किए गए उनके नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) का प्रस्तुतीकरण तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यह अनुशंसा की कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष तथा इसके बाद के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर का.टि., संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से चार माह के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से जांच करके उनको प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, 29 अप्रैल 2010 में संसद को प्रस्तुत उनके ग्यारहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में समिति ने अनुशंसा की कि उपचारी कार्रवाई करने तथा लो.ले.स. को का.टि. प्रस्तुत करने में असामान्य विलम्बों के सभी मामलों में व्यक्तिगत रूप से मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

समिति ने यह भी इच्छा की कि का.टि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्बों से संबंधित मामलों को आवधिक रूप से, ज्यादातर तिमाही अंतराल पर सचिव समिति (स.स.) के समक्ष लाया जाना चाहिए ताकि सभी चूककर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा का.टि. के प्रस्तुतीकरण पर कार्रवाही की जाए।

उनकी अनुशंसाओं के अनुसरण में, स.स. द्वारा कैबिनेट सचिवालय में कई बैठकें की गई थीं जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए थेः

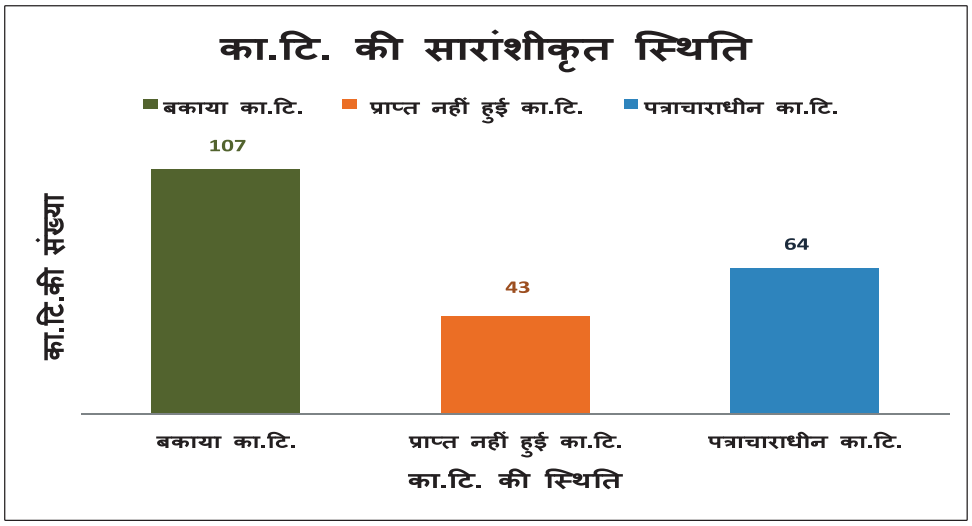
(i) मंत्रालयों/विभागों में सचिव, जो मुख्य लेखांकन अधिकारी है, निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा पैराओं/लो.ले.स. प्रतिवेदनों पर का.टि./का.रि. को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(ii) उपयुक्त शोधक उपाय करने के अतिरिक्त नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों के पैराओं पर का.टि. तथा लो.ले.स. की अनुशसाओं पर का.रि. के प्रस्तुतीकरण की मॉनीटरिंग हेतु प्रत्येक मंत्रालय द्वारा वित्तीय सलाहकार सहित सचिव/विशेष सचिव द्वारा अध्यक्षता वाली स्थायी लेखापरीक्षा समिति (स्था.ले.प.स.) स्थापित की जाएगी। स्थ.ले.प.स. मासिक आधार पर बैठक करेगी तथा इसके कार्य क्षेत्र (का.क्षे.) में लेखापरीक्षा पैराओं/लो.ले.स. के प्रतिवेदनों में इंगित अनियमितताओं के आवर्तन से बचने हेतु, लिए जाने वाली निवारक कार्रवाई शामिल होगी।

(iii) का.टि. के तीव्र प्रस्तुतीकरण हेतु का.टि. अदालतों/कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

अपनी बैठक में स.स. ने पाया कि लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों ने पहले ही स्था.ले.प.स. स्थापित कर ली थी तथा शेष स्था.ले.प.स. को स्थापित करने की प्रक्रिया में थे। स.स. ने आगे पाया कि का.टि. अदालतों/कार्यशालाओं के संबंध में प्रगति धीमी थी। स.स. ने निर्देश दिया कि सभी मंत्रालय का.टि. की विलंबता का निपटान करने हेतु विशेष अभियान प्रारम्भ करें।

31 मार्च 2012 को (**परिशिष्ट-I**) समाप्त अवधि तक संघ सरकार (सिविल) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति की स्थिति के पुनरीक्षण से प्रकट हुआ कि उपर्युक्त अनुदेशों के बावजूद मंत्रालयों ने बड़ी संख्या में पैराग्राफों के संबंध में उपचारी/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। 107 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. भेजनी अपेक्षित थी, में से 43 पैराग्राफों के संबंध में मार्च 2013 तक बिल्कुल भी का.टि. प्राप्त नहीं हुई थी। विवरण निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए गए हैं:



64 पैराग्राफ, जो पत्राचाराधीन थे, के संबंध में अंतिम का.टि. विभिन्न स्तरों पर लम्बित थी। इन 107 पैराग्राफों में से 11 पैराग्राफ, ऐसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदना से संबंधित थे जो 10 वर्षों से अधिक पुराने थे ।

17.2 ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति के कहने पर जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 33 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से 18 के प्रत्युत्तर नहीं भेजे थे।

लो.ले.स. की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रत्युत्तर, पैराग्राफ की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए थे।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के इस प्रतिवेदन में शामिल 33 पैराग्राफों में से 18 में, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। ब्यौरे **परिशिष्ट- II** में दर्शाए गए हैं।

नई दिल्ली
दिनांक: 19 अगस्त 2013

(रॉय मथरानी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 20 अगस्त 2013

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1

(पैराग्राफ सं. 2.2 के संदर्भ में)

लाइसेंस फीस की कम वसूली

अवधि (महीनों में)	दि.दु.यो. द्वारा प्रभारित लाइसेंस शुल्क की राशि (₹ में)	सं.नि. आदेशों के अनुसार वसूलनीय राशि (₹ में)	लाइसेंस शुल्क की कम वसूली की राशि (₹ में)
16 मार्च 1999 से 31 मार्च 2002 (36.5)	4742	404x220=88880	(88880-4742)x36.5=3071037
अप्रैल 2002 से मार्च 2005 (36)	4742	404x249=100596	(100596-4742)x36=3450744
अप्रैल 2005 से मार्च 2008 (36) *एटीएम: जनवरी 2007 से मार्च 2008 (15)*	4742 *2618*	404x279=112716 *11.90x279=3320*	(112716-4742)x36=3887064 *(3320-2618)x15=10530*
अप्रैल 2008 से मार्च 2011 (36) *एटीएम: अप्रैल 2008 से मार्च 2011(36)*	4742 2618	404x337=136148 11.90x337=4010	(136148-4742)x36=4730616 (4010-2618)x36=50112
अप्रैल 2011 से नवम्बर 2012 (20) *एटीएम: अप्रैल 2011 से नवम्बर 2012 (20)*	4742 *2618*	404x455=183820 *11.90x455=5414*	(183820-4742)x36=3581560 *(5414-2618)x20=55920*
योग			**18837583**

अनुबंध-2

(पैरा सं. 6.2.3.2 के संदर्भ में)

एच.वी.ए.सी. एवं बी.एम.एस. कार्य हेतु अदा की गई राशि में वृद्धि के विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अ.भा.आ. सं.	ठेकेदार का नाम	आर.ए. बिल	अंतिम आर.ए. बिल तक एच.वी.ए.सी. एवं बी.एम.एस. कार्य पर खर्च की गयी बढ़ी हुई राशि
1.	भोपाल	जे.एम.सी. प्रोजेक्टस(आई) लिमिटेड	17, बिल सं. 132/12-13 दिनांक 20.07.2012	68,28,338
2.	ऋषिकेश	जे.एम.सी. प्रोजेक्टस(आई) लिमिटेड	22, बिल सं. 132/12-13 दिनांक 20.07.2012	88,04,197
			कुल	**1,56,32,535**

अनुबंध-3

(पैरा सं. 6.2.4 के संदर्भ में)

सलाहकारों के पास रखी गयी निधियों की स्थिति

परियोजना सलाहकार का नाम	आवासीय परिसर	ली गयी अवधि	परियोजना सलाहकार के पास जमा रखी गयी निधियों के लिए दिनों की सं.		परियोजना सलाहकार के पास जमा रखी गयी निधियाँ		जमा ब्याज @ 7.9 %
			अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	
एच.एल.एल.	ऋषिकेश	07.11.08 से 30.10.09	84	1	13.45 करोड़	3.87 करोड़	0.61
एच.एल.एल.	पटना	07.11.08 से 30.10.09	85	14	6.29 करोड़	1.29 करोड़	0.28
एच.एस.सी.सी.	रायपुर	18.11.08 से 15.03.10	50	4	9.94 करोड़	0.57 करोड़	0.56
एच.एस.सी.सी.	भुवनेश्वर	18.11.08 से 14.01.10	166	8	16.66 करोड़	4.66 करोड़	1.27
कुल							**2.72**

अनुबंध-4

(पैरा सं. 6.3.6 के संदर्भ में)

वर्ष 2011-12 के लिए बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं में फॉर्मूला एवं कम मूल्य विकल्पों के आधार पर कीमतों की तुलना

(राशि ₹ में)

	दवा संविरचना		ब्रांडेड फॉर्मूला में सूचिबद्ध उच्चतर मूल्य ब्रांड			बाजार में उपलब्ध कमतर मूल्य ब्रांड के उदाहरण[1]					
क्र.सं.	दवा संविरचना	बाजार में उपलब्ध कमतर मूल्य के ब्रांडों की सं.	फॉर्मूला में उपलब्ध ब्रांड	निर्माता का नाम	छूट के बाद उपलब्ध कीमत	बाजार में उपलब्ध कमतर मूल्य ब्रांड	निर्माता का नाम	अ.खु.मू.	जेनरिकए वं ब्रांडेड के मूल्य में तुलना	2011-12 में उपलब्ध दवाओं की मात्रा	परिहार्य अतिरिक्त व्यय
1.	ग्लीक्लैजाइड-60 मि.ग्रा.	22	डायमाइक्रोन एक्स.आर. (60 मि.ग्रा.)	सर्दिया फॉर्मास्यूटिकल्स (इं) लि.	7	क्लैज ओ.डी. (60 मि.ग्रा.)	फ्रैंको इंडियन रेमेडीज	4.9	2.1	1566278	3289183.80
2.	ग्लीमेपाइराइड-2 मि.ग्रा.	141	अमारिल (2 मि.ग्रा.)	एवेन्टिस फार्मा लि.	8.3	एजुलिक्स (2 मि.ग्रा.)	डेल्टा (टारेंट) फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	5.3	3	2503830	7511490
3.	नाइकोरेंडिल-10 मि.ग्रा.	16	निकोरन (10 मि.ग्रा.)	टोरेंट फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	8.78	ड्योरेन्डिल (10 मि.ग्रा.)	मेड्रिक सैमिरा लि.	5.9	2.88	381890	1099843.2
4.	टेलमिसरटन-40 मि.ग्रा.+ हाइड्रोक्लोरो-	42	आर्बिटेल-एच. (40+12.5)	माइक्रो लैब्स लि.	5.51	टेलमिकाइंड एच (40+12.5)	मैनकाइंड फॉर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	3.25	2.26	1255760	2838017.6

[1] स्रोतःwww.medguideindia.com

	टियडाइज्ड 12.5 मि.ग्रा.										
5.	फेक्सोफेनाडाइन-120 मि.ग्रा.	81	एलेग्रा एफ.सी. (120 मि.ग्रा.)	एवेन्टिस फार्मा लि.	6.22	हिस्टाफ्री (120 मि.ग्रा.)	मैनकाइंड फॉर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	4.75	1.47	1668980	2453400.6
6.	लेवोसेट्रीजीन-5 मि.ग्रा. मोंटेलुकास्ट-10 मि.ग्रा.	87	मोंटेयर एल.सी.	सिपला लि.	8.7	लेजाइन एम. (5+10)	जेनक्स (हेटेरो हेल्थकेयर लि.)	5.9	2.8	1295410	3627148
7.	सेट्रीजीन 10 मि.ग्रा.	336	सेटजीन	ग्लैक्सोस्मिथ-क्लाइन लि.	2.44	बीलर्ट (10 मि.ग्रा.)	जेनक्स हेल्थकेयर	1.2	1.24	4179000	5181960
8.	ग्लीक्लेजाइड 60 मि.ग्रा.	21	डायनोर्म ओ.डी. 60	माइक्रो लैब्स लि.	4.42	न्यूजाईड (60 मि.ग्रा.)	इनटास फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	2.7	1.72	384370	661116.4
9.	एम्लोडिपाईन-5 मि.ग्रा. हाइड्रोक्लोरो टियजाईड-12.5 मि.ग्रा.	3	एमलौंग-एच	माइक्रो लैब्स लि.	2.6	एमलोकाइंड-एच (5+12.5)	मैनकाइंड फॉर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	1.25	1.35	680100	918135
10.	रामीप्रिल-10 मि.ग्रा.	32	कारडैक ई.10	एवेन्टिस फार्मा लि.	9.98	प्रोएस (10 मि.ग्रा.)	एलेम्बिक केमिकल वर्क्स को.लि.	6.35	3.63	391320	1420491.6
11.	रामीप्रिल-50 मि.ग्रा.	105	कारडाक ई. 5	एवेन्टिस फार्मा लि.	7.7	नामीप्रिल (5 मि.ग्रा.)	निकोलस पिरामल इंडिया प्रा.लि.	5.8	1.9	2047630	3890497
12.	एटेनोलोल-50 मि.ग्रा.	113	एटेन 50	कैडिला हेल्थकेयर लि.	1.94	एटेकाइंड (50 मि.ग्रा.)	मैनकाइंड फॉर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	1.08	0.86	973874	837531.64

13.	एटेनोलोल-50 मि.ग्रा. इंडेपेमाइड-2.5 मि.ग्रा.	3	एटेन डी	कैडिला हेल्थकेयर लि.	2.45	एटेकाइंड डी (50+2.5)	मैनकाइंड फॉर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	1.14	1.31	135944	178086.64
14.	एटेनोलोल-25 मि.ग्रा.	71	एटेन 25	कैडिला हेल्थकेयर लि.	1.26	लेटेनोल (25 मि.ग्रा.)	ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लि.	0.7	0.56	545328	305383.68
15.	मेकोबालामिन-500 मा.ग्रा.	85	मेथाईकोबाल टेबलेट	वोकाहार्डट लि.	4.19	न्यूरोकाइंड (500 मा.ग्रा.)	मैनकाइंड फॉर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	1.99	2.2	7074930	15564846
16.	एस्पिरीन-75 मि.ग्रा.	23	एकोस्प्री-75	यू.एस.वी. लि.	0.21	सी.वी. एस्पिरीन (75 मि.ग्रा.)	कैडिला फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	0.19	0.02	4889244	97784.88
17.	पेंटोप्राजोल सोडियम सेसक्विहाइड्रेट-20 मि.ग्रा. डोमपेरीडोन-10 मि.ग्रा.	134	पैन-डी	एल्केम लेबोरेट्रीज लि.	5.34	पैंटाडोम टैब (20+10)	मैनकाइंड फॉर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	3	2.34	4958040	11601813.6
18.	पैंटोप्राजोल सोडियम सेसक्विहाइड्रेट-40 मि.ग्रा.	724	पैन-40	एल्केम लेबोरेट्रीज लि.	4.54	पैंटाकाइंड (40 मि.ग्रा.)	मैनकाइंड फॉर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	1.75	2.79	4433140	12368460.6
19.	मेटफोरमिन-500 मि.ग्रा.	154	ग्लाईसीफेज एस.आर.	फ्रैंको इंडियन फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	1.22	ग्लूमेट ई.एक्स.टी. (500 मि.ग्रा.)	सिपला लि.	0.65	0.57	5210940	2970235.8
20.	एमलोडिपाईन-5 मि.ग्रा.	164	एमलौंग-5	माइक्रो लैब्स लि.	2.5	एमलोसिल (5 मि.ग्रा.)	निकोलस पिरामल इंडिया लि.	1.33	1.17	4121220	4821827.4

21.	पैंटोप्राजोल सोडियम सेसक्विहाइड्रेट-40 मि.ग्रा.	1010	पैंटोसिड	सन फॉर्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लि.	4.82	न्यूपेंटा (40 मि.ग्रा.)	मैकल्योड्स फॉर्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लि.	2.15	2.67	4072248	10872902.16
										योग	**92510155.60**

अनुबंध-5

(पैरा 6.3.7 के संदर्भ में)

के.स.स्वा.यो. दिल्ली में दवा की उपलब्धता पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	योग	प्रतिशत
अ. फॉर्मूला में सूचीबद्ध दवाएँ (एच.एस.सी.सी. द्वारा)					
i ब्रांडेड	11.73	56.03	125.53@	193.29	18.54
ii जेनरिक	0.33	0.84	0.83	2.00	0.19
iii) स्थानीय खरीद, ब्रांडेड (एम.एस.डी.)	0.38	0.49	0.48	1.35	0.13
योग (अ)	12.44	57.36	126.84	196.64	18.87
ब. फॉर्मूला के बाहर दवाएँ					
i) जीवन रक्षक दवाएँ	75.32	102.21	104.11	281.64	27.02
ii) पायलट परियोजना	77.16	110.83	0*	187.99	18.04
iii) इंसुलिन-प्रत्यक्ष	7.63	8.43	10.22	26.28	2.52
iv) स्थानीय खरीद (स्वास्थ्य केन्द्र)	155.60	108.45	85.76	349.81	33.56
योग (ब)	**315.71**	**329.92**	**200.09**	**845.71**	**81.13**
कुल योग (अ+ब)	**328.15**	**387.28**	**326.93**	**1042.36**	**100.00**

* 2011-12 के दौरान फॉर्मूला में शामिल

@ पायलट परियोजना के शामिल ₹ 97.98 करोड़

अनुबंध-6

(पैरा 6.3.8 के संदर्भ में)

ब्रांडेड एवं जेनरिक दवा फॉर्मूला में समान दवाओं की सूची

क्र.सं.	ब्रांडेड फॉर्मूला में दवा			जेनरिक फॉर्मूला में समान संविरचना वाले दवा	
	वी.एम.एस. संख्या	ब्रांड का नाम	निर्माता का नाम	वी.एम.एस. संख्या	
1.	पी03097	एलेग्रा 120 मि.ग्रा.	एवेन्टिस फार्मा लि.	जी03007	फेक्सोफेनाडाइन 120 मि.ग्रा. टेबलेट्स
2.	पी03098	एलेग्रा 180 मि.ग्रा.	एवेन्टिस फार्मा लि.	जी03008	फेक्सोफेनाडाइन 180 मि.ग्रा. टेबलेट्स
3.	पी03100	सेटजीन	ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन लि.	जी03009	सेट्रीजीन 10 मि.ग्रा. टेबलेट्स
4.	पी09082	बेटालोक 25 मि.ग्रा.	एस्ट्रा जेनेका फार्मा इंडिया लि.	जी12006	मेटोप्रोलो टारट्रेट 25 मि.ग्रा. टेबलेट्स
5.	पी09083	बेटालोक 50 मि.ग्रा.	एस्ट्रा जेनेसिया फार्मा इंडिया लि.	जी12007	मेटोप्रोलो टारट्रेट 50 मि.ग्रा. टेबलेट्स
6.	पी09080	बेटाकैप टी.आर. 40	सन फॉर्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लि.	जी12010	प्रोपैनोलोल हाइड्रोक्लोराइड 40 मि.ग्रा. टेबलेट्स
7.	पी09107	डिलजेम-30	टोरेंट फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	जी12019	डिल्टियाजेम हाइड्रोक्लोराइड 30 मि.ग्रा. टेबलेट्स
8.	पी09150	नेबिस्टार-एस.ए.	ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लि.	जी12034	एम्लोडिपाईन 2.5 मि.ग्रा. टेबलेट्स
9.	पी09062	एम्लोप्रेस- 5	सिपला लि.	जी12035	एम्लोडिपाईन 5 मि.ग्रा. टेबलेट्स
10.	पी09063	एम्लोवास-5	मैकल्योड्स फॉर्मास्यूटिकल्स लि.		
11.	पी09057	एमलौंग -10	माइक्रो लैब्स लि.	जी12036	एम्लोडिपाईन 10 मि.ग्रा. टेबलेट्स
12.	पी09071	एटेन 50	कैडिला हेल्थकेयर लि.	जी12037	एटेनोलोल 50 मि.ग्रा. टेबलेट्स
13.	पी09081	बेटाकार्ड-50	टोरेंट फॉर्मास्यूटिकल्स लि.		

14.	पी09067	आर्कामाईन	यूनीकेम लेबोरेट्रीज लि.	जी12041	क्लोनिडाईन हाइड्रोक्लोराईड 100 मा. ग्रा. टेबलेट्स
15.	पी09116	एनवास 2.5	कैडिला फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	जी12043	एनालाप्रिल मैलिएट 2.5 मि.ग्रा. टेबलेट्स
16.	पी09117	एनवास 5	कैडिला फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	जी12044	एनालाप्रिल मैलिएट 5 मि.ग्रा. टेबलेट्स
17.	पी09115	एनवास 10	कैडिला फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	जी12045	एनालाप्रिल मैलिएट 10 मि.ग्रा. टेबलेट्स
18.	पी09097	कोवान्स- 25	रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि.	जी12047	लोसारटन पोटाशियम 25 मि.ग्रा. टेबलेट्स
19.	पी09135	लोसार-25	यूनीकेम लेबोरेट्रीज लि.		
20.	पी09166	रीपेस-25 मि.ग्रा.	सन फॉर्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लि.	जी12048	लोसारटन पोटाशियम 50 मि.ग्रा. टेबलेट्स
21.	पी09098	कोवान्स- 50	रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि.		
22.	पी09166	रीपेस-50 मि.ग्रा.	सन फॉर्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लि.		
23.	पी09190	टोज्जार- 50	टोरेंट फॉर्मास्यूटिकल्स लि.		
24.	पी09136	लोसार-50	यूनीकेम लेबोरेट्रीज लि.		
25.	पी09113	इकोस्प्रिन-75	यू.एस.वी. लि.	जी12065	एसीटिल सेलीसिलिक एसिड 75 मि.ग्रा. टेबलेट्स
26.	पी09132	लोप्रिन डी.एस.	यूनीकेम लेबोरेट्रीज लि.	जी12077	एस्पिरीन 150 मि.ग्रा. टेबलेट्स
27.	पी09103	डेपलेट	टोरेंट फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	जी12078	क्लोपीडोग्रेल 75 मि.ग्रा. टेबलेट्स
28.	पी09096	क्लोपीग्रेल	यू.एस.वी. लि.		
29.	पी09161	रामीस्टार 2.5	ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लि.	जी12080	रामीप्रिल 2.5 मि.ग्रा. टेबलेट्स
30.	पी09124	होपेस-2.5	माइक्रो लैब्स लि.		

31.	पी09089	कारडेस 5	एवेन्टिस फार्मा लि.	जी12081	रामीप्रिल 5 मि.ग्रा. टेबलेट्स
32.	पी09162	रामीस्टार 5	ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लि.		
33.	पी09123	होपेस - 5	माइक्रो लैब्स लि.		
34.	पी09133	लोरवास	टोरेंट फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	जी12082	इंडेपेमाइड 2.5 मि.ग्रा. टेबलेट्स
35.	पी09186	टाईड-10	टोरेंट फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	जी16013	टोरसेमाइड 10 मि.ग्रा. टेबलेट्स
36.	. पी13015	ओसिड 20	कैडिला हेल्थकेयर लि.	जी17004	ओमेप्राजोल 20 मि.ग्रा. कैप्सूल्स
37.	पी13016	ओमेज	डॉ. रेड्डीज लैब्स लि.		
38.	पी13026	रैनटैक 150	जे.बी. केमिकल्स एवं फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	जी17006	रैन्टीडाईन हाइड्रोक्लोराइड 150 मि.ग्रा. टेबलेट्स
39.	पी13017	पैन-डी	एल्केम लेबोरेट्रीज लि.	जी17033	पैन्टोप्राजोल 40 मि.ग्रा. टेबलेट्स
40.	पी13023	पैन्टोडैक टेबलेट्स	कैडिला हेल्थकेयर लि.		
41.	पी13022	पैन्टोसिड	सन फॉर्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लि.		
42.	पी04037	डाओनिल	एवेन्टिस फार्मा लि.	जी18017	ग्लीबेनक्लैमाईड 5 मि.ग्रा. टेबलेट्स
43.	पी04036	सेटापिन एक्स.आर. 500 मि.ग्रा.	एवेन्टिस फार्मा लि.	जी18020	मेटफॉर्मिन 500 मि.ग्रा. टेबलेट्स
44.	पी04059	ग्लाईसिफेज एस.आर.	फ्रैंको इंडियन फॉर्मास्यूटिकल्स लि.		
45.	पी27001	थाईरोनॉर्म 100 मा.ग्रा.	एबॉट इंडिया लि.	जी18030	थाईरोक्सिन सोडियम 100 मा.ग्रा. टेबलेट्स
46.	पी04046	एल्ट्रोक्सिन 100 मा.ग्रा.	ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन लि.		
47.	पी27004	थाइरॉक्स-100	मैकल्योड्स फॉर्मास्यूटिकल्स लि.		
48.	पी04033	एमारिल 1 मि.ग्रा.	एवेन्टिस फार्मा लि.	जी18041	ग्लीमेप्राईड 1 मि.ग्रा. टेबलेट्स
49.	पी04034	एमारिल 2 मि.ग्रा.	एवेन्टिस फार्मा लि.	जी18042	ग्लीमेप्राईड 2 मि.ग्रा. टेबलेट्स
50.	पी04052	ग्लीजीड-80	पैनेसिया बायोटेक	जी18044	ग्लीक्लैजाईड 80 मि.ग्रा. टेबलेट्स

51.	पी04040	डायमाइक्रोन	सर्दिया फॉर्मास्यूटिकल्स (आई.) प्राइवेट लि.		
52.	पी04054	ग्लूकोबे 50	बेयर इंडिया लि.	जी18047	एकारबोस 50 मि.ग्रा. टेबलेट्स
53.	पी04038	डायबोस-50	माइक्रो लैब्स लि.		
54.	पी08015	ट्रिप्टोमेर 25 मि.ग्रा.	वोकहार्ड्ट लि.	जी24012	अमिट्रिप्टिलाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 मि.ग्रा. टेबलेट्स
55.	पी08007	एंक्सिट-0.25	माइक्रो लैब्स लि.	जी24017	एल्प्राजोलम 0.25 मि.ग्रा. टेबलेट्स
56.	पी08013	ट्रिका- 0.25	यूनीकेम लेबोरेट्रीज लि.		
57.	पी08006	एल्प्रैक्स-0-25	टोरेंट फॉर्मास्यूटिकल्स लि.		
58.	पी08005	एल्प्रैक्स-0.5	टोरेंट फॉर्मास्यूटिकल्स लि.	जी24018	एल्प्राजोलम 0.5 मि.ग्रा. टेबलेट्स
59.	पी03104	मोंटेयर एल.सी.	सिपला लि.	जी25031	मोन्टेलूयूकास्ट 10 मि.ग्रा. टेबलेट्स

अनुबंध-7

(पैरा 6.3.8 के संदर्भ में)

जेनरिक फॉर्मूला एवं ब्रांडेड फॉर्मूला दोनों/पायलट परियोजना में सूचीबद्ध दवाओं के कीमतों की तुलना

क्र.सं.	ब्रांडेड फॉर्मूला/पायलट परियोजना में ब्रांड का नाम	जेनरिक दवा का नाम	फॉर्मूला/पायलट परियोजना में प्रति टेबलेट ब्रांड कीमत (₹ में)	प्रति टेबलेट जेनरिक कीमत (जनऔषधि स्कीम कीमत)[2] (₹ में)	कीमत में अंतर (₹ में)	पायलट परियोजना में उपलब्ध मात्रा	परिहार्य अतिरिक्त व्यय (₹ में)
वर्ष 2011-12							
1.	वोवेरन एस.आर. 100	डायक्लोफेनैक सोडियम आई.पी. 100 मि.ग्रा. एस.आर.	3.38	0.34	3.04	1508550	4585992
2.	निमुलिड 100	निमेसुलाईड आई.पी. 100 मि.ग्रा.	2.48	0.27	2.21	748900	1655069
3.	पैन-40	पेंटाप्राजोल 40 मि.ग्रा. टैब्स	4.54	1.03	3.51	4433140	15560321
4.	पैन्टोडैक		4.35		3.32	480460	1595127
5.	पैन्टोसिड		4.8		3.77	4072248	15352375
6.	ओमेज	ओमेप्राजोल आई.पी. 20 मि.ग्रा.	3.53	0.69	2.84	1027955	2919392.2
7.	ओसिड 20		3.54		2.85	2094810	5970208.5
8.	सेटजीन	टैब सिटिराजीन 10 मि.ग्रा.	2.44	0.28	2.16	4179000	9026640
9.	डॉक्सीफ्लो 400	डॉक्सोफिलीन 400 मि.ग्रा.	3.02	1.47	1.55	2326318	3605792.9
10.	मैजेटोल एस.आर. 200	कार्बामैजेपिन 200 मि.ग्रा. टैब्स	1.02	0.92	0.1	332730	33273
11.	बेटाकार्ड-50	एटेनोलोल 50 मि.ग्रा. टैब्स	1.96	0.5	1.46	266494	389081.24
12.	एनवास5	एनालाप्रिल 5 मि.ग्रा. टैब्स	1.92	0.66	1.26	851430	1072802
13.	एल्प्रैक्स-0.5	एल्प्राजोलम 0.5 मि.ग्रा. टैब्स	1.67	0.3	1.37	686235	940141.95

[2] सभी जेनरिक दवाओं के उपलब्ध कीमतों की अनुपस्थिति में, रसायनिक एवं खाद मंत्रालय के जनऔषधि स्कीम की कीमतें प्रयोग की गई हैं।

14.	एंक्सिट -0.25	एल्प्राजोलम 0.25 मि.ग्रा. टैब्स	1.19	0.26	0.93	556110	517182.3
15.	एल्प्रैक्स-0-25		1.01		0.75	1868025	1401019
16.	ट्रिका- 0.25		0.81		0.55	235120	129316
17.	लिस्ट्रिल-5	लिसिनोप्रिल 5 मि.ग्रा.	3.94	0.88	3.06	228046	697821
18.	कोवान्स- 50	लोसार्टन पोटाशियम 50 मि.ग्रा. टेबलेट्स	4.72	0.94	3.78	569760	2153692.8
19.	रीपेस 50		4.09		3.15	820910	2585867
20.	टोज्जार- 50		4.26		3.32	317710	1054797
21.	लोसार-50		3.72		3.72	1139220	4237898
22.	डाओनिल	ग्लिबेनक्लैमाईड 5 मि.ग्रा. टैब्स	0.67	0.27	0.4	149750	59900
23.	सेटापिन एक्स.आर. 500 मि.ग्रा.	मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराईड 500 मि.ग्रा. टैब्स	1.74	0.6	1.14	1475682	1682277
24.	ग्लाइसीफेज एस.आर.		1.22		0.62	5210940	3230783
25.	ग्लूफॉर्मिन एक्स.एल. 500		1.39		0.79	2027060	1601377.4
26.	ग्लूफॉर्मिन एक्स.एल. 1000	मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराईड 1000 मि.ग्रा. टैब	2.15	0.77	1.38	1491790	2058670
27.	एमारिल 2 मि.ग्रा.	ग्लीमेपाइराईड 2 मि.ग्रा. टैब	8.31	1.18	7.13	2503830	17852308
28.	ग्लीमर 2 मि.ग्रा.		7.62		6.44	1207690	7777524
29.	एमारिल 1 मि.ग्रा.	ग्लीमेपाइराईड 1 मि.ग्रा. टैब	4.49	0.79	3.7	1657360	6132232
30.	ग्लीमर 1 मि.ग्रा.		3.93		3.14	698490	2193259
						योग	**118072139.29**

अनुबंध 8

(पैरा 6.3.9 के संदर्भ में)

एच.एस.सी.सी. द्वारा दवाओं की उपलब्धता में देरी

एच.एस.सी.सी. को आवश्यकता की सूचना का माह	अवधि जिसके दौरान आपूर्ति प्राप्त की गई	सूचना के पश्चात् आपूर्ति की प्राप्ति में देरी	अवधि, जिसके दौरान दवाएँ स्वास्थ्य केन्द्र में दी गई	सूचना के पश्चात् स्वास्थ्य केन्द्र में प्राप्ति में देरी	अभ्युक्तियाँ
2011-12					
जनवरी, 12	मार्च से मई, 12	2 से 5 माह	मार्च से जुलाई, 12	2 से 7 माह	पहली किश्त
मार्च, 12	मई से अगस्त, 12	2 से 5 माह	मई से सितम्बर, 12	2 से 7 माह	दूसरी किश्त
2010-11					
जून, 10	जून से नवम्बर, 10	1 से 6 माह	जुलाई, 10 से जनवरी, 11	1 से 8 माह	पहली किश्त
जनवरी, 11	फरवरी, 11 से जून, 11	1 से 6 माह	फरवरी, 11 से सितम्बर, 11	1 से 9 माह	दूसरी किश्त

अनुबंध 9

(पैरा 6.3.9 के संदर्भ में)

फार्मूला में सूचीबद्ध दवाएं जो स्थानीय औषधि विक्रेताओं से उच्च दर पर खरीदी गई, के कारण 2010-11 और 2011-12 के दौरान हुई हानि

क्र.सं.	दवा का नाम	स्थानीय खरीद दर	स्थानीय खरीद दर पर छूट	मंत्रालय द्वारा नियत की गई दरें	प्रति इकाई दर में अंतर	स्थानीय उपलब्ध माला	सरकार को हानि
वर्ष 2010-11							
1.	डुओलीन रेष्यूलस -2.5 मि.ग्रा.+ 500 मि.ग्रा.	10.33	9.03	6.3	2.73	21370	58340.1
	डुओलीन नेबुलाइजर	10.33	9.03	6.3	2.73	7447	20330.31
	डुओलीन - एन ए	10.33	9.03	6.3	2.73	58083	158566.59
	डुओलीन --2.5 मि.ली.	10.33	9.03	6.3	2.73	110358	301277.34
	डुओलीन रस्पयूले -एन ए	10.33	9.03	6.3	2.73	141455	386172.15
	डुओलीन नेबुलाइजेशन	10.33	9.03	6.3	2.73	3571	9748.83
	डुओलीन	10.33	9.03	6.3	2.73	2987	8154.51
	डुओलीन - एन ए	10.33	9.03	6.3	2.73	14260	38929.8
2.	फोराकोर्ट 200 एम डी आई	278	243.11	181.5	61.61	603	37150.83
	फोराकोर्ट--200	278	243.11	181.5	61.61	5870	361650.7
	फोराकोर्ट इन्हेलर 200	278	243.11	181.5	61.61	119	7331.59
	फोराकोर्ट 200	278	243.11	181.5	61.61	38	2341.18
	फोराकोर्ट --6+200 मा.ग्रा.	278	243.11	181.5	61.61	80	4928.8
3.	जेमकल	9.81	8.58	6.28	2.3	882	2028.6
	जेमकल --0.25+500+7.5 मि.ग्रा.	9.81	8.58	6.28	2.3	47712	109737.6
	जेमकल –0 मि.ग्रा.	9.81	8.58	6.28	2.3	10196	23450.8
	जेमकल --500	9.81	8.58	6.28	2.3	182080	418784
	जेमकल --एन ए	9.81	8.58	6.28	2.3	27550	63365

4.	सेरोफ्लो--250	404.7	353.91	280.64	73.27	15788	1156786.76
	सेरोफ्लो 250	404.7	353.91	280.64	73.27	29	2124.83
	सेरोफ्लो --250 मा.ग्रा.	404.7	353.91	280.64	73.27	3901	285826.27
	सेरोफ्लो --25+250 मा.ग्रा.	404.7	353.91	280.64	73.27	510	37367.7
5.	शेकल 500	3.5	3.06	2.08	0.98	4237	4152.26
	शेकल -500	3.5	3.06	2.08	0.98	11205	10980.9
	शेलक्ल--500	3.5	3.06	2.08	0.98	1032800	1012144
	शेलक्ल 500 मि.ग्रा.	3.5	3.06	2.08	0.98	1495	1465.1
	शेलक्ल 500 मि.ग्रा.	3.5	3.06	2.08	0.98	26800	26264
6.	ऑगमेंटीन 625	40.2	35.15	31.14	4.01	7773	31169.73
	ऑगमेंटीन --500+125मि.ग्रा.	40.2	35.15	31.14	4.01	2234	8958.34
	ऑगमेंटीन --625 मि.ग्रा.	40.2	35.15	31.14	4.01	31108	124743.08
	ऑगमेंटीन --625 मि.ग्रा.	40.2	35.15	31.14	4.01	16469	66040.69
	ऑगमेंटीन --625 मि.ग्रा. डीयूओ	40.2	35.15	31.14	4.01	1451	5818.51
	ऑगमेंटीन डीयूओ--500+125 मि.ग्रा.	40.2	35.15	31.14	4.01	2355	9443.55
	ऑगमेंटीन डीयूओ.625	40.2	35.15	31.14	4.01	1220	4892.2
	ऑगमेंटीन डीयूओ 625	40.2	35.15	31.14	4.01	1412	5662.12
7.	डाइनापार	71	62.09	38	24.09	74	1782.66
	डाइनापार मलहम --	71	62.09	38	24.09	3768	90771.12
	डाइनापार जेल-एन ए	71	62.09	38	24.09	41040	988653.6
	डाइनापार	71	62.09	38	24.09	1228	29582.52
						ए	5916918.67
वर्ष 2011-12							
1.	एलेक्स एस/एफ सिरप	43.6	38.13	27.6	10.53	2461	25914.33
	एलेक्स शूगा फ्री	43.6	38.13	27.6	10.53	4427	46616.31
	एलेक्स शूगर फ्री-	43.6	38.13	27.6	10.53	6108	64317.24
	एलेक्स शूगर फ्री—100 मि.लि.	43.6	38.13	27.6	10.53	7416	78090.48
	एलेक्स शूगर फ्री--100 मि.लि.	43.6	38.13	27.6	10.53	2392	25187.76

	एलेक्स -एस एफ - एन ए	43.6	38.13	27.6	10.53	3508	36939.24
2.	ऑगमेंटीन 625 मि.ग्रा.	43.92	38.41	26.6	11.81	3663	43260.03
	ऑगमेंटीन 625/	43.92	38.41	26.6	11.81	3998	47216.38
	ऑगमेंटीन 625	43.92	38.41	26.6	11.81	6598	77922.38
	ऑगमेंटीन डीयूओ.625	43.92	38.41	26.6	11.81	3639	42976.59
	ऑगमेंटीन डीयूओ --500+125 मि.ग्रा.	43.92	38.41	26.6	11.81	1169	13805.89
	ऑगमेंटीन --625 मि.ग्रा.	43.92	38.41	26.6	11.81	33180	391855.8
	ऑगमेंटीन --625 मि.ग्रा.	43.92	38.41	26.6	11.81	24502	289368.62
	ऑगमेंटीन --625 मि.ग्रा. डीयूओ	43.92	38.41	26.6	11.81	6791	80201.71
	ऑगमेंटीन --500+125 मि.ग्रा.	43.92	38.41	26.6	11.81	9456	111675.36
	ऑगुआमेन्टीन 625मि.ग्रा.	43.92	38.41	26.6	11.81	422	4983.82
	ऑगुआमेन्टीन डीयूओ 625	43.92	38.41	26.6	11.81	1828	21588.68
3.	बायो डी 3 प्लस	10.86	9.5	6.65	2.85	2135	6084.75
	बायो डी 3 प्लस टेबलेट्स	10.86	9.5	6.65	2.85	22865	65165.25
	बायो डी 3 प्लस --एन ए	10.86	9.5	6.65	2.85	191666	546248.1
4.	कायमोरल फोर्ट --	9.4	8.22	6.6	1.62	133731	216644.22
	कायमोरल फोर्ट टेबलेट्स	9.4	8.22	6.6	1.62	3031	4910.22
	कायमोरल फोर्ट--एन ए	9.4	8.22	6.6	1.62	17443	28257.66
5.	डाइजीन जेल	56	48.97	31.82	17.15	391	6705.65
	डाइजीन जेल --830+185+50+100 मि.ग्रा./10 मि.लि.	56	48.97	32.82	16.15	6547	105734.05
	डाइजीन जेल -एम --	56	48.97	33.82	15.15	727	11014.05
	डाइजीन जेन	56	48.97	34.82	14.15	483	6834.45
	डाइजीन -- एन ए	56	48.97	35.82	13.15	4735	62265.25
	डाइजीन सिरप	56	48.97	36.82	12.15	2753	33448.95
6.	डुओलीन---	210	183.65	143.8	39.85	4863	193790.55
	डुओलीन इनहेलर	210	183.65	143.8	39.85	95	3785.75
	डुओलीन इनहेलर--एन ए	210	183.65	143.8	39.85	130	5180.5
	डुओलीन --एन ए	210	183.65	143.8	39.85	38	1514.3

7.	डुओलीन रेस्प्यूले--एन ए	10.51	9.19	6.3	2.89	89645	259074.05
	डुओलीन	10.51	9.19	6.3	2.89	960	2774.4
	डुओलीन -- एन ए	10.51	9.19	6.3	2.89	34798	100566.22
	डुओलीन -- एन ए	10.51	9.19	6.3	2.89	14651	42341.39
	डुओलीन --.5	10.51	9.19	6.3	2.89	186736	539667.04
8.	फोराकोर्ट--200	276	241.36	183.3	58.06	6874	399104.44
9.	जेमकल केप्सूल्स	10.73	9.38	6.04	3.34	69691	232767.94
	जेमकल --0.25+500+7.5 मि.ग्रा.	10.73	9.38	6.04	3.34	176660	590044.4
	जेमकल --0 मि.ग्रा.	10.73	9.38	6.04	3.34	35758	119431.72
	जेमकल -500	10.73	9.38	6.04	3.34	1080	3607.2
	जेमकल --500	10.73	9.38	6.04	3.34	750841	2507808.94
	जेमकल --एन ए	10.73	9.38	6.04	3.34	92468	308843.12
10.	गेमेर 1 (1+500)	4.7	4.11	2.89	1.22	56620	69076.4
	गेमेर 1--एन ए	4.7	4.11	2.89	1.22	48051	58622.22
	गेमेर--1+500 मि.ग्रा.	4.7	4.11	2.89	1.22	20579	25106.38
11.	गेमेर 2 (2+500)	7	6.12	4.6	1.52	178153	270792.56
	गेमेर 2--एन ए	7	6.12	4.6	1.52	110407	167818.64
	गेमेर--2+500 मि.ग्रा.	7	6.12	4.6	1.52	63805	96983.6
12.	ग्लीजड एम --80 मि.ग्रा.	6.6	5.77	3.74	2.03	7425	15072.75
	ग्लीजड एम --80+500 मि.ग्रा.	6.6	5.77	3.74	2.03	55430	112522.9
	ग्लीजड एम -- एन ए	6.6	5.77	3.74	2.03	164287	333502.61
13.	ग्रीलीक्टस	53.25	46.57	29.3	17.27	235	4058.45
	ग्रीलींकट्स -- एन ए	53.25	46.57	29.3	17.27	1223	21121.21
	ग्रीलींकट्स	53.25	46.57	29.3	17.27	3962	68423.74
	ग्रीलींकट्स	53.25	46.57	29.3	17.27	327	5647.29
	ग्रीलींकट्स --एन ए	53.25	46.57	29.3	17.27	684	11812.68
	ग्रीलींकट्स -- एन ए	53.25	46.57	29.3	17.27	2896	50013.92
	ग्रीलींकट्स 100 मि.लि.	53.25	46.57	29.3	17.27	7046	121684.42
	ग्रीलींकट्स प्लेन	53.25	46.57	29.3	17.27	2463	42536.01

14.	ग्रीलींकट्स एक्सपेक्टोरेन्ट	53.25	46.57	29.3	17.27	506	8738.62
15.	ग्रीलींकट्स बी एम	42	36.73	11.59	25.14	1562	39268.68
16.	ग्रीलींकट्स बी एम --00	42	36.73	11.59	25.14	10221	256955.94
	ग्रीलींकट्स बी एम -- एन ए	42	36.73	11.59	25.14	2984	75017.76
	ग्रीलींकट्स बी एम -- एन ए	42	36.73	11.59	25.14	2593	65188.02
	ग्रीलींकट्स बी एम	42	36.73	11.59	25.14	2478	62296.92
	ग्रीलींकटिस बी एम	42	36.73	11.59	25.14	3016	75822.24
17.	लोसर एच 50 मि.ग्रा.	5.95	5.2	3.9	1.3	11227	14595.1
	लोसर एच -- एन ए	5.95	5.2	3.9	1.3	49941	64923.3
	लोसर एच --50+12.5 मि.ग्रा.	5.95	5.2	3.9	1.3	19617	25502.1
18.	मोक्सक्लेव--625 मि.ग्रा.	42	36.73	24.15	12.58	6261	78763.38
	मोक्सक्लेव 625/	42	36.73	24.15	12.58	3124	39299.92
	मोक्सक्लेव --500+125 मि.ग्रा.	42	36.73	24.15	12.58	455	5723.9
19.	रोलसिकल प्लस--0.25+500 मि.ग्रा.	10.5	9.18	6.2	2.98	99298	295908.04
	सेरेटाइड 500 एक्यूहेलर	1130	988.19	753.23	234.96	935	219687.6
21.	सेरोफ्लो--250	404.7	353.91	283.4	70.51	5899	415938.49
22.	शेलकल 500 मि.ग्रा.	3.8	3.32	2.08	1.24	386435	479179.4
	शेलकल 500 मि.ग्रा. टेबलेट	3.8	3.32	2.08	1.24	63680	78963.2
	शेलकल --500	3.8	3.32	2.08	1.24	4162176	5161098.24
23.	शेलकल एम --एन	4.13	3.61	2.2	1.41	166437	234676.17
	शेलकल एम	4.13	3.61	2.2	1.41	76680	108118.8
24.	जी डैक्स सिरप	57.5	50.28	29.77	20.51	8802	180529.02
						बी	**17266525.8**
						योग ए +बी	**23183444.47**

अनुबंध-10

(पैरा 6.3.12 के संदर्भ में)

के.स्वा.से.यो. के जीवन रक्षक दवाईयों की सूची में समान दवाओं के विभिन्न ब्रांडो के दरों की तुलना

(राशि ₹ में)

दवा का जेनेरिक नाम	सूची में ऊँची कीमत वाले ब्रांड	सूची में कम कीमत वाले ब्रांड	निर्माता का नाम	सूची में ऊँची कीमत वाले ब्रांड का मूल्य	सूची में कम कीमत वाले ब्रांड का मूल्य	मूल्य में अंतर	2011-12 के दौरान ऊँची कीमत वाले ब्रांड की उपलब्धता	अतिरिक्त किए गए खर्च
एनास्ट्राजोल	एरीमिडेक्स 1 मि.ग्रा		एस्टा जेनका	373.94		331.26	56588	18745381.3
		एल्ट्राज 1 मि.ग्रा.	एल्केम		42.68			
डोक्सोरूबिसिन एच.सी.एल लिपोसामाल	केलीक्स 20 मि.ग्रा.		जॉनसन एवं जॉनसन	39541.6		32716.6	156	5103789.6
		न्यूडोक्सा 20	जाइडस		6825			
एक्सेमेसटेन 25 मि.ग्रा.	एरोमासीन 25 मि.ग्रा.		फीजर	230.16		197.91	10410	2060243.1
		एक्सटेने 25 मि.ग्रा	नाटको		32.25			
फलबेक्सटेरेण्ट 250	फास्लोडेक्स 250		आस्ट्राजेनका	20458.2		7708.2	156	1202479.2
		फलवन 250 मि.ग्रा.	नाटको		12750			
आइबैंड्रोनिक एसिड 50 मि.ग्रा.	बॉन्ड्रोनेट 50 मि.ग्रा.		रोके	400.05		359.1	4228	1518274.8
		बेन्ड्रोन 50 मि.ग्रा.	नाटको		40.95			

आइबैंड्रोनिक एसिड 6 मि.ग्रा.	बॉन्ड्रोनेट 6 मि.ग्रा.		रोके	8749.65		6678.15	97	647780.55
		बेन्ड्रोन 6 मि.ग्रा.	नाटको		2071.5			
इरिनोटेकन 100 मि.ग्रा.	कॉम्पटो 100		पी फाइजर	14976		14776.5	136	2009604
		नेक्सीरॉन 100	जाइडस		199.5			
लेट्रोजोले 2.5 मि.ग्रा.	फेमारा 2.5		नोवार्टिस	171.15		143.85	16805	2417399.25
		लेट्रोज 2.5 मि.ग्रा. (टेंब्लेट)	एल्केम		27.3			
माइकोफेनोलेट मोफेटिल 500	माइकोफिट 500 (टेबलेट)		इंटस बायोफार्मा	80.955		24.955	9520	237571.6
		मोफिलेट 500 मि.ग्रा.	जेनोवा		56			
माइकोफेनोलेट मोफेटिल एस 360	माइकोफिट एस 360 (टेबलेट)		इंटस बायोफार्मा	71.085		15.085	20180	304415.3
		मोफिलेट एस 360 मि.ग्रा.	जेनोवा		56			
ओक्सालिपेटिन 100 मि.ग्रा.	डेकोटिन 100 मि.ग्रा		डॉ रेड्डीज	8070.27		3439.77	363	1248636.51
		आक्सीडेक 100	रेनबेक्सी		4630.5			
ओक्सालिपेटि 50 मि.ग्रा.	डेकोटिन 50 मि.ग्रा.		डॉ. रेड्डीज	4024.64		1871.16	248	464047.68
		आक्सीडेक 50	रेनबेक्सी		2153.48			
पेक्लिटेक्सेल 100 100 मि.ग्रा.	टेक्सोल 100		ब्रिस्टोल मेयरसक्विब	4918.03		1617.74	242	391493.08
		माइटोटेक्स 100	डॉ. रेड्डीज		3300.29			

पेक्लिटेक्सेल 100 30 मि.ग्रा.	टेक्सोल 30		ब्रिस्टोल मेयरसक्विब	2039.1		634.33	223	141455.59
		माइटोटेक्स 30	डॉ रेड्डीज		1404.77			
एल्बूमिन बाउण्ड पेक्लिटेक्सेल	एब्राक्सेन 100 (वायल)		बायोकम	14608.7		5320.26	576	3064469.76
		एल्बूयेक्स 100 (वायल)	नाटको		9288.44			
बोर्टेजोमिब 3.5 मि.ग्रा.	वेल्केड 3.5 मि.ग्रा.		जॉनसन एवं जॉनसन	49987.27		36757.27	81	2977338.87
		बोरटेनेट 3.5 मि.ग्रा.	नाटको		13230			
कार्बोप्लेटिन 150 मि.ग्रा.	पारा प्लाटीन 150		ब्रिस्टोल मेयरसक्विब	2030		770	352	271040
		बायोकार्ब 150	बायोकेम		1260			
डोकेटाक्सेल 80 मि.ग्रा.	टेक्सोटेरे 80		सेनाफि एवेन्टिस	13569.23		6300	479	3017700
		डोकेनेट 80	नाटको		7269.23			
एपिरूबिसिन एच.सी.एल. 50 मि.ग्रा.	फार्मोरूबिसिन 50		फीजर	2646.84		1001.16	223	223258.68
		रूबिजेन 50	रेनबेक्सी		1645.68			
एरिथ्रोपोइटिन 4000 आई.यू.	एप्रेक्स 4000		जॉनसन एवं जॉनसन	1365		756	13214	9989784
		न्यूरेकोरमोन 4000	रोके		609			
एरिथ्रोपोइटिन 40000 आई.यू.	एप्रेक्स 40000		जॉनसन एवं जॉनसन	10584		2835	1089	3087315
		एपोफेर 40000	रोके		7749			
कुल योग								**59123478***

*** समान मामलों के अतिरिक्त, केरल और कोलकाता में ₹ 9.50 लाख और ₹ 25.42 लाख मूल्य क्रमशः पाया गया।**

अनुबंध-11

(पैराग्राफ सं. 7.1 के संदर्भ में)

लागत वृद्धि का विवरण

- नवम्बर 2006 तक तथा मार्च 2007 के बीच निर्मित 48 क्वार्टरों (टाईप-II) की निर्माण लागत:

सिविल कार्य = ₹ 2,72,11,884	**इलेक्ट्रीकल कार्य = ₹ 14,53,555**	**योग= ₹ 2,86,65,439**
1 क्वार्टर (टाईप-II) की निर्माण लागत = 2,86,65,439 ÷ 48 = ₹ 5,97,196 (क)		

- अक्तूबर 2009 को के.लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत 'संशोधित अनुमानों' के अनुसार 108 क्वार्टरों (टाईप-II) की निर्माण लागत:

सिविल कार्य = ₹ 10,45,60,993	**इलेक्ट्रीकल कार्य = ₹ 1,18,55,129**	**योग = ₹ 11,64,16,122**
1 क्वार्टर की निर्माण लागत = 11,64,16,122 ÷ 108 = 10,77,927 (ख)		

दर के अन्तर की लागत = **(ख)** - **(क)** = 10,77,927 – 5,97,196 = ₹ 4,80,731

108 टाईप-II क्वार्टरों के संबंध में लागत वृद्धि = 108 X 480731 = ₹ 5,19,18,948

अनुबंध - 12

(पैराग्राफ सं.10.1 के संदर्भ में)

भारतीय समुदाय कल्याण योजना के अंतर्गत निधि का उपयोग

मिशन	देश	भा.स.क.नि.		
		प्रारंभ तिथि	व्यय (₹)	31.03.2012 को शेष (₹)
ई.आई. मॉस्को	रूस	13-फरवरी -12	0	894163
एच.सी.आई. लंदन	यू.के.	14-मार्च -11	607488	78260903
ई.आई. पेरिस	फ्रांस	01-दिसम्बर -10	2788791	30822381
पी.एम.आई. जिनेवा	स्विजरलैण्ड	0	0	0
ई.आई. रोम	इटली	जनवरी-11	1424378	7119771
ई.आई. ब्रसैल्स	बैल्जियम	01-मई -11	353485	6448801
ई.आई. बर्लिन	जर्मनी	01-अप्रैल -11	40724	5025382
ई.आई. द हेग	नीदरलैण्ड	01-सितम्बर -10	25181	17960152
ई.आई. मैड्रिड	स्पेन	11-अप्रैल -11	399146	12154031
ई.आई. बर्ने	स्विजरलैण्ड	0	0	0
ई.आई. वियेना	ऑस्ट्रीया	0	0	0
सी.जी.आई. फ्रैंकफर्ट	जर्मनी	01-अप्रैल -11	116657	7966582
ई.आई. स्टोकहोम	स्वीडन	01-अक्तूबर -11	0	1731306
सी.जी.आई. म्यूनिक	जर्मनी	01-अप्रैल -11	546917	8693010
सी.जी.आई. बर्मिंघम	यू.के.	14- मार्च -11	276070	28791564
ई.आई. कोपेहेगन	डैनमार्क	01-अगस्त-11	0	2856587
ई.आई. एथेंस	ग्रीस	16-अगस्त -11	0	1195332
ई.आई. प्राग	चेक रिप.	01- दिसम्बर-11	0	477478
ई.आई. ओस्लो	नॉर्वे	19- जनवरी -12	0	573584
ई.आई. बुडापेस्ट	हंगरी	0	0	0
ई.आई. डबलिन	आयरलैण्ड	0	0	0
ई.आई. लिस्पन	पुर्तगाल	17-मई -10	102194	3279399
सी.जी.आई. मिलन	इटली	01-अप्रैल -11	291535	17097568
ई.आई. बुचारेस्ट	रोमानिया	09- मई -11	718873	495020
ई.आई. हेलसिंकी	फिनलैण्ड	0	0	0
ई.आई. ब्रटिसलवा	स्लोवाक रिप.	11-अप्रैल -11	0	466575

ई.आई. वर्षो	पोलैण्ड	0	0	0
ई.आई. जब्लजन	स्लोविनिया	0	0	0
ई.आई. जगरेब	क्रोएशिया	0	0	0
सी.जी.आई. ईदिनबुर्ग	यू.के.	14- मार्च -11	0	2638525
ई.आई. सोपिया	बुलगारिया	0	0	0
ई.आई. बेलग्रेद	यूगोस्लाविया	18-अप्रैल -11	0	169259
ई.आई., रेक्जविक	आईसलैण्ड	08-अप्रैल -11	0	107736
सी.जी.आई. हमबर्ग	जर्मनी	01-अप्रैल -11	4034	3825081
ई.आई. मिंस्क	बेलारूस	01-अक्तूबर -11	0	388439
सी.जी.आई. सैन्ट पीटर्सवर्ग	रूस	0	0	0
सी.जी.आई. व्लादिवोस्टोक	रूस	27- जनवरी -12	0	20,933
सी.जी.आई. सैन्ट डेनिस, रूनियन	फ्रांस	0	0	0
कुल			**7695473**	**239459562**

अनुबंध - 13

(पैराग्राफ सं.14.9 के संदर्भ में)

वातानुकूलित बसों के गैर/स्थानीय परिचालन के कारण राजस्व की हानि

क्र.सं.	चेसिस सं.	बस सं.	निमार्ण के पश्चात बस की प्राप्ति की तिथि	प्रपत्र 20 के अनुसार पास करने की तिथि	स्टेशन से बाहर के रूटों पर परिचालन की तिथि	स्टेशन से बाहर के रूटों पर परिचालन के दिनों की संख्या	स्टेशन से बाहर के रूट से प्राप्ति	पुनः परिचालन में नही रहने वाले दिनों की संख्या	स्थानीय रूट पर परिचालन की तिथि	स्थानीय परिचालन के दौरान तय की गई प्रभावी दूरी (कि.मी.)	स्थानीय रूट से प्राप्ति (राशि ₹ में)	अर्द्ध शहरी रूट पर परिचालन की तिथि	पास करने के पश्चात बसों का सेवा में नहीं रहने के लिए अवधि (दिवस)	स्थानीय रूट पर परिचालित बसों के लिए अवधि (दिनों में)	स्थानीय रूट पर परिचालित/ गैर परिचालित बसों के लिए कुल अवधि (दिवस)
1	1412	सीएच01जी17566	1/8/2011	1/25/2011	02-04-11 से 4-04-11	3	4304	7	4/12/2011	421	6533	4/29/2011	66	17	83
2	1422	सीएच01जी17565	1/12/2011	1/25/2011					4/8/2011	775	9281	4/30/2011	72	22	94
3	1472	सीएच01जी17567	1/12/2011	1/25/2011					4/8/2011	712	12925	4/28/2011	72	20	92
4	1421	सीएच01जी17564	1/14/2011	1/25/2011					4/7/2011	467	5415	5/4/2011	71	27	98
5	1489	सीएच01जी17568	1/15/2011	1/25/2011	3-04-11 से 4-04-11	2	3230	2	4/7/2011	718	10993	4/29/2011	67	22	89
6	1491	सीएच01जी17569	1/17/2011	1/25/2011	4/5/2011	1	2494	3	4/9/2011	671	7324	4/28/2011	66	19	85
7	1418	सीएच 01जीए 5308	1/18/2011	2/3/2011					4/5/2011	919	13210	5/4/2011	60	29	89
8	1465	सीएच 01जीए 5309	1/28/2011	3/1/2011					4/5/2011	953	14511	4/28/2011	34	23	57
9	1467	सीएच 01जीए 5311	1/31/2011	3/1/2011					4/5/2011	678	6698	4/29/2011	34	24	58
10	1494	सीएच 01जीए 5313	1/31/2011	3/1/2011					4/6/2011	377	4764	5/2/2011	35	26	61
11	1495	सीएच 01जीए 5314	2/2/2011	3/1/2011					4/7/2011	1321	22538	4/29/2011	36	22	58
12	1468	सीएच 01जीए 5312	2/7/2011	3/1/2011					4/10/2011	360	3096	4/29/2011	39	19	58
13	1490	सीएच 01जीए 5306	1/28/2011	3/1/2011								5/7/2011	66		66

14	1492	सीएच 01जीए 5301	1/31/2011	3/1/2011								5/7/2011	66		66
15	1471	सीएच 01जीए 5310	2/8/2011	3/1/2011					4/5/2011	1249	16689	4/29/2011	34	24	58
16	1466	सीएच 01जीए 5307	2/14/2011	3/1/2011								5/7/2011	66		66
17	1420	सीएच 01जीए 5304	2/14/2011	3/1/2011								5/7/2011	66		66
18	1496	सीएच 01जीए 5302	2/17/2011	3/3/2011								5/6/2011	63		63
19	1419	सीएच 01जीए 5303	2/19/2011	3/3/2011								5/7/2011	64		64
20	1493	सीएच 01जीए 5305	2/25/2011	3/8/2011								5/6/2011	58		58
	कुल					**6**	**10028**	**12**		**9621**	**133977**		**1135**	**294**	**1429**

(राशि में ₹)

डिपो सं. 1 के सबंध में जनवरी 2011 से मई 2011 के दौरान प्रति बस दिवस औसत राजस्व (-) प्रति बस दिवस औसत परिवर्तनशील मूल्य के आधार पर हानि

गैर परिचालन के कारण 7 बसों के संबंध में हानि	449*4337		1947313
गैर परिचालन के कारण 13 बसों के संबंध में हानि	686*4337		2975182
			4922495
13 लम्बे रूटों पर बसों के परिचालन के कारण राजस्व की हानि	294*4337	1275076	
घटाएं: स्थानीय रूट का योगदान (डिपो सं. 4 के संबंध में जनवरी 2011 से मई 2011 के दौरान प्रति बस दिवस औसत राजस्व (-) प्रति बस दिवस औसत परिर्वतनशील मूल्य	294*1023	300762	
बसों के गैर परिचालन/स्थानीय मार्गों पर बसों के परिचालन के कारण शुद्ध हानि			974314
कुल हानि			**5896809**

टिप्पणी: डिपो 1 लम्बे रूट पर बसों का परिचालन करता है।

डिपो 4 स्थानीय रूट पर बसों का परिचालन करता है।

अनुबंध - 14

(पैराग्राफ सं. 14.10 के संदर्भ में)

खजाने में वाहन के पंजीकरण शुल्क/ड्राइवर लाइसेंस शुल्क को जमा न करना

क्र.स.	काउंटर कैशियर का नाम पंजीकरण शुल्क	संग्रहित राशि	संग्रहित करने की तिथि	दैनिक बही/रोकड़ बही में दर्ज तथा खजाने में जमा की गई राशि
1.	विनोद	58320/-	21/09/2010	शून्य
2.	विनोद	4760/-	25/10/2010	शून्य
3.	राजपाल	11200/-	01/11/2010	शून्य
4.	राजपाल	8000/-	03/11/2010	शून्य
5.	राजपाल	1600/-	18/11/2010	शून्य
6.	संजीव	71850/-	20/11/2010	शून्य
7.	राजपाल	16170/-	23/11/2010	शून्य
8.	अनिल राठी	147200/-	24/11/2010	शून्य
9.	विनोद	188370/-	25/11/2010	शून्य
10.	नीरू	12600/-	25/11/2010	शून्य
11.	विनोद	3400/-	10/12/2010	शून्य
12.	नरेन्द्र	10730/-	11/12/2010	शून्य
13.	संजय	21560/-	11/12/2010	शून्य
14.	प्रवीन	116320/-	20/12/2010	शून्य
15.	संजीव	153890/-	22/12/2010	शून्य
16.	प्रवीन	132890/-	23/12/2010	शून्य
17.	प्रवीन	134610/-	24/12/2010	शून्य
18.	प्रवीन	152490/-	27/12/2010	शून्य
19.	संजीव	184130/-	28/12/2010	शून्य

20.	संजीव	172560/-	29/12/2010	शून्य
21.	सुमित	170320/-	29/12/2010	शून्य
22.	संजीव	49500/-	30/12/2010	शून्य
23.	अंजू	5120/-	31/12/2010	शून्य
24.	संजीव	296620/-	31/12/2010	शून्य
25.	सुमित	60880/-	08/01/2011	शून्य
26.	नीरू	72500/-	25/01/2011	शून्य
27.	अनिता	81265/-	29/01/2011	शून्य
28.	विनोद	2850/-	04/02/2011	शून्य
	कुल (अ)	**2341705/-**		
	ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क			
1.	रजनी	22860/-	20/12/2010	शून्य
2.	अल्का	26485/-	18/03/2011	शून्य
	कुल (ब)	**49345/-**		
	कुल अ एवं ब	**2391050/-**		

अनुबंध - 15

(पैराग्राफ सं. 14.10 के संदर्भ में)

आंशिक रूप से जमा किया गया वाहन पंजीकरण शुल्क

क्र.स.	काउंटर कैशियर का नाम पंजीकरण शुल्क	संग्रहित राशि	संग्रहित करने की तिथि	दैनिक बही/रोकड़ बही में दर्ज तथा खजाने में जमा की गई राशि	दैनिक बही/रोकड़ बही में नहीं दर्ज तथा खजाने में जमा नहीं की गई राशि
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6. (4-5)**
1.	संजीव	26/5/2010	126576/-	123626/- दैनिक बही में दर्ज 27/5/2010 को	2950/-
2.	अनिल राठी	09/08/2010	75770/-	73160/- दैनिक बही में दर्ज 10/8/2010 को	2610/-
3.	संजय	30/08/2010	857350/-	856170/-	1180/-
4.	संजय	08/09/2010	45875/-	40580/-	5295/-
5.	नरेन्द्र	20/10/2010	39920/-	37410/-	2510/-
6.	नरेन्द्र	07/01/2011	34750/-	32150/-	2600/-
7.	संजय	31/01/2011	150160/-	15060/-	135100/-
8.	विनोद	11/02/2011	20340/-	11800/-	8540/-
9.	नरेन्द्र	25/03/2011	240379/-	224229/-	16150/-
कुल			**1591120/-**	**1414185/-**	**176935/-**

अनुबंध - 16

(पैराग्राफ सं. 14.11 के संदर्भ में)

बकाया परिनियोजन प्रभारों का विवरण

क्र.सं.	आयोजक एजेंसी	मांग पत्र सं. एवं तिथि	मांग सं. एवं तिथि	अवधि	राशि (₹)
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंजाब क्रिकेट संघ, मोहाली	पी.सी.ए. -2009/0981 दिनांक 04/11/2009	डी.15573/वि./अनु./सं.शा.क्षे. दिनांक 31/3/11	25/3/2011 से 31/3/2011	1,60,68,600
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंजाब क्रिकेट संघ, मोहाली	पी.सी.ए.-2009/0981 दिनांक 04/11/2009	डी.15575/वि. /अनु. /सं.शा.क्षे. दिनांक 31/3/11	28/2/11 to 12/3/2011	2,65,35,200
3.	महाप्रबंधक प्रचालन, किंग्स XI पंजाब	0009/2010 दिनांक 21/02/2010	डी.-701/वि./अनु./सं.शा.क्षे. दिनांक 11/3/2010	1/03/2010 से 10/04/2010	47,44,732
4.	महाप्रबंधक प्रचालन, किंग्स XI पंजाब	डी. -01/वि. /अनु. /सं.शा.क्षे. दिनांक 11/3/2010	डी.-11266/वि./अनु./सं.शा.क्षे. दिनांक 31/3/2010	15/03/2010 से 10/04/2010	9,58,156
5.	महाप्रबंधक प्रचालन, किंग्स XI पंजाब	शून्य	20049/वि./अनु./सं.शा.क्षे. दिनांक 9/5/2011	01/05/2011 से 11/05/2011	1,12,24,800
6.	महाप्रबंधक प्रचालन, किंग्स XI पंजाब	शून्य	20045/वि./अनु./सं.शा.क्षे. दिनांक 9/5/2011	03/4/2011 से 16/04/2011	1,00,60,600
7.	महाप्रबंधक प्रचालन, किंग्स XI पंजाब	शून्य	20047/वि./अनु./सं.शा.क्षे. दिनांक 9/5/2011	17/04/2011 से 22/04/2011	76,17,600
8.	महाप्रबंधक प्रचालन, किंग्स XI पंजाब	शून्य	38210/वि./अनु./सं.शा.क्षे. दिनांक 18/7/2012	28/03/2012 से 14/05/2012	1,20,36,600
कुल					**8,92,46,288**

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ सं. 17.1 के संदर्भ में)

मार्च 2013 को, मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तक विभिन्न मंत्रालय/विभागों से प्रतिक्षित कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च में समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल		
			बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
1.	कृषि	2010	1	-	1
2.	रसायन एवं उर्वरक	2010	1	-	1
3.	नागरिक उड्डयन	2009	2	1	1
		2011	1	1	-
4.	वाणिज्य एवं उद्योग	2008	1	-	1
		2009	1	-	1
5.	कम्पनी मामले	2010	3	2	1
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण	2011	1	-	1
7.	संस्कृति	2003	1	-	1
		2004	1	-	1
		2006	2	2	-
		2007	2	-	2
		2008	1	1	-
8.	कार्मिक नियोजन एवं शिकायतें	2011	1	1	-
9.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	2011	1	-	1
10.	विदेश मामले	2006	4	-	4
		2007	1	-	1
		2008	1	-	1
		2009	6	2	4
		2010	8	7	1

	2011	6	6	-
11. वित्त	2012	1	1	-
12. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2000	2	-	2
	2005	1	-	1
	2007	1	-	1
	2008	2	-	2
	2009	3	1	2
	2010	5	-	5
13. गृह मामले	2010	1	-	1
	2011	4	2	2
गृह मामले (संघ शासित क्षेत्र)	2007	1	-	1
	2008	1	-	1
	2010	1	-	1
	2011	3	2	1
14. मानव संसाधन विकास	2011	1	1	-
15. सूचना एवं प्रसारण	2000	1	-	1
	2011	1	1	-
16. विधि एवं न्याय	2003	1	1	-
17. खनन	1998	1	-	1
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	2008	1	-	1
	2010	1	-	1
18. ग्रामीण विकास	2002	1	1	-
	2007	1	-	1
	2009	1	-	1
	2010	1	1	
19. पोत-परिवहन	2009	1	1	-
	2011	3	3	-
20. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1996	1	-	1
	2003	1	-	1
	2006	1	-	1

	2010	1	-	1
21. कपड़ा	2003	1	-	1
	2007	1	-	1
	2009	3	-	3
22. जनजातीय मामले	1998	1	-	1
	2006	1	1	-
23. शहरी विकास	2009	1	-	1
	2011	1	1	-
24. जल संसाधन	2008	-	-	-
25. महिला एवं बाल विकास	1999	1	-	1
	2003	1	-	1
	2010	1	-	1
	2011	2	2	-
26. युवा मामले एवं खेल	2011	2	1	1
योग		**107**	**43**	**64**

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ सं. 17.2 के संदर्भ में)

ड्राफ्ट पैराग्राफ के संदर्भ में मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

क्र.स.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की कुल संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनके संदर्भ में उत्तर प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफों के संदर्भ
1.	कृषि	3	1	2.2
2.	नागरिक उड्डयन	1	-	-
3.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	-	-
4.	विदेश मामले	1	1	5.1
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4	2	6.1, 6.3
6.	गृह मामले	2	-	-
7.	मानव संसाधन विकास	2	1	8.1
8.	खनन	1	1	9.1
9.	समुद्रपारीय भारतीय मामले	1	1	10.1
10.	पोत-परिवहन	1	1	11.1
11.	कपड़ा	1	1	12.1
12.	पर्यटन	1	-	-
13.	संघ शासित क्षेत्र	12	8	14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.9, 14.10, 14.11 और 14.12
14.	महिला एवं बाल विकास	1	-	-
15.	युवा मामले एवं खेल	1	1	16.1
	योग	**33**	**18**	**-**